

The House reassembled after lunch at two of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair*

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: Motion of Thanks on the President's Address. Shri Ravi Shankar Prasad.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I move that an Address be presented to the President in the following terms:—

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2017."

सर, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रपति जी के दोनों सदनों के अभिभाषण पर मुझे इस सदन में अपने विचार रखने का अवसर मिला है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी भारतीय संसद की परम्परा के मर्मज्ञ हैं और उनको भारतीय राजनीति का अनुभव भी है। अपनी इस लम्बी यात्रा में उन्होंने भारत के विकास की यात्रा को भी देखा है। आज बजट सत्र के उद्घाटन के अवसर पर, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्होंने जो अपने उद्गार प्रकट किए हैं, वे देश के बदलाव का संकेत हैं।

माननीय सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। एक, महान सिख संत, गुरुगोबिंद सिंह जी के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसे हम लोगों ने अभी 'प्रकाश उत्सव' के रूप में मनाया। स्वयं प्रधान मंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए पटना गए थे। दूसरा, देश के महान संत, रामानुजाचार्य जी के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही चम्पारण सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने सत्याग्रह के आंदोलन को पहली बार मूर्त रूप दिया था, उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थल पटना, बिहार है, जो मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। चम्पारण भी बिहार में ही है, इसलिए यह मेरे लिए भावनात्मक लगाव का विषय है। साथ ही विचारक और हम सभी के प्रखर नेता, दीनदयाल उपाध्याय जी के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिन्होंने 'अंत्योदय' की कल्पना दी थी और जिसके आधार पर सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक और महत्वपूर्ण बात जनशक्ति से विकास की यात्रा, *the road to development through peoples' involvement* के बारे में कही है। जन-शक्ति ही राष्ट्र-शक्ति है, *peoples' power, nation's power*. If that involvement comes about, the development becomes extraordinary and dedicated.

[Shri Ravi Shankar Prasad]

माननीय सभापति जी, प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में यह सरकार बदलाव की सरकार है और इस बदलाव में, उनकी अगुवाई में हमारे दो सिद्धान्त हैं "सब का साथ, सब का विकास" एवं "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" और इस बड़ी परिकल्पना में, जिसमें सबको लेकर चलना है, इसमें जनता किस प्रकार से सहभागी बने, इस बारे में मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा कि यह देश कैसे बदलता है।

महोदय, मैं सदन के अपने उद्बोधन में एक वाक्य कहना चाहूंगा - देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए और अगर जगाने वाला महत्वपूर्ण नेता बनता है, तो देश कैसे जागता है, वह मैं बताना चाहता हूँ। दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को यूएन को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि *Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body. By changing our life style and creating consciousness, it can help in well being.* और बाद में अपील की थी कि *let us work towards adopting an International Yoga Day.* आपने स्वयं भी देखा होगा दिनांक 21 जून, 2015 को पहला 'इंटरनेशनल योगा डे' मनाया गया था। स्वयं प्रधान मंत्री जी दिल्ली के राजपथ पर हजारों लोगों के साथ योग कर रहे थे। हम सभी लोग कर रहे थे। देश की जनता आई। पहले साल 84 देशों में और दूसरे साल 173 देशों में योगा डे मनाया गया और बाद में 171 कंट्रीज ने, आप तो स्वयं यूएन की कार्यवाही से परिचित रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में योगा डे को पूरी दुनिया ने एक प्रकार से आशीर्वाद दिया और Wall Street Journal ने कहा कि *Yoga takes over the world.* इसलिए यदि जनशक्ति की शक्ति लगती है, तो एक योजना किस तरह से सर्वव्यापी बनती है, योगा डे की सफलता उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी अगुआई में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनशक्ति का उपयोग किया।

महोदय, "स्वच्छ भारत अभियान", देश को साफ होना चाहिए, स्वयं महात्मा गांधी जी की एक बहुत बड़ी कहावत है और उन्होंने इसे माना भी था, लेकिन अगर देश को जगाना है, तो बोलने से काम नहीं चलेगा। वह हम सभी के लिए बहुत भावुक क्षण था जब स्वयं प्रधान मंत्री जी झाड़ू लेकर दिल्ली की सड़कों पर सफाई करने के लिए उतरे। "स्वच्छ भारत अभियान" की माननीय राष्ट्रपति जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग फील्ड में थे और लोग, महिलाएं और बच्चे अपने आप सड़कों पर निकल रहे थे।

सभापति जी, MyGov हमारा एक कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश के 40 लाख लोग डिजिटली इन्वॉल्व होते हैं। हमने उनसे कहा था कि आप "स्वच्छ भारत अभियान" का लोगो बनाओ, क्राउड सोर्सिंग और उन्होंने गांधी जी का चश्मा बनाकर दिया गांधी जी का विचार, उनका चश्मा, स्वच्छ भारत का अभियान-यह है जनशक्ति के माध्यम से भारत का बदलाव।

माननीय सभापति जी, शौचालय बनने चाहिए। अब मात्र ढाई वर्षों में 1,04,000 गांव, 450 शहर, 77 जिले और तीन राज्यों ने डिक्लेयर किया कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। अब यह कितनी बड़ी बात है। लगभग तीन करोड़ शौचालय बने हैं और जब जनान्दोलन बनता है, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक सरकारी कार्यक्रम में मैं इंदौर गया था। मैं आपके माध्यम से यह बात सदन को बताना चाहता हूँ। वहां एक गांव मुराद है। वहां की सरपंच ने अपने पूरे गांव को ओपन

डेफिकेशन फ्री किया है, यानी खुले में शौच से मुक्त। उसका बहुत आग्रह था कि मैं उसके गांव में जाऊँ। मैं वहां गया और वहां उन्होंने किस तरह से यूनिक कार्यक्रम किया कि उसने बच्चों की एक वानर सेना बनाई थी, जिसके सदस्य सुबह चार बजे से गांव में घूमते थे और कोई खुले में शौच करता था, तो उसे रोकते थे और कहते थे कि अपने घर में शौचालय बनाओ क्योंकि मोदी सरकार शौचालय के लिए प्रेरणा दे रही है। यह जो पूरा आन्दोलन बना है, तो आज लगभग तीन करोड़ शौचालय इस देश में बने हैं। माननीय सभापति जी, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि शौचालय नहीं बनने से प्राइवेट में परेशानी होती है, महिलाओं को रोग होता है, इसलिए इसको बहुत ही आगे बढ़ाना जरूरी है।

सर, जनान्दोलन से जुड़ा दूसरा कार्यक्रम देखिए: 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। अब इसकी बात तो हम सभी करते थे। मुझे याद है कि करनाल के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वहाँ मैं भी गया था और उसमें हमारे कई मंत्री भी उपस्थित थे। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी: "अगर बेटी नहीं बचाओगे, तो बहू कहाँ से लाओगे?" अब इसके पीछे इतनी बड़ी सोच थी कि जो हरियाणा में सेक्स रेश्यो का एक बहुत imbalance रहा है, आज देखिए कि एक-डेढ़ साल के अन्दर वह imbalance बराबर हो गया। तो प्रधानमंत्री जी यह संकल्प के साथ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को लीड करते हैं।

एक योजना 'सुकन्या समृद्धि योजना' है। मैं उस विभाग को पहले हैंडल करता था। अभी तक 94 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खुल चुके हैं, जिनमें 7,600 करोड़ रुपये बेटियों की सुरक्षा के लिए जमा हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कल अपने बजट भाषण में इस पूरे आन्दोलन की बहुत तारीफ की थी, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का है।

माननीय सभापति जी, एक बात देखिए कि अगर यह आन्दोलन बनता है, तो उसके क्या संकेत जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी 26 जनवरी, 2015 को आए थे। 26 जनवरी की परेड चलती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह विचार हुआ कि 26 जनवरी की परेड में हमारी महिला सेना की पूरी टुकड़ी एक कैप्टन की अगुआई में लीड करेगी। उससे एक मैसेज जाता है। जब ओबामा जी राष्ट्रपति भवन आए थे, तो उनकी अगुवानी करने के लिए हमारे एयर फोर्स की एक महिला स्क्वाड्रन लीडर खड़ी थी। इससे यह संकेत जाता है कि जब यह एक आन्दोलन बनता है, तो आप देखिए कि खेल में भी, इस बार के ओलम्पिक में, चाहे वह पी.वी. सिंधु हों या साक्षी मलिक हों या दीपा करमाकर हों अथवा हमारी बाकी sportswomen हों, इस सबों ने कितना बड़ा नाम किया। पैरालिम्पिक्स में दीपा मलिक ने नाम किया। तो आज 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जनशक्ति के माध्यम से देश का एक बहुत बड़ा आन्दोलन बन गया है। यह एक बहुत बड़े बदलाव की बात है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

माननीय सभापति जी, आज मुझे सदन से एक और भी महत्वपूर्ण बात शेयर करनी है। 'पद्म अवाडर्स' तो सबको मिलते हैं, मिलने भी चाहिए। "भारत रत्न" भी मिलने चाहिए, 'पद्म भूषण' और 'पद्मश्री' भी मिलने चाहिए। इस बार के 'पद्म अवाडर्स' में एक बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ है? हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी सरकार ने आम आदमी को खोजा है। जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता था, उनको 'पद्मश्री' दिया है। मैं आपके सामने यह भी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' -- ऐसे

[Shri Ravi Shankar Prasad]

साधारण भारतीय, जो देश को बदलने का काम कर रहे हैं, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार उनको पहचानेगी। भले ही उनके लिए कोई प्रशस्तिगान करने वाला नहीं हो, भले ही उनके लिए कोई एमपी रिकमेंड करने वाला नहीं हो, भले ही उनके लिए कोई सरकार अनुशंसा करने वाली नहीं हो, but the Government of Narendra Modi will recognize their work and award them with the Padma Award. That is what has happened this year. Sir.

सर, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। श्री करीमुल हक़ 52 वर्ष के हैं। वे दलबाड़ी गाँव, जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल के हैं। इनके पास एक मोटरसाइकिल है। हर हफ्ते ये 20 गाँवों में से बीमार लोगों को ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचाते हैं। अब तक इन्होंने 3,000 लोगों की जिन्दगी बचाई है, जो परेशान थे, दुखी थे, बीमार थे, उनको 'पद्मश्री अवार्ड' दिया जा रहा है, चाय बागान में काम करने वाले एक गरीब मजदूर को यह अवार्ड दिया जा रहा है।

My friends from Kerala would like to know about Meenakshi Amma. She is 76 year-old from Kerala. What is her contribution? Right from the age of 16, she is teaching Kalaripayattu, the famous Kerala sport. For 68 years she is doing that job. Our Prime Minister has given Padma Shri to this great achiever of Kerala. ...*(Interruptions)*... All right, whatever my friends from Kerala say, I accept it; no problem.

Daripalli Ramaiah, my friend from Telangana, is 68 years. He has dedicated his life for making India green and planted one crore trees. He has been given Padma Shri by this Government. सभापति महोदय, इंदौर की 91 साल की डॉ. भक्ति यादव, जो कि Gynaecologist हैं, वे पिछले 68 साल से गरीबों को मुफ्त सेवा दे रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने खोजा, इनको 'पद्मश्री' दिया जायेगा और इस बार इनको यह अवार्ड दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। One Bipin Ganatra from Kolkata, my friend from Bengal would love to know, वे 59 साल के हैं, fire incident में उनके भाई की मौत हो गयी थी। उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य है कि जो लोग आग में फँसते हैं, उनको बचाएं। उनको 'पद्मश्री' अवार्ड दिया गया है।

Sir, I would like to share with this House that it is a metamorphosis of India happening now. The common people are being recognized. The contribution, quality, accomplishment of common people is being celebrated and it is now being talked about. They are given the highest honour. This is the Government, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', 'सबका साथ, सबका विकास'।

सर, आज 'पद्मश्री' अवार्ड की बात चलती है, तो एक बात कहने की इच्छा होती है। मैंने एक बार हल्के से इसका संकेत दिया था, आज थोड़ा विस्तार से बोलने की इच्छा है। आज़ादी के बाद हमारा देश 70 साल का परिपक्व देश हो गया है। इस देश को बनाने में बहुत लोगों ने काम किया। उनकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, उनकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा काम है कि हम ईमानदारी से उनके त्याग, बलिदान और उपलब्धियों को जानें और उन्हें आदर दें।

सभापति जी, डॉ. अम्बेडकर बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने देश को बदलने का बहुत बड़ा काम किया। वे 1956 में मरे, उनको 'भारत रत्न' 1990 में मिला और 1990 में किसकी सरकार थी? शरद जी बैठे हुए हैं, वी.पी. सिंह जी की सरकार थी, जिसके बायें आप खड़े थे, दाएं हम भी खड़े थे और सीताराम जी कहां हैं, वे भी पीछे खड़े थे, तब उनको 'भारत रत्न' देने के लिए स्वीकार किया गया। भारत के महान नेता, जोड़ने वाले नेता, सरदार पटेल 1950 में मरे थे, उनको 'भारत रत्न' 1991 में मिला। 41 साल के बाद उनको 'भारत रत्न' मिला, बीच में बहुत लोगों को मिला, नेहरू जी को मिला, राजेन्द्र बाबू को मिला, राधाकृष्णन को मिला, ज़ाकिर हुसैन को मिला, वी.वी. गिरी को मिला, राजीव गांधी को मिला, इंदिरा गांधी को मिला, अच्छी बात है, लेकिन वे कौन-सी ताकतें थीं, जो सरदार पटेल को 'भारत रत्न' मिलने से रोक रही थीं? मौलाना आज़ाद 1958 में मरे, मैं जितना उनको पढ़ता हूँ, सभापति जी, वे सही में देश के बहुत बड़े जननायक थे। उनको 'भारत रत्न' 1992 में मिलता है। 1991 से भारत के प्रधान मंत्री कौन थे, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह पीड़ा होती है कि वे कौन-सी ताकत थीं, वह कौन-सी सोच थी, जो रोकने का काम कर रही थी? कभी न कभी इस पर विचार करना पड़ेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1979 में मरे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में उनको 'भारत रत्न' दिया और शायद हमारे कांग्रेस के मित्र माफ करेंगे, अगर 1991 में भी परिवार के लोग होते, तो सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद को भी 'भारत रत्न' नरेन्द्र मोदी और वाजपेयी जी की सरकार को देना पड़ता, यह भी हम बड़े विश्वास से कहना चाहते हैं। हमें हृदय बड़ा करना पड़ेगा। We need to become more generous in recognizing the work and accomplishment of the leaders who have made India what it is today.

सर, हम एक बात और कहना चाहेंगे। हमारी, मोदी जी की सरकार की कुछ बड़ी मौलिक सोच है देश को बदलने की, गरीबों के लिए, क्योंकि खास करके दीन दयाल उपाध्याय जी के सौ वर्ष पूरे हुए हैं, हम इसे 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, तब इसी संसद के सेन्ट्रल हॉल में बोलते हुए प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, उस समय वे बीजेपी के पार्लियामेंटरी पार्टी और एनडीए के नेता बने थे। हमारी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए काम करेगी और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', 'सबका साथ, सबका विकास' रखते हुए भी हमारे सिद्धांत के और मौलिक उप-सिद्धांत हैं और वे हैं, *banking the unbanked, number one; funding the unfunded, number two; securing the unsecured, number three; pensioning the unpensioned, number four*. ये हमारे चार सिद्धांत हैं। ऐसे लोग, जो बैंक में नहीं आए, उनको बैंक में लाओ, उनको गरीबी से ऊपर उठाना है। ऐसे लोग, जो बैंक में नहीं आए, उनको बैंक में लाओ, उनको गरीबी से ऊपर उठाना है। ऐसे लोग, जिनको आज तक बैंक से लोन नहीं मिलता था, फंडिंग नहीं होती थी, उनको फंड में लाओ। ऐसे लोग, जिनको सुरक्षा नहीं मिलती थी, उनको सुरक्षा में लाओ। सभापति जी, सदन में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, क्योंकि उस काम में हम भी लगे हुए थे, जब बैंक कर्मचारियों से प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया कि आप देश के लिए जागो और उन लोगों ने एक साल के अंदर 27 करोड़ लोगों के जनधन एकाउंट्स खोल दिए, जो आज तक बैंक से बाहर थे और उनसे कोई अपेक्षा नहीं की गई कि आप पैसा जमा करो, लेकिन उन गरीबों ने 10 रुपए, 20 या 50 रुपए करके more than 45,000 करोड़ रुपए जनधन एकाउंट्स में जमा कराए।

[Shri Ravi Shankar Prasad]

सर, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा, 'सीक्योरिंग द अनसिक्योर्ड', आप बताएं कि सिर्फ एक रुपया प्रति महीना देकर दो लाख रुपए का इश्योरेंस कवर मिल जाए, और 330 रुपए प्रति साल देकर, जो एक रुपए से भी कम प्रतिदिन बनता है, दो लाख रुपए का इश्योरेंस कवर मिल जाए, अभी तक 13 करोड़ लोगों को हमने यह इश्योरेंस कवर दिया है, जो गरीब हैं, आम आदमी हैं और यह काम चल रहा है। सबसे बड़ा काम तो 'फंडिंग ऑफ अनफंडेड' के अंतर्गत हुआ है।

मुद्रा लोन योजना की बात, सभापति जी, आपने सुनी होगी। अभी तक हमने दो लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन योजना में 5.6 करोड़ ऐसे लोगों को दिए, जो पान वाले, चाय वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले हैं, जो छोटा-छोटा काम करते हैं। इसमें आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मुद्रा लोन योजना में लगभग दो-तिहाई लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स के भी हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के भी हैं। इस बार के बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी से मैं बहुत आदर से बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इस पूरी राशि को डबल कर दिया है, दो लाख 44 हजार करोड़ रुपए मुद्रा लोन योजना में कर दिए हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल): बजट में प्रावधान किया है ...*(व्यवधान)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: एक लाइन तो मुझे बोल सकते हैं - There is no *res judicata* or prohibition. 'पेंशनिंग अनपेंशन्ड' आदि सारी बातें आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की हैं। उसमें हम लोगों ने अब तक बड़ी संख्या में लोगों को राहत देने का काम किया है।

यहां मैं किसानों की बात करूँ, उससे पहले दिव्यांगों की बात करना चाहता हूँ। अपनी सरकार में, जिसकी चर्चा राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में की है, दिव्यांगों के लिए जो काम हुआ है, सबसे पहले तो हमने इस योजना का नाम बदला है। पहले उसका नाम विकलांग था, जिसे बदलकर हमने दिव्यांग किया है। सर, यह विकलांग से दिव्यांग की यात्रा बहुत सोच की यात्रा है। विकलांग से कमजोरी समझ में आती है, दिव्यांग से आशा जगती है। *Divyang* represents hope. Handicap remains handicap. That is the basic, fundamental difference. इसमें हमने उनके रिजर्वेशन को तीन से बढ़ाकर चार परसेंट किया है। लगभग 6 लाख दिव्यांगों को हमने 47,00 special assistance camps लगाकर राहत दी है। इसके अलावा, माननीय थावर चन्द गहलोत जी की अगुवाई में, इस विभाग में काफी दूसरे काम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बार पैरालिम्पिक्स में हुई, इस बार blind cricket में हमारी team first आई और दीपा मलिक ने पैरालिम्पिक्स में बड़ा एवार्ड जीता।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Even Mariappan.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: My friends from Tamil Nadu are always great. ...*(Interruptions)*... I am grateful. I take the name with a great degree of pride and assurance.

सर, जहां हम किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए कल माननीय वित्त मंत्री जी ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की घोषणा की है, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे।

फिर भी, फसल बीमा योजना के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अभी तक एक लाख चार हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे 3 लाख 66 हजार फार्मर्स को पिछले साल फायदा हुआ है, लोग योजना का फायदा ले रहे हैं। इस बार इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, soil health card, इरिगेशन के नाम पर, 40 हजार करोड़ रुपया नाबार्ड के पास गया है, 5,000 करोड़ रुपए स्माल फार्मर्स के लिए और नीम कोटेड यूरिया इत्यादि की बात तो हम काफी सुनते हैं। इस मामले में हम अपनी सोच के बारे में दो बातें और कहेंगे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। आप देखें कि जितने लोगों के पास गैस नहीं है, उन गरीबों को गैस मिलनी चाहिए। एक भाषण रहा है कि फूँककर चूल्हा जलाना, आँख खराब होना और एक चूल्हा जलाने में लगभग 400 सिगरेट्स का धुआँ consume करना। अब क्या सोच बनी? गरीबों को हमें गैस का चूल्हा देना है और उसके लिए एक और पहल हुई। वह पहल यह थी कि जो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, वे छोड़ें, जो afford कर सकते हैं, वे afford करें। माननीय सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने अपील की और 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी अपने आप छोड़ दी। यह देश में एक नई चीज़ देखी गई। मैं फिर इस पर आता हूँ। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। इस उदाहरण को देखकर मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आ गई। हम लोग तब बहुत छोटे बच्चे थे, जब सन् 1965 का युद्ध हुआ था। जब पाकिस्तान के साथ हो रही लड़ाई के कारण अमेरिका में बैठी ताकतें अमेरिका के पीएल-480 गेहूँ को यहाँ आने से रोक रही थीं, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश से यह अपील की थी कि हिन्दुस्तान के लोगों, सोमवार के दिन रात्रि का भोजन छोड़ दो और देश ने सोमवार को रात का भोजन छोड़ा था, ताकि देश में अनाज की व्यवस्था हो। उसके बाद से यह पहली घटना हुई। आज हमें लगभग 5 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा फ्री देना है। लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को यह दिया गया है और इसको और भी आगे बढ़ाना है।

माननीय सभापति जी, यह जो "दीनदयाल ज्योति योजना" है, इसमें प्रधान मंत्री जी का क्या निर्देश हुआ? भारत की आज़ादी के 68 साल बाद भी 18,000 गाँव बिना बिजली के हैं! यह नहीं होना चाहिए। आज 11,000 से अधिक गाँव बिजलीयुक्त हो चुके हैं और इस साल के अंत तक पूरे 18,000 गाँवों में बिजली पहुँच जाएगी, यह एक बदलाव का लक्षण है और जनता के सहयोग से यह हो पाता है।

सर, हमें भारत के संस्कारों पर बहुत विश्वास है, भारत की संस्कृति पर भी बहुत विश्वास है, उससे हम गर्व लेते हैं। हम अतीत से सीखते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को मजबूत बनाते हैं, लेकिन हमारी सरकार के आने के पहले हमारी एक राजनीतिक विरासत भी थी। हमारे मित्र हमें ज़रा क्षमा करेंगे। उस समय देश की क्या स्थिति थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कैसा policy paralysis था, महँगाई कितनी थी, देश में कितना भ्रष्टाचार था? ...**(व्यवधान)**... आप तो भारत की संस्कृति को बहुत जानते हैं, आपके समय यह 8 से 10 परसेंट था। आप चिन्ता मत करिए, यह आँकड़े की बात है, यह देश जानता है। दिसम्बर में यह कितना कम हो गया है, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन को बताया है कि यह 3 परसेंट हो गया है। आप तो भारत की संस्कृति को बहुत जानते हैं। पंचतत्व से पृथ्वी बनती है, जिसमें आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है और जमीन भी है। यह बात तो हमने सुनी है, यह अच्छा है, लेकिन पृथ्वी के हर तत्व में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार देखा गया। अंतरिक्ष में भी देखा गया— Antrix Devas; वायु में भी देखा गया — airwaves spectrum; आकाश में भी देखा गया —

[Shri Ravi Shankar Prasad]

helicopter scam; जमीन पर भी देखा गया — आदर्श और कॉमनवेल्थ स्कैम्स; पाताल में भी देखा गया — कोयला स्कैम; और समुन्दर में भी देखा गया — submarine scam. तो यह पंचतत्व की नई व्याख्या हमें समझ में आई। आजकल जमाना innovation का है और innovation में नई-नई बातें आती हैं। उस समय innovation में क्या बात की जा रही थी, zero loss theory! कोयला स्कैम पर आपकी तरफ के एक बहुत विद्वान मित्र ने कहा, "Since the coal is embedded to the land, there is a scam." ये बातें हम सुनते थे, उस समय हम विपक्ष में थे। मुझे आज इस बात का बहुत मान और गौरव है कि अतीत की सरकार के विपरीत नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बंद है और ईमानदारी से फैसले होते हैं। जहाँ कोयला घोटाला होता था, वहाँ हमने ईमानदारी से नीलामी की। जहाँ घोटाला हुआ था, वहाँ 3 लाख करोड़ रुपये आए और वह पैसा केन्द्र और उन प्रदेशों को जा रहा है, जहाँ कोयले की खदानें हैं।
...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): अभी आया नहीं है। ...(व्यवधान)... आया या आ गया है?
...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: अच्छा, ठीक है। अब मुझे बोलने दीजिए। स्पेक्ट्रम में पहली बार ऑक्शन हुआ। जहाँ घोटाले हुआ करते थे, वहाँ से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये की highest ever राशि भारत सरकार को आई। इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में स्पेक्ट्रम बेचा गया। Spectrum sharing, spectrum trading, harmonization, ये सारे काम पूरे किए गए। तो ये बदलाव हुए हैं। लेकिन जहाँ policy paralysis था, वहाँ भारत का चेहरा क्या बदला है, भारत का व्यक्तित्व क्या बदला है इसके बारे में हम सदन को जरूर कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है कि चाहे दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, वह किस तरह से सार्थक चर्चा करके, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो या किसी और संस्था की रिपोर्ट हो या आई.एम.एफ. की हो, सब जगह एक ही बात कही जा रही है कि India is the most promising economy. नोटबंदी पर मैं अलग से चर्चा करूंगा।

आज मैं बार-बार उस सारे को साइड करके यहां बताना नहीं चाहता हूं कि क्या-क्या बदलाव हुआ है, लेकिन यह जग जाहिर है कि किस तरह से बदलाव हुआ है। अब आप देखें एफ.डी.आई. की बात आई थी। India today is host to the highest number of FDIs. यह बताने की जरूरत है। सर, जरा उन लोगों को शांत होने के लिए बोलेंगे, उनको बोलने का मौका मिलेगा। Our manufacturing is going very high. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the speaker to continue.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Our manufacturing has gone high. Yesterday, it was explained in great detail how India is home to the biggest number of FDIs in the recent years. Yesterday, it was explained in great detail. I don't want to go into those details. Those are matters of record as to how India today is privy to the biggest foreign exchange reserves. Today, India has scaled great heights in Ease of Doing Business. ये बातें तो सभी जानते हैं। नोटबंदी पर कमजोरियों को उजागर करते हुए भी चाहे वह आई.एम.एफ. हो

या वर्ल्ड बैंक हो, वे सब क्या कह रहे हैं? Indian growth story in the coming two to three years is going to be 6.5 per cent to 7.5 per cent to 8.5 per cent. यह हम नहीं कह रहे हैं। अब वे नहीं मानते हैं तो उनको उनकी शुभकामनाएं मुबारक हों, उनके विचार मुबारक हों। सर, मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, इधर कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर हमें विदेश जाने का मौका मिला कुछ सरकारी मामलों में। चार देशों में यूरोप के तीन देशों के एम्बैसेडर ने मुझे यह बात कही। आप जानते हैं कि एम्बैसेडर लगभग 30 साल सर्विस करने के बाद बनते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भारत के प्रतिनिधि इतने वर्षों से हैं, लेकिन भारत के एम्बैसेडर के रूप में दुनिया में हमको इतनी इज्जत आज तक नहीं मिली, जितनी नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में मिल रही है। ऐसा वे लोग बोल रहे हैं। अगर आप अब नहीं समझने को तैयार हैं तो आपके ऊपर है। आपकी स्पॉन्सरशिप कहती थी आप अपनी आज की जगह देखिए, पहले आप इधर बैठते थे। तो अभी काफी दिन वहां बैठेंगे, चिंता मत करिए।

सर, मैं नोटबंदी पर अब कुछ बोलना चाहता हूं। इसको लेकर काफी परेशानी रही। सर, भारत को ईमानदार रास्ते पर बनाने की कोशिश प्रधान मंत्री जी की उस दिन से है जिस दिन से पहली कैबिनेट बैठी थी। यह बात उन्होंने अपने पूरे चुनाव अभियान में भी कही थी। पहली कैबिनेट में क्या फैसला हुआ कि ब्लैक मनी के लिए एस.आई.टी. बनाई जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दो साल से आप नहीं बना रहे थे। वह हमने फैसला पहली कैबिनेट में किया। जी-20 कन्फ्रेंस में कैम्पेन करके प्रधान मंत्री जी ने कहा कि फॉरेन में जो काला धन जमा होता है, उसके ऊपर पूरी दुनिया को एक साथ बोलने की जरूरत है। आज automatic exchange of information अमेरिका के साथ है, स्विट्ज़रलैंड के साथ है। हम लोगों ने यहां टैक्स पर बदलाव किया, Bankruptcy Code लाए। Benami Act कितने वर्षों से इफेक्टिव नहीं था, उसको इफेक्टिव बनाया, उसको धारदार बनाया। उसके अलावा Money Laundering Act व बाकी सब किया। तो यह नोटबंदी एक पहली प्रक्रिया नहीं है जो की गई, दो साल में प्रधान मंत्री जी ने पहल करके भारत को ईमानदार और भारत की अर्थव्यवस्था को ईमानदार बनाने के लिए कई कोशिशों की गईं। अब नोटबंदी से जनता में प्रधान मंत्री जी ने ईमानदारी से अपील की थी कि आपको कुछ महीनों की परेशानी होगी। उन्होंने 50 दिन की बात कही थी। हमने यह भी देखा कि लोगों ने कहा कि हमें कठिनाई हो रही है, लेकिन यह जो कदम उठाया है नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह देश को मजबूत बनाने वाला कदम है, आगे बढ़ाने वाला कदम है। मुझे याद है, आज मुझे इस सदन में बोलना पड़ेगा कि हमारे कुछ टीवी के एंकर्स अपना छोटा-बड़ा कैमरा लेकर लाइन में खड़े हुए लोगों के मुंह में भी कैमरा घुसा दिया करते थे कि आपको कैसा लग रहा है? लोग कहते थे कि खड़े होते हैं तो परेशानी तो होती है, लेकिन यह कदम अच्छा है, यह भारत को बदलने वाला कदम है — यह हुआ है। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। यह हमने करके दिखाया है। सर, नोटबंदी पर हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन चाहे वह दुनिया हो, चाहे हिन्दुस्तान को समझने-समझाने वाले लोग हों, चाहे वे बड़े अर्थशास्त्री हों - एकाध को छोड़कर, जिनका हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में पूर्वाग्रह रहता है - सबने यह स्वीकार किया कि It is a transformational initiative taken by Narendra Modi Government. मैं आपको तीन-चार बातें बताता हूं। आतंकवाद की वित्तीय कमर टूटी या नहीं टूटी? हवाला कारोबारी की साख कमजोर हुई या नहीं हुई? सुपारी किलिंग्स की हिम्मत टूटी या नहीं टूटी? कश्मीर में पाकिस्तान के प्रायोजन से पैसे लेकर ढेला फैकने वालों की हिम्मत कमजोर हुई या नहीं हुई? जो माओवादी पैसे इकट्ठा करके,

[Shri Ravi Shankar Prasad]

प्लास्टिक में बांधकर नीचे गाढ़ते थे, वे हिंसा से कम, अपने पैसे को बदलवाने के लिए अधिक परेशान हो रहे थे — यह हमने करके दिखाया।

माननीय सभापति जी, एक जो सबसे बड़ी बात हुई है, जिसकी चर्चा मैंने बाहर भी की और मैं सदन को भी बताना चाहूंगा कि Resurgent India ने स्टडी किया है कि हिन्दुस्तान सेक्स ट्रेड के लिए जो मानव तस्करी हुआ करती थी, उसमें भयंकर कमी आयी है क्योंकि बंगाल, असम, झारखंड, बंगलादेश और नेपाल से लड़कियों को लाकर जो सेक्स ट्रेड के लिए exploit किया जाता था, वे सारे जो बिचौलिए थे, उनका पेमेंट पांच सौ और हजार रुपए के पुराने नोटों में हुआ करता था, वह धंधा भी कमजोर पड़ गया। हमने यह बदलाव करके दिखाया। इसके कारण एडवांस टैक्स कितना बढ़ा है, यह तो अरुण जेटली जी बता चुके हैं कि एकाएक उसमें कितना सर्ज आया है। इससे tax compliant देश कैसे बनेगा, इसकी भी चर्चा हुई है।

सभापति जी, आज मैं बहुत गर्व से अपनी सरकार के बारे में, माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, कि आज सरकार और वित्त मंत्री ने देश को ईमानदारी से बताने की कोशिश की है कि देश में कितने कम लोग टैक्स देते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि सिर्फ 24 लाख लोग दस लाख से अधिक आमदनी दिखाते हैं? लाखों की संख्या में कम्पनियां हैं, लेकिन सिर्फ सात हजार के करीब कम्पनियां अपनी आमदनी पचास करोड़ से अधिक बताती हैं? यह देश underpaid इन्कम टैक्स की स्थिति में था, यह स्थिति चल रही थी, इसको बदलना था। एक बात मैंने बाहर भी कही है और मैं आज सदन में भी कहना चाहूंगा कि आज देश के विकास के लिए, exact विकास के लिए साढ़े चार, पांच लाख करोड़ available होता है, बाकी पेंशन देनी पड़ती है, सेलरी देनी पड़ती है और बाकी establishment cost होता है। क्या हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना बने, अच्छे आयुध आएँ, अच्छे weapons आएँ? Do we want or not that Indian good young mind must innovate, create good intellectual property and patent for the country? क्या हम चाहते हैं या नहीं चाहते कि भारत का satellite दुनिया में और आगे ऊँचाई पर जाए? उसके लिए we need money, we need to enlarge the tax base of India. यह नोटबंदी का जो ऐतिहासिक कदम है या भारत को मजबूत और ईमानदार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, यह हम कहना चाहते हैं।

सर, हमने surgical strike की - एक तो नोटबंदी करके और दूसरी सरहद के पार भी की - उसको लेकर भी काफी परेशानी हुई। यह कहा जा रहा है कि सबूत लाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। देश के जवानों के बलिदान और हिम्मत का सबूत नहीं मांगा जाता है, वे तो देश के लिए त्याग करते हैं। हमने पाकिस्तान से रिश्तों को अच्छा करने की पूरी कोशिश की। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं पहल की। अटल जी का कहना था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर वहां आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलेगा तो भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए हर यथोचित वैधानिक कार्यवाही करेगा, उससे यह संकेत आता है। सर, आप तो विदेश नीति को स्वयं बहुत समझते हैं, आपका व्यापक अनुभव है। इस बार भारत और पाकिस्तान के साथ जो हुआ, इसमें हमने एक नया नजारा देखा। पहले भारत के साथ पारम्परिक रूप से रूस खड़ा रहता था और बाकी दुनिया या तो चुप या indifferent या पाकिस्तान की ओर झुकी हुई दिखाई पड़ती थी। इस बार ऐसा हुआ कि क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या आस्ट्रेलिया, क्या भारत के

पड़ोसी, क्या सउदी अरेबिया, क्या इराक, क्या ईरान, क्या क़तर, क्या दुबई, क्या मस्कट, सब भारत के साथ खड़े नज़र आए। यह देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात हुई है। हमारे प्रधान मंत्री विदेश जाया करते थे, यह सही है। दुनिया के एक लोकप्रिय नेता हैं। उधर से कभी-कभी एक सवाल उठता था कि आजकल प्रधान मंत्री जी भारत की यात्रा पर हैं। ऐसा हम सुनते थे। हम अपने ऐसे मित्रों को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे कि भारत के प्रधान मंत्री विदेश छुट्टियां मनाने नहीं जाया करते थे। वे भारत की सुरक्षा की दीवारों को मजबूत करने जाया करते थे और पाकिस्तान की दीवारों को कमजोर करने जाया करते थे। वे जहां भी जात थे, हम जानते थे कि भारत के प्रधान मंत्री जी कहां गए हैं, हमें यह भी मालूम था। आज इस देश के बदलाव में, भारत की विदेश नीति ...(व्यवधान)... आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। ...(व्यवधान)... मेरा कहना यह है कि भारत की विदेश नीति की यह बहुत बड़ी श्रेष्ठता हुई है कि भारत एक दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरा है।

सर, मैं कुछ मोटी बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक बात कहूंगा और मैं यह बहुत भावुकता से कहना चाहता हूं कि देश में जो सेना के जवान क़ुरबान होते हैं, जब आप उस क़ुरबानी का सबूत मांगते हैं, तो कभी-कभी उनके परिवार से पूछना चाहिए। अभी 26, जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय राइफल्स के martyr के हवलदार हंगपन दादा को अशोक चक्र दिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री बी. के. हरिप्रसाद (कर्णाटक): सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताइए। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। आप तो मंत्री भी रहे हैं, आप सांसद भी हैं। आप शांत रहिए।

श्री बी. के. हरिप्रसाद: आप सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, इन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए चार आतंकवादियों को मारा और इनको देश का सर्वश्रेष्ठ पीस टाइम अवार्ड दिया गया, अशोक चक्र अवार्ड दिया गया।

सर, मैं टी.वी. देख रहा था। उनकी पत्नी अरुणाचल प्रदेश से आती हैं और उनका बेटा भी। उनके छोटे बेटे से जब पूछा गया कि तुम क्या बनोगे, तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी की तरह सेना में जाऊंगा, सेना का अफसर बनूंगा और आतंकवादियों से लड़ूंगा। यह भारत की परम्परा होती है और मैं यह हर बार देखता हूं कि जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं और ऐसा काम करते हैं।

सर, हमारी सरकार ने इसलिए तय किया "वन रैंक, वन पेंशन" का मामला, जो इतने दिनों से पेंडिंग था, कभी-कभी पांच सौ करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। सर, हमारे बिहार में एक कहावत है, गाज़ीपुर में भी होगी, "ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन।" सर, यह इतनी बड़ी अपेक्षा थी और इसके लिए सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपये दिए गए। किसी के जख्म पर क्या नमक छिड़का गया था? प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इसको पूरा करना है। सर, "वन रैंक, वन पेंशन" में 11,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अभी तक 6,200 करोड़ रुपये डिस्ट्रिब्यूट हो चुके हैं और 19,06,000 जो हमारे veterans हैं, वे इसका फायदा पा चुके हैं। यह होता है, "वन रैंक, वन पेंशन" को ईमानदारी से लागू करना और बाकी भी समय-सीमा के अंदर लागू कर दी जाएगी।

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

सर, मैं एक बात इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहना चाहूंगा कि सड़कें कितनी बन रही हैं। पहले सड़क 73 किलोमीटर बनती थी और अब 135 किलोमीटर बनती है। नेशनल हाईवे कितना बन रहा है, पोर्ट कितना बन रहा है। कल लगभग 4 लाख करोड़ रुपया वित्त मंत्री जी ने दिया है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे और यह इन्फ्रास्ट्रक्चर में आज तक का highest allocation है। मैंने आरम्भ में ही कहा है कि मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है। Digital India, Make in India, Skill India, Start-up India, Stand-up India are all transformational programmes designed to make India an empowered society. सर, मैं आपको बताता हूँ कि हम डिजिटल इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं। इस देश के 111 करोड़ लोग आज "आधार" पर हैं। मैं यह मानता हूँ कि इसे आपने शुरू किया था। कुछ-कुछ अच्छा काम तो आप शुरू करते थे, उसको बढ़िया करना हमारा काम था। वह कहानी कभी और सही। अहमद पटेल जी बैठे हुए हैं, वे समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? सर, हमने JAM trinity किया। सर, 125 करोड़ के देश में 108 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल फोन्स हैं। पिछले दो साल में इस देश में इतने मोबाइल फोन्स जोड़े गए हैं, जितनी कि इटली और फ्रॉंस की जनसंख्या है। यह इस देश का मान बना है। सर, 111 करोड़ लोग "आधार" पर हैं, 50 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 35 करोड़ स्मार्ट फोन्स, India is becoming the biggest, fastest, start-up country in the world, even living China behind. यह देश में बदलाव हो रहा है। सर, यह देश कैसे बदल रहा है और लोग कैसे जाग्रत हो रहे हैं, मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी इंग्लैंड गए थे और Wembley stadium में भारतीयों को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलवर के इमरान खान हिंदुस्तान बना रहे हैं। सर, उस समय में कम्युनिकेशन विभाग का मंत्री था। हमने रात में ही बीएसएनएल के सीएमडी को कहा कि कल मैनेजर को बुके लेकर भेजो और वे उनसे मेरी बात कराएं। उनका 9 बजे फोन आया कि हमरान खान आपके फोन का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, जनाब आपका कल लंदन की एक सभा में प्रधान मंत्री जी ने नाम लिया है, आपको मालूम है? उन्होंने कहा, मैं तो सो गया था। उस वक्त रात के एक बज रहे थे। मुझे पड़ोसियों ने जगाया कि प्रधान मंत्री लंदन में तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत महाविद्यालय में गणित का शिक्षक हूँ। मैंने पूछा और क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि सर, मैं "ऐप" बनाता हूँ। मैंने पूछा किस के लिए? उन्होंने कहा बच्चों के लिए फिजिक्स, कैमिस्ट्री, कैलकुलस के "ऐप्स" बनाता हूँ। मैंने पूछा कितने बच्चे यूज करते हैं। उन्होंने कहा 40 लाख बच्चे हमारे "ऐप्स" को यूज करते हैं।

माननीय सभापति जी, अलवर जैसे छोटे शहर में अपनी विधा से वे यह कह रहे हैं। My friend from Telangana, I would like to tell you one more example. सर, सतम्मा देवी एक बीड़ी मजदूर हैं। वे डिजिटल लिटरेट हो गयी हैं। सर, हमने एक ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। वे celebrity हो गयीं और टी.वी. वाले उनका इंटरव्यू लेने गए। मैंने उनसे फोन पर बात की। She does not know English or Hindi. मैंने तेलुगू में ट्रांसलेशन से बात की। मैंने पूछा आप क्या करती हैं? वह बोली कि बीड़ी मजदूर हूँ। फिर पूछा कि आप डिजिटल literate कैसे हो गयीं? उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा दुबई में प्लंबर है। मैं उसे और अपने पोते को मिस करती थी। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि अगर पोते से बात करना है और उसका चेहरा देखना है, तो स्काइप करना सीखो। फिर स्काइप करने के लिए मैं कंप्यूटर लिटरेट हो गयी। इस तरह हिंदुस्तान बदलाव की कोशिश कर रही है। आज डिजिटल इंडिया ऐसे हर हिंदुस्तानी को आवाज दे रहा है और आगे बढ़ रहा है।

महोदय, हमने जन-धन को आधार से जोड़ा, मोबाइल से जोड़ा और गैस की, राशन की, कुकिंग गैस की सब्सिडी उनके अकाउंट में सीधे डालनी शुरू कर दी। सर, कुछ ही योजनाओं में 35 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है और माननीय सभापति जी, हमने 36 हजार करोड़ बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। सर, हमारी सरकार का यह मानना है कि digital governance is good governance; digital delivery is faster delivery; digital eco-system is honest eco-system. यह पूरी सोच है। इसलिए मुझे माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना है कि उन्होंने कल पेश किए अपने बजट में डिजिटल पेमेंट को बहुत आगे बढ़ाया है। सर, हमने "भीम ऐप" बनाया, जिसे अब तक सवा करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। यह बहुत लोकप्रिय हो रहा है।

माननीय सभापति जी, जिस तरह से आम आदमी इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा है। आज वह समझता है कि digital India के माध्यम से मुझे देश को बदलने का मौका मिला है। सर, हमारे दो लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। इन्हें दलित और साधारण महिलाएं चलाती हैं। ये 1,25,000 ग्राम पंचायतों में हैं, जोकि पासपोर्ट बनाती हैं, आधार कार्ड बनाती हैं, और बाकी काम करती हैं। सर, यह पूरे बदलाव का जो एक महान काम हो रहा है। सर, Skill India, कौशल विकास योजना, आज 12 हजार करोड़ रुपये देश के नौजवानों को skilled करने के लिए दिए गए हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की योजना है। सर, यह पूरे भारत को मजबूत बनाने का एक कार्यक्रम है।

सर, Transformational Programme जैसे एक और बड़े कार्यक्रम की बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने उसकी विस्तार से चर्चा की है। हम गंगा ऊर्जा की तरह जगदीशपुर से धर्मा तक इसे ले जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No posters, please. Sit down. ...**(Interruptions)**... Hon. Member, please sit down. ...**(Interruptions)**... Take away the poster; please sit down. ...**(Interruptions)**... Please sit down.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, हम इस तरह से गोरखपुर से, बरौनी से लेकर सिंदरी के पूरे फर्टिलाइजर कारखाने को आगे बढ़ाएंगे और लगभग 20 हजार से अधिक गांवों और शहरों में पाइपलाइन से गैस की व्यवस्था करेंगे। सर, यह गैस ऊर्जा का एक नया स्रोत बना है। यह सरकार बदलाव की सरकार है, यह सरकार transformation की है।

माननीय सभापति जी, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please sit down, hon. Member. You are not allowed to display posters here. ...**(Interruptions)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: जब बदलाव की सरकार बनती है, तो जो देश निराशा के माहौल में था, वही देश भ्रष्टाचार से पीड़ित था। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Stop interruptions. ...**(Interruptions)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: वही देश, जो निराशा में था कि इस देश में एक प्रकार से कुछ नहीं हो सकता है, यह भाव था। ...**(व्यवधान)**... चाहे वह हिन्दुस्तान के NRI हों, हमें बहुत गर्व है, हम विदेशों में जाया करते थे। They used to feel so hopeless, "What has happened to our country?" ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री रवि शंकर प्रसाद: आज वही भारत उत्साह में है, आज वही भारत आशा में है, आज वही भारत विश्वास में है और आज वही भारत एक नए भारत के भविष्य के संकल्प को लेकर ऊर्जावान है। मोदी जी की सरकार एक ईमानदार भारत बनाना चाहती है, एक ऊर्जावान भारत बनाना चाहती है, श्रेष्ठ भारत बनाना चाहती है और दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहती है। भारतवर्ष पनपे यह हमारा संकल्प है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उस पूरे दृष्टिकोण को विस्तार से रखा है। मैं इसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, इस प्रस्ताव को मूव करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe to make his speech seconding the Motion. ...**(Interruptions)**...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): आदरणीय सभापति जी ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, take away that poster and sit down.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir. ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. When your turn comes to speak, you will speak.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, श्री रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा यहां जिस प्रस्ताव को रखा गया है, उसका अनुमोदन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि देश में गवर्नेन्स के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाली इस सरकार के संदर्भ में जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण रहा, उसके ऊपर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव का अनुमोदन करने का अवसर मुझे मिल रहा है।

सभापति जी, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, एक दृष्टि से अमरीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पद्धति से State of the Nation Address करते हैं, उस तरीके का होता है। पूरे देश में क्या चल रहा है, सरकार के इरादे क्या हैं, भविष्य की योजनाएं क्या हैं, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सिलसिलेवार तथा तफसील से कई मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से स्पर्श किया है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

उस भाषण में जो कहा गया है, उसी के ऊपर और अधिक विस्तार से कहने की शायद आवश्यकता नहीं है। आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी ने उसके बारे में बहुत विस्तार से हमें कुछ बातें बताई हैं। जो चार बिन्दु मेरे ध्यान में आए हैं, मैं केवल चन्द मिनटों में उनके ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सबसे पहली बात यह है कि यह सरकार एक continuity with change के इरादे से काम कर रही है। इस सरकार को सत्ता में आए ढाई साल हो रहे हैं, व्यवस्था वही है, लोग वही हैं। मतलब सरकारी तंत्र चलाने वाले अफसरशाह वही हैं, कानून का दायरा भी वही है, सदन के नियम भी वही हैं, बावजूद इसके जो प्रेरणा हमारी सरकार ने सरकार संचालन करने वाले हर व्यक्ति के अंदर निर्मित की है, उसके कारण परिवर्तन आ रहा है, इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में कहते हैं, 'नित्य नूतन चिर पुरातन'। यह बात सही है कि ...**(व्यवधान)**... जो एक व्यवस्था बनाई गई है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijayasai Reddy, please sit down. ...*(Interruptions)*... Please don't do that. Sit down. Don't do that, please. It is very unfortunate. Why do you do like this?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I would like to draw the attention of hon. Prime Minister. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not the way for doing that. Please put it down. This is not the way.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What are you doing? Nothing will go on record. Whatever he says will not go on record. Sit down. It is very unfortunate.

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Sir, I am not yielding. Kindly allow me to continue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijayasai Reddy, please, don't do this. Sit down.

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे: उपसभापति जी, मैं आपसे यह कह रहा था कि जब ideology-driven सरकार आती है और इस सरकार की ideology ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vijayasai Reddy, sit down. I will take action against you. Stop this. I cannot allow this. ...*(Interruptions)*... You put it down first. ...*(Interruptions)*...

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. This is not allowed. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is our humble request. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to me. If you have anything to say, you give notice; tomorrow, we will allow but now, please sit down. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... You cannot disobey the Chair like this. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): You have drawn the attention of the entire nation. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, please. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, please. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It cannot be allowed. No, no. This is not allowed. ...*(Interruptions)*... I am sorry, I cannot allow this. ...*(Interruptions)*... What are you doing? ...*(Interruptions)*... Please put it down now. ...*(Interruptions)*... Please advise him. ...*(Interruptions)*...

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, प्रधान मंत्री जी एक बार देख के मुँह घुमा लें, फिर वे बैठ जाएंगे। प्रधान मंत्री जी एक बार देख लें कि यह क्या है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He can give notice. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... He can give notice. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: You were drawing the attention of the Prime Minister and the entire nation. ...*(Interruptions)*... Your mission is completed. ...*(Interruptions)*...

चौधरी सुखराम सिंह यादव: प्रधान मंत्री जी एक बार देख लें।

एक माननीय सदस्य: देख लिया है।

चौधरी सुखराम सिंह यादव: प्रधान मंत्री जी ने देख लिया है, तो फिर बैठ जाएंगे।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता था कि जब हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास" का मंत्र लेकर सत्ता में आई है, तो देशभक्ति हमारी सरकार की विचारधारा की माता है और राष्ट्रवाद हमारी सरकार की विचारधारा का पिता है। इसलिए इस देश की मिट्टी के साथ, इस देश के स्वभाव के साथ, इस देश के लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, जो इथोस है, उसके साथ मेल खाते हुए, उनका विश्वास और संपादन करते हुए, उनको सहभागी बनाते

हुए एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का नया मॉडल खड़ा करने की दृष्टि से यह सरकार अग्रसर हो रही है। जब एक कार्यकर्ता सत्ता में आता है - वह किसी घराने की बदौलत सत्ता में नहीं है, एक कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता ज़मीन से लेकर काम करते-करते जब प्रधान मंत्री पद तक आता है, तब वह दुनिया के गरीबों की समस्याओं को पहचानता है, जिसका रिफ्लेक्शन उसकी नीतियों में पड़ता है।

मैं अपने अगले बिंदु पर आता हूँ कि इस सरकार की प्रमुख विचारधारा है - वंचितों के प्रति संवेदना, गरीबों का कल्याण और गरीबों का सशक्तिकरण यह कैसे है, इसको मैं आपको चार बिंदुओं में बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में किसानों के लिए बीमा योजनाओं का एक लंबा सिलसिला रहा है और हमने देखा है कि इसके लिए अवर्षण की स्थिति, अकाल की स्थिति या अतिवृष्टि की स्थिति को डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद ही उसको बीमा का लाभ मिलता था। हमारे शहर में कोई गाड़ी खरीदता है, तो वह बीमा करा सकता है, कोई बंगला खरीदता है, तो वह बीमा करा सकता है, कोई स्कूटर खरीदता है, तो वह बीमा करा सकता है, कोई कंप्यूटर खरीदता है, तो वह भी बीमा करा सकता है, मगर किसान अपनी फसल, जिसको वह अपनी मेहनत के आधार पर उगाता है, उसका बीमा करने की कोई सहूलियत इस देश में नहीं है। अब यह हुआ है, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" की खूबी यह है कि खेत में आप जो फसल उगाओगे - जयराम रमेश जी, आप भी जानते हैं कि फसल चक्र के हर पायदान पर उसको सुरक्षा प्राप्त हो गई है। अगर खेत में फसल बनी हुई है और किसी कारणवश फसल का नाश होता है तो उसको बीमा की सुरक्षा मिलेगी। अगर आप बाजार में फसल ले जाते हो, कोई एक्सिडेंट होता है, फसल वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तब भी आपको बीमे की सुरक्षा मिलेगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश के किसानों को पूरे जीवन चक्र में सुरक्षा देने वाली इस तरीके की एक बहुत ही अनूठी फसल बीमा योजना दी है, जिसके कारण किसानों को राहत भी मिली है। उसके लिए अभी आबंटन भी बढ़ा है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, इससे पहले, हमारे पूर्ववक्ता ने "उज्जवला योजना" का जिक्र किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर हमारे देश का जो अविकसित इलाका है - ईशान्य भारत, पूर्वांचल, उस पूर्वांचल के हमारे भाई-बहनों को न्याय मिले, इसके लिए प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार यहाँ पर आई थी। उस सरकार ने डोनर, Department of North-East Region नाम का एक मंत्रालय बनाया था। यह मंत्रालय बहुत सुचारु रूप से चला। 2004 में वह सरकार गई, नई सरकार आई। सरकार के साथ-साथ जो प्राधान्य क्रम था, प्राइयोरिटी थी, उसको बरकरार रखना जरूरी था, लेकिन उसको रखा नहीं गया। जिस भाव से उस मंत्रालय का निर्माण किया गया था कि उनकी उपेक्षा का अंत हो, उस मंत्रालय की ही उपेक्षा हुई। इस पद्धति से इस मंत्रालय के साथ खिलवाड़ किया गया, उनका आबंटन कम हुआ और उसके ऊपर ध्यान देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। अभी हमारे डा. जितेन्द्र सिंह उस मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं। वे हमें बता रहे थे कि अब ईशान्य भारत के, हमारे पूर्वांचल के मुख्य मंत्रियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय उनकी राजधानियों में उनकी समस्याओं का हल निकालने की दृष्टि से हर महीने कैंप लगा रहा है, जिसके कारण सरकार उनके द्वार जा रही है। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्टर्न

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

3.00 P.M.

काउंसिल की एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी, जिसके लिए शिलाँग में एक बहुत बड़ा संस्थान खड़ा है, मगर विगत 15 सालों में उसकी बैठक नहीं हुई थी, उसमें नियुक्तियां नहीं हुई थीं। जब हमारी सरकार आई, तो उस संस्था को पुनर्जीवित किया गया, उसकी बैठक हुई और जिसके कारण विकास के रास्ते भी प्रशस्त हो गए। जो हम "सबका साथ" कहते हैं, तो यह केवल नारा नहीं होता, *we live by the slogan. We define the slogan in such a way that it is translated into reality.*

उपसभापति जी, दिव्यांगों की चर्चा भी इस सदन में हुई है। हमारे थावर चन्द गहलोत जी उस मंत्रालय का नेतृत्व का रहे हैं। हम सब यह जानते हैं कि जितने सारे दिव्यांग हैं, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए, उनको अंगदान करने के लिए कार्यक्रम होते हैं, जैसे जयपुर फुट दिए जाते हैं, अन्य दूसरे उपाय किए जाते हैं। अब ऐसे कार्यक्रम करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, मगर ये कार्यक्रम किए नहीं जाते थे, क्योंकि उनके बारे में कोई बहुत उत्साह नहीं होता था। केन्द्रीय मंत्रालय के द्वारा साल में मुश्किल से पच्चीस, तीस ऐसे कैम्प लगाए जाते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई, तो सरकार ने सोचा कि हम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्यों न हमारे जन-प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए? हमारे सभी सांसदों को, विधायकों को सरकार ने चिट्ठियां लिखीं कि ये कैम्प आप अपने-अपने चुनाव-क्षेत्र में ऑर्गेनाइज करिए, इससे आपको लाभ होगा और जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी लाभ होगा। इससे 300 परसेंट का इजाफा हुआ और इस तरीके के 150 से भी अधिक कैम्प मात्र दो साल की अवधि में लगे। मैं मानता हूँ कि जब संवेदनशील होने वाले व्यक्ति सत्ता का नेतृत्व करते हैं, तब इस तरीके का परिणाम निकल कर आता है। इसलिए मैं इसका भी यहाँ आग्रह के साथ जिक्र करना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, हम सब रेलवे के बारे में जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इस सरकार का बहुत अच्छा बल सोशल मीडिया पर रहा है। यह सोशल मीडिया कोई एक फैशन नहीं है, यह सोशल मीडिया कोई अपना स्टेटस बढ़ाने का औजार नहीं है, बल्कि इस सोशल मीडिया को जनता के उपयोग के लिए, उसकी पीड़ा, दुख-दर्द मिटाने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। कैसे? हम जानते हैं और हमने देखा है, आप सब लोग भी जानते हैं कि ट्विटर का उपयोग करते हुए हमारे रेल मंत्री का ध्यान आकर्षण करते हुए कई रेल यात्रियों ने अपनी पीड़ा का हरण किया। कोई महिला यात्रा कर रही थी, जिसने बच्चे के लिए दूध लिया था, जो खराब हो गया और गाड़ी रुकती नहीं थी, कोई फास्ट ट्रेन थी, तो उसने ट्वीट किया। उसके बाद उस गाड़ी को किसी दूसरे स्टेशन पर एक स्पेशल हॉल्ट दिया गया और उस बच्चे की आवश्यकता पूरी करने के लिए रेलवे के कर्मचारी दूध लेकर वहाँ उपस्थित हुए। That is called a Government with sensitivity. उदयपुर से हमारे एक मित्र ट्रेन से आ रहे थे। जब वे आ रहे थे, तो उनकी बहन भी साथ में सफर कर रही थी, जो दूसरे कंपार्टमेंट में थी। यात्रा में रात्रि का प्रवास होता है। जब वह रात्रि में श्री ए.सी. कंपार्टमेंट में ऊपर की सीट पर थी, जब रात्रि का अंधेरा और घना हो गया, तो उसको लगा कि कुछ लोग उस कंपार्टमेंट में आए और उन्होंने शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी हुआ। यह अकेली महिला थी, डर गई। उसने भाई को पूछा कि मैं क्या करूँ? भाई ने कहा कि तुरंत ट्वीट करो, हो सकता है एक-आधे घंटे में कुछ कार्यवाही

हो। उसने ट्वीट किया। संबंधित डिविजनल रेलवे मैनेजर ने जो भी कॉन्गीजेंस लेना जरूरी था, वह लिया और आधे घंटे के अंदर जो भी उसको परेशान करने की स्थिति में थे, ऐसे शराबियों को हिरासत में लिया गया। यह होता है - Government that works.

उपसभापति जी, मैं यहां पर आपको यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि संवेदना यह सबसे अहम पहलू है, जो इस सरकार की चिंतनधारा है, जो सिद्धांत है, उसका। कई प्रधान मंत्री इस देश में हुए और उनमें कई प्रधानमंत्रियों ने दिवाली अपने-अपने तरीके से मनाई, मगर ये ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जो अपनी दिवाली मनाने के लिए हर बार सियाचिन जाते हैं, बॉर्डर एरिया में जाते हैं, जवानों के साथ अपने त्योहार का आनंद बांटते हैं। इसके लिए संवेदना जरूरी होती है, कृतज्ञता जरूरी होती है, केवल नारों से काम नहीं चलता, कल मैं वित्त मंत्री जी का बजट सुन रहा था। इस बजट के बारे में चर्चा तो बाद में होगी, मगर यह रेलवे यात्रा का ही विषय है, मुझे अच्छा लगा इतनी बारीकी से जाकर इसमें ऐसा किया गया। हमारे कई जवानों को कई बार आनन-फानन में यहां से आना-जाना पड़ता है, रेल यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जब जाते हैं तो ऐन समय पर आरक्षण संभव नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में उनके लिए जो सुविधा आवश्यक होती है, माननीय वित्त मंत्री जी ने इतनी बारीकी में जाकर सोचते हुए उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए डिफेंस पर्सोनेल की यात्रा को सुखद करने के लिए, हेसल-फ्री करने के लिए एक प्रावधान किया है। मैं इस समय वित्त मंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी बारीकी से इस बारे में सोचा है, which is something very rare. उपसभापति जी, मैं आपको तीसरे पहलू पर ले जा रहा हूँ, जो इस सरकार की विशेषता के बारे में है और उसका नाम है - नवाचार, Innovation. Innovation की चर्चा तो हम काफी सुनते आए हैं और innovation को promote करने के लिए इस देश में इसके पहले भी प्रयत्न होते रहे, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया नहीं, मगर innovation, जिसको out of box thinking कहते हैं, उसका क्रियान्वयन हमारी सरकार की governance की प्रक्रिया के अन्दर करना और लोगों को भी सचेत करना, लोगों का भी आह्वान करना कि आप सोचिए, अपनी प्रतिभा का परिचय दीजिए, आपके जो भी सुझाव हैं, उनका स्वागत है, इस पद्धति से खुले मन से इस विषय की ओर देखना, मैं मानता हूँ कि यह इस देश के governance के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह कोई जरूरी नहीं था कि पद्म पुरस्कारों के बारे में हमेशा एक secrecy का वातावरण रहे कि पता नहीं यह किसको मिलता है, क्या करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किसको खुश रखना पड़ता है, nobody knows. अब क्या हुआ! अब सरकार ने आदेश कराया कि पद्म पुरस्कार के लिए आप इंटरनेट पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, आप जिस किसी को नामांकित करना चाहते हैं, आप उसका नाम दे दीजिए, उसके बारे में सरकार निर्णय करेगी। इतना खुलापन! पद्म पुरस्कारों के लिए कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई ordinance निकालने की जरूरत नहीं थी। जब मन में इच्छा होती है, जब खुलेपन के प्रति एक प्रतिबद्धता होती है, तब यह हो सकता है। मैं मानता हूँ कि यह एक नवाचार का उदाहरण है कि इस तरह की बातों को हमने जनता के साथ बाँटा है, जनता के सुझाव माँगे हैं। अभी-अभी रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि कितने नामी-गिरामी लोगों को, जिनके बारे में एक दृष्टि से मैं कहता हूँ कि वे ऐसे talented व्यक्ति थे, जो अब तक इस देश और दुनिया के सामने नहीं आए थे, हम उनको प्रकाश में लाए हैं। I must sincerely thank the hon. Prime Minister.

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी देश के साथ संवाद करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी प्रधान मंत्री नेहरू जी के समय से हम देखते आए हैं कि 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, तो राष्ट्र के नाम प्रधान मंत्री जी का एक संदेश आता था और हम उसे बड़े चाव से सुनते थे। हम रेडियो लगाते थे, टीवी पर देखते थे। अब क्या हो रहा है! अब यह जरूरी नहीं कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी तक रुकें। हर महीने के अन्तिम रविवार को प्रधान मंत्री जी देश के साथ अपने मन की बात को साझा करते हैं। किसी ने आलोचना की कि यह प्रधान मंत्री के मन की बात है, तो मैं उनका ज्ञानवर्द्धन करना चाहूंगा कि यह उनके मन की बात जरूर है, मगर वे जनता से पूछते हैं कि बताइए, मैं क्या बताऊँ। इसलिए यह तो जन की बात है, जिसका केवल नाम 'मन की बात' है। इसे हम सबको समझना चाहिए। वे कई लोगों के उदाहरण देते हैं। लोगों के जो नामी-गिरामी प्रयास रहते हैं, जैसे अभी रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा उदाहरण दिया गया, ऐसी कई अनूठी कहानियाँ, उदाहरण, प्रसंग, इनका वर्णन करते हुए वे जनता को एक दृष्टि से संवाद की धारा में लाते हैं और कहते हैं, अपने मन की बात को बाँटते हैं और उनके मन की बात को भी सुनते हैं। इसके कारण संवाद की प्रक्रिया चलती है, जो मैं मानता हूँ कि इस सरकार की कार्यशैली की जो एक नीति है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

मान्यवर, हम जानते हैं कि विदेश में जाने वालों की संख्या बढ़ी है। पासपोर्ट ऑफिस में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसको तो *hastle free ... (व्यवधान) ...* नहीं, नवाचारों की बात है, तो आपको एकदम *compartmental thinking* करने की जरूरत नहीं है। Let us have a holistic approach. मैं यह कह रहा था कि हमने इसको पहले भी online के मामले में बहुत आसान किया था। गुप्ता जी, आप जानते हैं। इसलिए चीजों को आसान करना, सरल करना, मैं मानता हूँ कि पोस्ट ऑफिस को पासपोर्ट ऑफिस में तब्दील करना, इसके लिए कानून कोई ordinance लाने की या संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। लोगों की पीड़ा को जानने की, समझने की आवश्यकता थी। जब उसे समझने वाले व्यक्ति सत्ता में होते हैं, तो क्या होता है, इसके उदाहरण इन निर्णयों के द्वारा हमारे सामने आते हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आपको राज्यों में भी जो हो रहा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब केन्द्र सरकार इतना बढ़िया काम करती है, तो प्रेरणा जिस तरीके से रिसाव होकर नीचे तक जाती है, उससे राज्यों में भी एक प्रेरणा बनती है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था - *Per drop, more crop*. पानी की किल्लत, पानी की समस्या, खेती के लिए पानी की अनुपलब्धता, हम दुनिया भर की बातें वर्षों से सुनते आए हैं, मगर पहली बार यह हुआ है, आप कृपया सुन लीजिए, पहली बार यह हुआ है कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, कई राज्यों में *water table* बढ़ाने के लिए बहुत कारगर प्रयास हुए हैं। इसके लिए महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार योजना शुरू हुई, यहाँ पर भामाशाह योजना शुरू हुई। यह कोई बेवजह नहीं है कि मध्य प्रदेश में खेती की जो विकास दर है, वह एकदम 18, 19, 20 परसेंट तक हो गई है। There is some reason behind it. वहाँ यह जो सिंचाई की व्यवस्था हो गई, जो *water-table* बढ़ा, जो नदियों को जोड़ने का प्रयास हुआ, मैं मानता हूँ कि यह सब कारगर ढंग से तभी होता है, जब केन्द्र में नेतृत्व करने वाली सरकार विकास की एक सोच लेकर, एकदिशा में, 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र लेकर आगे बढ़ने के इरादे से काम करती है।

मान्यवर, एक बार लोग पुनः कहेंगे कि आप बजट के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, मगर मुझे मोह हो रहा है और उसका कारण भी है। मैंने इससे पहले भी बजट के कई भाषण सुने। मैं सोच रहा था

कि कहीं किसी ने इसका उल्लेख भी किया है या नहीं किया है, मगर जब हम क्रियान्वयन की बात करते हैं, तो क्रियान्वयन हवा में नहीं होता है, जमीन पर होता है। जब सामाजिक विकास की बात आती है, तो विकास का मतलब केवल infrastructure का विकास नहीं होता है। वह महत्वपूर्ण तो है, but, that is not just development. जब माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में IMR और MMR को कम करने की बात करते हैं, ऐसे में सामाजिक विकास के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसको और अधिक प्रकाश में लाने की आवश्यकता नहीं है। It is very clear to everybody.

सर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक महत्वपूर्ण पहलू और है, जिसके ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है बार-बार होने वाले चुनाव। उन्होंने simultaneous elections की बात की है। इसके बारे में इस सदन के अंदर और इसके बाहर कई बार चर्चा हुई है। माननीय आडवाणी जी ने भी एक बार कहा था कि यह देश ऐसी स्थिति में है कि we are in a perennial election mode. हर वक्त कहीं न कहीं पर कोई छोटा चुनाव या कोई बड़ा चुनाव हो रहा होता है। चुनाव की राजनीति का बोझ या pressure, जो सत्ता में बैठे हैं अथवा जो विपक्ष में बैठे हैं, सभी लोगों पर होता है। बार-बार चुनावों के कारण पैसे की बरबादी होती है, इस बात को तो हम सब जानते हैं। इसके कारण समय भी बरबाद होता है। अभी हम देख रहे हैं कि पहले इस सदन का कार्यकाल चलता था, लेकिन अब बीच में थोड़ा अवकाश है, क्योंकि बहुत सारे लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सदन की उपस्थिति पर भी उसका असर है। इसमें पैसे की बरबादी होती है, समय बहुत लगाना पड़ता है और लोक-लुभावन वायदों से भी हम खुद को बहुत ज्यादा मुक्त नहीं रख पाते, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में एक समानान्तर पद्धति से, समन्वित प्रयासों के माध्यम से, simultaneous election करवाने की बात माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़े आग्रह के साथ रखी है, जिसका विस्तृत उल्लेख माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सभी मान्यवरों से अवश्य अपील करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण democratic reform है, जिसको इस देश की जनता हम सबसे मांग रही है। मैं मानता हूँ कि हमें जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए और simultaneous election को पूरा समर्थन देना चाहिए। अगर आने वाले दो-चार वर्षों में हम इसको क्रियान्वयन में ला पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोगों के द्वारा इस देश की जनता की बहुत बड़ी सेवा हो पाएगी।

माननीय उपसभापति जी, मैं अंतिम बिन्दु पर आ रहा हूँ और वह है क्रियान्वयन। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में, भाषणों में, नारों में, इरादों में बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, मगर जैसा कहते हैं कि शक्कर का स्वाद उसको खाने के बाद ही पता चलता है, वैसे ही आपके इरादे कितने अच्छे हैं, जब तक वे जमीनी धरातल पर नहीं उतरते, जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक उनके बारे में पता नहीं चलेगा। यह सरकार ऐसी सरकार है, जो क्रियान्वयन पर बल देती है, सबसे क्रियान्वयन का हिसाब-किताब मांगती है।

देखिए, प्रधान मंत्री बहुत आए, Administrative Reforms Commission की बहुत सारी reports आईं, संवैधानिक परिवर्तन भी हुए, मगर मैं एक प्रधान मंत्री ऐसा देख रहा हूँ, जो योजनाओं के क्रियान्वयन में विश्वास रखता है। यह मैं flatter करने के लिए या प्रशंसा के पुल बांधने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको हकीकत के रूप में बता रहा हूँ कि विगत दो सालों में जो प्रगति योजना शुरू हुई है,

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

उसका वर्णन हम टीवी पर देखते रहते हैं। प्रधान मंत्री जी बैठते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज बैठते हैं, सामने स्क्रीन पर एक-एक राज्य का मुख्य सचिव आता है और उससे हिसाब-किताब मांगा जाता है कि भई, आपने यह कहा था कि आप इस काम को तीस दिनों में करेंगे, तो यह क्यों नहीं हुआ? अगर यहां का काम नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और अगर वहां का काम नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? There is some accountability now, तब जाकर good governance होता है। Good governance कोई नारा नहीं है, good governance has to be a part of our experience. We are trying through all our efforts to bring good governance at the experimental level. यह अनुभव की बात होनी चाहिए। यह केवल खोखला नारा नहीं है। इस सुशासन को मुहैया करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसका रहस्य कहां है? मैं मानता हूँ कि उसका रहस्य एक sense of purpose में है। सत्ता की राजनीति, सत्ता में आना, मंत्रिमंडल में आना, लाल बत्ती वाली गाड़ी, बंगले और लुटियंस का सारा वातावरण, यह सब बहुत ही आकर्षक है, मगर क्या हम केवल उसके लिए सत्ता में आए हैं? Are we not supposed to convert the democracy into delivering democracy?

I think, this Government is convinced that that is our objective, that is our aim and, therefore, this Government, let me tell you, after so many decades, has brought a robust sense of purpose to the very process of democratic governance which is the most important contribution of this Government. उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस वातावरण को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए सरकार के प्रति भी एक ओनरशिप बढ़नी चाहिए और ओनरशिप बढ़ाने का प्रयास MyGov के माध्यम से हुआ है। जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी, तब तो लोगों को अपनी सरकार है, ऐसा लगता नहीं था और बाद में जो सरकारें आईं उन्होंने भी अपनापन सृजन करने की बहुत सारी कोशिशें नहीं कीं और उसके कारण सरकार और जनता, रूल्ड एंड दि रूलर्स, इनके बीच में हमेशा एक अन्तर रहता आया है।

महोदय, मैं मानता हूँ कि इस सरकार ने MyGov के माध्यम से सहभागिता को बढ़ाते हुए जितने सारे प्रयास किए हैं, उसके कारण इस अन्तर को मिटाने की एक बहुत सार्थक कोशिश हो रही है। इस वातावरण को यदि बढ़ावा देना है, तो कई सारी जो विभाजनकारी चीजें आती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। मैं अभी बंगलादेश गया था। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी भी हमारे साथ थे। हम एक डेलीगेशन में गए थे। हम ढाका यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमें बताया कि यहां का हर डिपार्टमेंट सरस्वती पूजा को एक उत्सव के रूप में मनाता है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल के एक क्षेत्र में सरस्वती पूजा को लेकर एक बवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए।

महोदय, हमने "सब का साथ, सब का विकास" का जो नारा दिया है, जो एक मंत्र दिया है, उसके आधार पर हमें सब को लेकर विकास की इस यात्रा में सबको सहभागी बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज यह देश की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर "तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें", इस भाव से भारत माता की सेवा में जुट जाएं। इस काम में जुटी हुई सरकार और इसके कामों के प्रति अपनी भावना को दर्शाने वाला माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं पूरी ताकत से समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Sahasrabuddhe. Thank you very much. Now, hon. Members, the Motion that has been moved and seconded is that an Address be presented to the President in the following terms: –

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2017."

Now, there are 651 Amendments to the Motion and I will call the names. Those who would like to move can move now. Amendments (Nos.1 – 59) are in the names of Shri Vishambhar Prasad Nishad, Ch. Sukhram Singh Yadav, Dr. Anil Kumar Sahani and Shrimati Chhaya Verma. Any one of them move it.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

1. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के किसानों का सभी फसलों की लागत मूल्य से अधिक कीमत दिलाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

2. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेती में प्रयोग होने वाले नई प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों, बीजों और अन्य संसाधनों को नियंत्रित मूल्य पर किसानों तक मुहैया कराने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

3. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लगातार अलाभकारी होती खेती के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के उपायों की जानकारी नहीं है।"

4. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलाभकारी होती कृषि के कारण गांवों से पलायन रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

5. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि-क्षेत्र में घटते रोजगार के अवसरों को बढ़ाए जाने की जानकारी नहीं है।"

6. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेती योग्य भूमि का लगातार घटते रकबे को स्थिर बनाने या रकबा बढ़ाने की योजना की जानकारी नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

7. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीज़ल व मिट्टी के तेल की कीमतों में आए दिन बढ़ोत्तरी से किसानों को सिंचाई हेतु दर बढ़ोत्तरी के प्रभाव से मुक्त कर नियंत्रित दर पर डीज़ल उपलब्ध कराने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

8. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खेती भूमि की सिंचाई प्रणाली को और दुरुस्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

9. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की कमी को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

10. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

11. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सरकारी नौकरी पाने की आयु से ऊपर निकल चुके बेरोजगार पढ़े-लिखे शिक्षित नागरिकों को रोजगार के अवसरों के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

12. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों के विकास के लिए पंचायतों हेतु आबंटित धनराशि में बंदरबाट को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

13. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरे वर्ष काम मिले, इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।"

14. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के समस्त नागरिकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सुविधा (सीजीएचएस) की तय सरकारी दरों के समान आम नागरिकों के इलाज हेतु अस्पतालों एवं जांच केन्द्रों को शुल्क लेने की बाध्यता, जिससे आम नागरिक भी कम दर पर अपना इलाज करा सके, के संबंध में जानकारी नहीं है।"

15. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों की रखरखाव को और सुदृढ़ करने तथा नये गोदामों के निर्माण हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

16. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ा कर निजी स्कूलों के समान लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
17. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्यालयों से बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ने की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
18. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत व अभेद्य बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
19. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे-शहरों, कस्बों तक औद्योगिक प्रगति और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
20. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
21. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार एवं अन्य कारणों से गांवों की ओर से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
22. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोटबंदी के बाद धीमे पड़े उद्योग-धंधों को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
23. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र के कामकाज को गति देने जिससे पुनः असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रोजगार का अवसर मिल सके, के दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
24. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों से अपनी जमा राशि के इस्तेमाल के अधिकार को पुनः बहाल करने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
25. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोटबंदी के बाद देश में बेरोजगार हुए नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

26. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी के लिए देश के सरकारी बड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों को समय से इलाज हेतु उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

27. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में चल रही पोंजी योजनाओं जिनसे नागरिकों को गुमराह कर उनकी मेहनत की धनराशि हड़प करने वाली पोंजी योजनाओं की रोकथाम या उनको देश के कानून के दायरे में लाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

28. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली सहित देश के महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के मानक के अनुरूप लाने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

29. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूरी तरह रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

30. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय रेल की लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर विराम लगाने हेतु उठाए जाने वाले सार्थक कदमों की जानकारी नहीं है।"

31. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों के लगातार बढ़ रहे एनपीए को कम करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

32. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि कार्य हेतु बैंकों द्वारा कर्ज को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

33. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिक्त पड़े विभिन्न शिक्षकों के पदों को भरने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

34. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर नियुक्तियों को समय पर भरने में हो रहे विलंब को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

35. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी तथा अगले पंचवर्षीय योजनाओं पर उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।

36. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबों के लिए चलाए जाने वाले योजनाओं में आंकड़ों के आधार पर समावेश हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

37. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन का मापदण्ड निर्धारित करने और सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

38. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से पूरी तरह नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

39. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ते या भूलवश जल सीमा के पार गए भारतीय मछुआरों को पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा पकड़ने की घटनाओं के शीघ्र समाधान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

40. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोटबंदी के दौरान ऑनलाइन लेन-देन पर छूट के बावजूद विभिन्न बैंकों द्वारा वसूले गए चार्ज को उपभोक्ता/खाताधारकों के खाते में वापस दिलाए जाने के बारे में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

41. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की उच्च न्यायिक व्यवस्था में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है जिससे मुकदमों को शीघ्र निपटा कर समय पर नागरिकों को न्याय मिल सके।"

42. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नये जाली नोटों की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

43. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोटबंदी से काले धन की प्राप्ति की संतोषजनक जवाब न देने से उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
44. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली क्षेत्र में लगातार यमुना नदी के सिकुड़ते आकार और यमुना नदी के पानी में बढ़ते जहरीले तत्वों की समस्या से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
45. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नोटबंदी के दौरान देश के विभिन्न बैंकों से किसानों के कर्ज की ब्याज राशि को माफ करने की जानकारी नहीं है।"
46. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन पर किए गए वायदे के अनुरूप नागरिकों के खाते में अभी तक 15 लाख रुपए लाए जाने की दिशा में जानकारी नहीं है।"
47. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन द्वारा हड़पी गई भारतीय क्षेत्र को पुनः भारतीय परिधि में लाए जाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
48. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
49. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के किसानों के फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"
50. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुशल कामगारों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों के देश से पलायन रोकने हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
51. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लगातार बढ़ रहे अमीरों एवं गरीबों की खाई कम करने की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
52. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मानव तस्करी रोकने की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

53. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मशीनों का सीमित उपयोग जिससे बेरोजगारी कम हो, की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
54. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलाभकारी होती कृषि लागत मूल्य कम करने की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
55. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले सार्थक कदमों की जानकारी नहीं है।"
56. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचारों-दुराचारों को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।"
57. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ई-वेस्ट के उचित निपटारे हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
58. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विलुप्त हो रहे वन्य संपदा के संरक्षण हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
59. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्ट अफसरों को दण्डित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos.60 - 78) by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

60. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुन्देलखण्ड में कई वर्षों से पड़ रहे सूखे के समाधान हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"
61. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भेजे गए प्रस्ताव को मानते हुए उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु उल्लेख नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

62. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इंदिरा आवास योजना की धनराशि उ.प्र. सरकार की तरह 70 हजार से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने जैसे प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

63. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुंदेलखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

64. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुंदेलखण्ड के नागरिकों को प्रति वर्ष सूखे के कारण आने वाली दिक्कतों के समाधान हेतु अतिरिक्त राशन, आवास, पीने योग्य पानी एवं खेती के लिए किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

65. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलाभकारी कृषि को देखते हुए सभी किसानों और वृद्धों को कम से कम 1000 रुपया पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।"

66. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के निवासियों के पलायन को रोकने के लिए उक्त क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानकारी नहीं है।"

67. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सुरक्षा सेना के तीनों अंगों में बाढ़ जैसी दैवीय आपदा से निपटने हेतु जन्मजात मछुआ समुदाय के नौजवानों को भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।"

68. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि गंगा सहित महत्वपूर्ण सभी नदियों के सफाई अभियान में नदी किनारे निवास करने वाले मछुआ समुदाय के नाविकों को 50 फीसदी आरक्षण भर्ती में प्रदान किया जाए।"

69. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में द्रोणाचार्य पुरस्कार की तरह एकलव्य पुरस्कार दिए जाने का जिक्र नहीं है।"

70. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि देश की नदियों, तालाबों की नीलामी समाप्त कराकर प्री फिशिंग की सुविधा दी जाए।"

71. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि चित्रकूट मण्डल के सभी तालाबों, जलाशयों में मौजूद सिल्ट की सफाई कराकर इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता को वर्षा जल द्वारा तालाबों एवं जलाशयों में अधिक जल एकत्रित करने की किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

72. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि केंद्र को बुंदेलखण्ड में किसानों से ऋण वसूली समाप्त कर कर्ज माफ करना चाहिए तथा कृषि हेतु खाद, बीज और बिजली मुफ्त प्रदान की जानी चाहिए।"

73. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि बुंदेलखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु बजट में 50000 हजार करोड़ की अतिरिक्त सहायता दी जाए।"

74. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि 11069/11070 तुलसी एक्सप्रेस प्रतिदिन करने तथा 14009/14110 चित्रकूट कानपुर एक्सप्रेस को कानपुर से बढ़ाकर लखनऊ तक चलाई जाए।"

75. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि बुंदेलखण्ड में पलायन को रोकने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए।"

76. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि बुंदेलखण्ड के जनपद बांदा में औगासी ग्राम के पास यमुना नदी पर तटबंध बनाकर यमुना नहर निकाली जाए।"

77. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में यमुना नदी पुल के पास से महेश्वरी मंदिर तक तटबंध बनाने तथा केन नदी से बांदा जनपद के ग्राम कनवारा छावनी डेरा ब्रह्मा डेरा तथा चटगन, पथरी, चटगन, छेरांव, मरौली, कयोटरा, अछरोड़, खट्टिहाकला, पैलानी सिन्धनकला, सांडी, खैरेई आदि बाढ़ पीड़ित बस्तियों को ऊंची जगह बसाने तथा तटबंध बनाने तथा हमीरपुर के रागौल गांव में बस्ती को कटान से बचाने हेतु बड़ेरी नाला पर तटबंध बनाए जाएं।"

78. कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि ट्रेन 18203/18204 बेतवां एक्सप्रेस को कानपुर से दुर्ग के बीच प्रतिदिन चलाए जाने तथा ट्रेन 12535/12536

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

गरीब रथ को प्रतिदिन चलाने तथा ठहराव रागौल स्टेशन पर कराने का तथा ट्रेन नम्बर 12427/12428 रीवांचल एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर से बांदा होते हुए रीवां तक चलाई जाए।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.79 – 80) by Shrimati Chhaya Verma.

SHRIMATI CHHAYA VERMA (Chhattisgarh): Sir, I move:

79. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken to improve upon the conditions due to not issuing of scheduled castes to the Dhanuwar caste in Chhattisgarh owing to the anomalous policies of the Government."

80. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any action plan to deal with problems being faced by the passengers of Chhattisgarh particularly Raipur as the Bilaspur Rajdhani train does not run on daily basis."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos.81 –89) by Shri Sitaram Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I move:

81. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret at that there is no mention in the address about condoling or noting the tragic death of over 100 people and announcing adequate compensation to the families of those who lost their lives while standing in queue to withdraw their own hard earned money from banks/ATMs."

82. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about what did we get from the note demonetisation."

83. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that how much black money was recovered from the note demonetisation."

84. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the severe drought situation faced by the States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, parts of Telangana and Andhra Pradesh and Union Territory of Puducherry."

85. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing economic burden on the people, whether the industrial manufacturing production has shown a decline, the energy sector is in crisis indicating significant industrial slow down, rising unemployment, agrarian crisis is deepening, vast section of people are deprived of even meagre relief through legal entitlement."

86. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in the prices of all essential commodities."

87. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the abnormal increase in the prices of petrol and diesel causing much hardship to the people."

88. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about empowerment of backward communities minorities, scheduled castes, scheduled tribes and women in the country."

89. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any effective step for making public distribution system universal, effective and people oriented."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.90 – 97) by Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I move:

90. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the grant of Special Category status to the residuary State of Andhra Pradesh in spite of the fact that the assurance was given by the then Prime Minister on the floor of Parliament on 20th February 2014."

91. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to fulfill the assurance given to the successor or State of Andhra Pradesh that package for backward areas would be given on the lines of Bundelkhand area and KBK districts in Odisha."

[Shri V. Vijayasai Reddy]

92. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to Address the anomalies under sections 50, 51 and 56 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 that relate to recovery - of arrears of taxes or duty on property, including arrears of land revenue."

93. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the commitment of the Indian Railways, as mandated in paragraph 8 under the head 'Infrastructure', of Thirteenth Schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, to establish a new Railway Zone in the successor State of Andhra Pradesh with Vishakhapatnam as the Zonal Headquarter."

94. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the timeframe to complete the Polavaram National Project in Andhra Pradesh."

95. That at the end of the Motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address fails to mention about setting up of a separate High Court for the State of Andhra Pradesh in a time-bound manner."

96. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mentions how and by when Government is going to divide 107 common institutions between AP and Telangana listed under Schedule X to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014."

97. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Government is committed to securing greater participation of women in the Parliament and State."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.98 – 121) by Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I move:

98. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing incidents of atrocities on people of Dalit communities in the country."

99. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to repeal the archaic sedition law which is not needed in the democratic India."

100. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of attempt to take away the land rights of tribals given under the Forest Rights Act to facilitate coal mining in certain tribal villages."

101. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to enact a central legislation for the welfare and security of the agricultural workers in the country."

102. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the attempts being made by the government to curtail trade union rights of the workers in the name of ease of doing business."

103. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the prevailing crisis in the agriculture sector and increasing incidents of farmers committing suicide in the country."

104. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the abnormal increase in the Non-Performing Assets (NPAs) of the public sector Banks and writing off a total ₹ 1.14 lakh crore of bad debts between the financial years 2013 to 2015."

105. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the continuous slow down in the growth rate of economy."

106. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the continuous decline in India's export during the last 15 months."

107. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its serious concern over the delay in passing the legislation on reservation of women in the Parliament and State Assemblies."

[Shri D. Raja]

108. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating quality of education particularly at the higher level in the country."

109. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education to the common people."

110. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating condition of the public health facilities in the country compelling the poor patients to avail medical treatment from costly private medical institutions."

111. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the increasing incidents of crime against women and children in the country."

112. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to solve the problem of unemployment particularly of the educated youth in the country."

113. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to pay sustainable wages to the Anganvadi and Asha workers in the country."

114. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the increased attacks on the tribal people in the country particularly in Chhattisgarh."

115. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the fact that the decision of demonetisation of currency notes of ₹ 500 and ₹ 1000 denominations pushed the economy as well as the common people into a distressful condition."

116. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the fact that certain right wing forces in the country are trying to destroy the secular-democratic fabric of the

country by attacking the Universities, all educational and cultural institutions, freedom of speech, right to dissent, minorities, dalits, tribals and progressive activists."

117. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its concern over the diversion of allocations made for sub-plans for SCs and STs."

118. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does mention about the increasing number of derailments of trains due to deterioration of safety standards of the Indian Railways and ignoring the recommendations of various reports on accidents in the Railways."

119. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the continued protest of the Ex-service men demanding full implementation of the One Rank, One Pension (OROP)."

120. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fact that thousands of villages still remain without electricity in the country."

121. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fact that ₹ 653 crore scheme for safety of women on public transport and ₹ 79.6 crore Nirbhaya project devised in the year 2015-16 for the safety of women still remain unutilized whereas the attacks on women goes on unchecked."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.122 – 186) by Shri Ritabrata Banerjee.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I move:

122. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the sufferings of the innumerable Indians due to the process of demonetisation."

123. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the deaths of more than hundred people due to demonetisation."

[Shri Ritabrata Benerjee]

124. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the amount of black money recovered from foreign countries."

125. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the misuse of Jandhan Accounts for deposition of large sums of money after demonetisation was announced."

126. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the sufferings of lakhs of people who have lost their money in the Sarada, Rose Valley and other Chit Fund scams."

127. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the suicides of 123 people cheated in the Sarada Chit Fund scam in West Bengal."

128. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the starvation deaths in the tea gardens of West Bengal."

129. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the number of train accidents occurring in the last five months."

130. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the large number of posts lying vacant in Railways related to Railway Safety."

131. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the increasing incidents of rape, attack and atrocities on women in West Bengal in the last few years."

132. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the severe drought situation faced by the States of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, parts of Telangana and Andhra Pradesh and Union Territory of Puducherry."

133. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in the prices of all essential commodities."

134. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the abnormal increase in the prices of petrol and diesel causing much hardship to the people."

135. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about empowerment of backward community, minorities, schedule castes, scheduled tribes and women in the country."

136. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure in adequately identifying the BPL section of the population."

137. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to tackle the huge unemployment problem in the country."

138. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

139. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective steps in strengthening the Non-aligned Movement."

140. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to release Indians languishing in jails in various countries."

141. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about loss of lakhs of jobs in India during the last three years."

[Shri Ritabrata Benerjee]

142. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Government's failure to review the Centre-State relations as per the demands of the State Governments."

143. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to allot six per cent of GDP in education."

144. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to invest enough money in public sector and social sectors."

145. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need for drastically revising and/or correcting the official definition of 'poverty line' which has become totally obsolete."

146. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret the Address fails to mention about the innumerable cases of distress suicides by the farmers during the last few years in various parts of the country."

147. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the huge irregularities in the Government's Farm Debt Waiver Scheme in which substantial portion of loan was extended to Micro Finance institutions."

148. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take serious steps on the disastrous impact of global slow down on millions of workers who have lost their jobs, livelihood and earnings due to closure, lay off, wage-cuts, retrenchment, etc., in various sectors."

149. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any special package for the special category States to enable them to narrow down regional disparities."

150. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about a one-time Debt Relief Package by writing off all the outstanding Central Government loans including interest thereon of the North-Eastern States."

151. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any scheme for employment for unemployment youth of the Special Category States."

152. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any comprehensive legislation for the welfare of agricultural workers in the country."

153. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps taken to expedite land reforms in the country."

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about universalisation of Integrated Child Development Scheme."

155. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take steps for the development of under-developed remote villages."

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to supply coal according to the needs of power plants in the country."

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective steps to provide universal right to at least 35 kg of foodgrains at two rupees a kilo."

158. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective steps to stop the crimes against women and children."

[Shri Ritabrata Benerjee]

159. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective measures to check the malnutrition among the women and children in our country."

160. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the demand of universalisation of public distribution system and a complete ban on speculation and futures trading in the commodity market."

161. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punishment for violation of labour laws."

162. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the universal social security for the unorganized sector workers and creation of a National Social Security Fund with adequate resources as per the recommendations of the National Social Security Board for Unorganised Workers."

163. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fail to mention the failure of the Government to safeguard and promote the livelihood of street vendors."

164. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fail to mention the failure of the Government to take effective measures to eradicate Child Labour from the country."

165. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fail to mention the failure of the Government to liberalize the educational policy to access higher education to all, irrespective of their paying capacity."

166. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the emergence of paid news that has been a dangerous phenomenon in media world distorting parliamentary democracy."

167. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to develop efficient water transport in the country."

168. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective steps to provide the life saving medicines at subsidized rate."

169. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to fix statutory minimum wage at not less than ₹ 10,000 to 15,000."

170. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the removal of all ceilings on payment and eligibility of Bonus, Provident Fund and increase the quantum of gratuity."

171. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to assure pension for all."

172. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the compulsory registration of trade unions within a period of 45 days and immediate ratification of the ILO Conventions Nos. 87 and 98."

173. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the all-round hike in rail fares."

174. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps taken to curb the alarming rise in the atrocities on Dalits, SCs and OBCs in the country."

175. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the filling up of one million vacancies under various Government establishment, departments, Railways, PSUs and Banks and Insurance Sectors, etc."

[Shri Ritabrata Benerjee]

176. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the provision for relief and financial, technical and logistical support for the scientific farming of various agriculture crops."

177. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the deplorable condition of the Indian agriculture and about the farmer's suicide which has risen 26% during the tenure of this Government."

178. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the NPAs caused by the large industrial houses."

179. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about burning issue of the common people, i.e. uncontrolled inflation of essential goods and services and inadequacy of the social security network."

180. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about how many centralised sponsored schemes have been renamed and how many of the old schemes have been merged with the new schemes."

181. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any financial and technical encouragement of traditional industries such as handloom bamboo, mat weaving, fisheries, handicrafts etc."

182. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the reservation and protection of public lands and promotion of sports facilities at grass root level."

183. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the need to increase protein consumption of children and the pregnant women and for free provision of sufficient quota of pulses, cooking oil, sugar to the schools as well as *anganwadies*."

184. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing menace of various signs of intolerance *i.e.* communal religious, social and political."

185. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about growing attacks on the media persons and the whistleblowers."

186. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention about the extreme difficulties faced by the Indian athletes in the Rio Olympics due to the negligence of the Government."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.187 – 545) by Shri Sanjay Seth.

SHRI SANJAY SETH (Uttar Pradesh): Sir, I move:

187. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about poverty alleviation and tackling unemployment."

188. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about eradication of corruption from the country."

189. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about elimination of economic disparity."

190. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about controlling the growing population."

191. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to check the crimes which are increasing rapidly from petty to heinous crimes."

192. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about development of rural areas."

[Shri Sanjay Seth]

193. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing electricity at reasonable cost to farmers."

194. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing unemployment allowance to educated unemployed youths."

195. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need of balanced economic development in the country."

196. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need of land reforms in the country."

197. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking concrete steps regarding unprecedented increase in prices of essential commodities."

198. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about controlling the increasing number of sick units in small scale industries."

199. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about preparing a time-bound programme for elimination of bonded labour in certain parts of the country."

200. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about controlling the problem of increasing pollution the country."

201. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about preparing an Action Plan at national level for land conservation in the country."

202. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about current international scenario and discussing Government's policy thereon."

203. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about checking the menace of malnutrition in the country."

204. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about appropriate policy to counter actual condition and deteriorating political, economic and social conditions."

205. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any measure to assess accurately the number of people living below poverty line."

206. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making appropriate reforms in present education system and making it employment oriented."

207. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about welfare measures for people living in slums."

208. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about reducing exorbitant fee hiked by public schools, engineering colleges and medical institutes."

209. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about availability of drinking water in backward and rural areas of the country."

210. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating a comprehensive scheme to create more employment opportunities in rural areas to resolve increasing unemployment there."

211. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating an effective scheme for the welfare of landless labourers."

212. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing Environment as compulsory subject at primary level in schools."

[Shri Sanjay Seth]

213. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making Sanskrit as compulsory subject in primary and high school curriculum."

214. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishing a well-equipped technical college for students belonging to backward, poor and Scheduled Castes in each district of the country."

215. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about ensuring reservation for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in admission in educational institutes and other professional institutes."

216. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing basic facilities to schools in the country especially in backward and rural areas where proper building and adequate number of teachers are not available and school buildings are in dilapidated condition."

217. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing computer based education system in rural areas."

218. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing compulsory and free and cost education to all categories in the society in the country."

219. TThat at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening a residential school in each Development Block for promoting girl education at primary level."

220. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about constituting Monitoring committees at tehsil and district level for the success of Sarva Siksha Abhiyan and ensuring participation of Members of Parliament in these Committees."

221. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing free of cost education to all children up to graduation level without gender discrimination."

222. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about implementing new education policy for masses in the country."

223. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the effective implementation of Land Reforms Act and distribution of surplus land to Landless People."

224. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the sweeping land reforms for the welfare of landless and the poor people."

225. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of various schemes for the transformation of barren lands into arable land through time-bound scheme."

226. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the formulation of action plan on national level for the conservation of land in the country."

227. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the expeditious implementation of the multi-purpose national identify card scheme in the country."

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing special assistance to the para-military forces for the purpose of buying vehicles, states of the art communication technology and ammunition in order to keep vigil on the border and to check infiltration."

229. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the balanced development of rural areas."

230. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing shelters, employment and food to the families living below poverty line in the backward and rural regions of the country."

[Shri Sanjay Seth]

231. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does "not mention about the inclusion of ideals and teachings of great saints and great persons of India like Swami Dayanand Saraswati, Sri Ram Krishhna Paramhans and Swami Vivekanand in the educational syllabus and especially in the syllabus of History in lieu of the stories of Kings."

232. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the conservation of such cultural heritage and vedic traditions of the country which have saught lessons of devotion towards gurus, fraternity and services to the parents to the entire world."

233. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the eradication of social evils like feast given on death."

234. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the eradication of dowry system in the country."

235. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about stopping smoking."

236. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about prohibiting drinking."

237. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about promoting remarriage of widows."

238. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the effective implementation of Yamuna Action Plan."

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to check the discharge being own by the chemical factories directly into the Ganges, the Yamuna, the Narmada, the Sabarmati, the Tapti, the Gandak, the Kosi, the Chambal, the Ghaghra, the Jhelum, the Godavari, the Krishna, the Kaveri rivers."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about draining out garbage, contaminate water into the major rivers of the country—Ganges, the Yamuna, the Gomati, the Narmada, the Sabarmati, the Tapti, the Gandak, the Kosi, the Chambal, the Ghaghra, the Jhelum, the Godavari, the Krishna, the Kaveri."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the assessment of volume as well as the names of harmful elements present in the major rivers of the country, especially the Ganges, the Yamuna, the Gomati, the Narmada, the Sabarmati, the Tapti, the Gandak, the Kosi, the Chambal, the Ghaghra, the Jhelum, the Godavari, the Krishna, the Kaveri."

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures taken for the conservation and erosion of the major rivers of the country especially the Yamuna, the Gomati, the Narmada, the Sabarmati, the Tapti, the Gandak, the Kosi, the Chambal, the Ghaghra, the Jhelum, the Godavari, the Krishna, the Kaveri in order to maintain the existence."

243. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing relief to the people of the villages residing at the bank of the Yamuna who are suffering from the spread of lethal diseases like cancer, kidney, failure, heart attack, lever failure, blood pressure, hepeticitis due to the contamination of ground water."

244. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making contamination free ground water of the villages situated on the banks of the Ganges, the Yamuna, the Gomati, the Narmada, the Sabarmati, the Tapti, the Gandak, the Kosi, the Chambal, the Ghaghra, the Jhelum, the Godavari, the Krishna, the Kaveri."

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing profitable value to the paddy growers of their produces."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing proper treatment facilities to the people suffering from cancer in the country in order to check the increasing number of such patients and to provide treatment."

[Shri Sanjay Seth]

247. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fully implementation of the report of the Dr. Swaminathan Agricultural Commission so far."

248. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the incessant downfall in the number of the animals in the country and making the medows free from the unauthorised occupation."

249. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about stopping the migration of people from the rural areas and promoting the cottage and small scale industries along with promoting the export of the manufactured goods."

250. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the deployment of scientists for the purpose of checking the all perennial rivers from the pollution and light security arrangement in each region."

251. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the inclusion of syllabus regarding ethical values in primary, secondary and higher education."

252. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing all facilities to the agricultural labourers of unorganized sector in the country."

253. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention providing grants and technical facilities to the Indian craftsmen for the manufactured goods and promotion of there exports through the cottage and small scale industries."

254. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention making the punitive provisions more rigorous for the offences like, misconduct, rape and other such heinous crimes committed against Women."

255. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about abolition of racism, lingualism and regionalism in the country."

256. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about abolition of superstitions and other social evils in the country."

257. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the welfare of the cotton mill labourers."

258. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of the various schemes for the transformation of barren land into arable land in a time-bound manner."

259. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the checking of steep price rise of petroleum products from time to time and also to bring down their, prices."

260. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the formulation of national level action plan for the water conservation."

261. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about functioning of Khadi and Village industries Commission with a view to make it more result Oriented and productive."

262. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing time bound programme for imparting free and compulsory primary education to every child in his her mother tongue."

263. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about checking the malpractices prevalent in the administration."

264. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about checking the continuous brain drain from various sectors."

[Shri Sanjay Seth]

265. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of new tourism policy showcasing Indian Culture and tradition in Proper light."

266. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about giving loans the poor, deprived, unemployed youth, labourers and marginal farmers by banks and financial institutions and to overcome the short comings in the policy adopted for recovery of those loans."

267. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a time bound programme for eradication of child labour in the country."

268. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about checking the increasing incidents of atrocities on women and children in the country."

269. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking effective steps for eradication of begging."

270. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about recurring floods in various - parts of the country and taking excessive river water to drought prone areas and also for preparation of a comprehensive plan to control floods in large tracts of land."

271. That at *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing fast economic and corruption free justice to the poor in the country."

272. That at *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of private or public sector industries in backward and rural areas of the country."

273. That at *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about increasing the broadcasting capacity of All India Radio and Doordarshan in backward and rural areas of the country."

274. That at *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about lack of effective implementation of land Reform Act and non distribution of surplus land among the landless."

275. That at *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about excessive increase in killings of the old aged persons, women and children in metros of the country and proper security for them."

276. That at *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing remunerative price to the farmers for their produces."

277. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about development of small and cottage industries."

278. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about connecting villages to nearby towns and cities with non-metalled/metalled roads."

279. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of tribunals for obviate the delay injustice and for quick delivery of justice."

280. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making any effective plan to make country's historical monuments pollution-free."

281. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing telecommunication services in country's backward and rural areas on priority basis."

282. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making any plan for power allocation to the States."

283. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about reduction in the expenditure on publicity, advertisement, hospitality, catering, inaugurations, seminar,

[Shri Sanjay Seth]

conference, travels. STD/ISD telephone bills and other office expenses by Central Ministries, departments and undertakings."

284. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about Providing adequate medical facilities in the country, keeping in view its population."

285. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the release of Indian prisoners of war from Pakistani prisons."

286. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-refunding of loans given to Uganda, Tanzania, Kenya, Sudan and other countries by the Govt. of India."

287. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about Installation of high power TV transmitter in border areas to check anti-India campaigning on Pakistani television."

288. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on brutal deaths of boys/girls students caused due to alleged ragging in engineering colleges, medical colleges and other educational institutions, and inhuman behaviours with them."

289. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on rapidly depleting water level in the country."

290. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about approval of *pending* irrigation projects."

291. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing basic civil facilities in slum clusters situated in metropolitan cities and towns."

292. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about Making a National Livestock policy."

293. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about reducing fiscal deficit."

294. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about rehabilitation of workers rendered jobless because of closure of textile units."

295. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about development of handicraft."

296. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about not supplying of coal to country's thermal power stations in keeping with their demands."

297. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the development of country's tourist spots to attract domestic and foreign tourists throughout the year."

298. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about not bringing any change in income tax structure."

299. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about Increasing Central investment and its overall progress."

300. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the growing crisis in country, because of poverty, disparity in income and price rise."

301. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the need for fresh initiatives to be taken by the government to fulfil hopes and desires of poor people."

302. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about public sector undertaking closing down owing to declining economic condition in the country."

[Shri Sanjay Seth]

303. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but-regret that the address does not mention about making the timely medical facilities available to persons afflicted with Hepatitis-B, Tuberculosis, HIV, kidney and heart related ailments and poverty borne disease in the country."

304. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about formulating a plan for promotion of primary education, secondary education and higher education."

305. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the measures to be adopted for enhancing the production of foodgrains, pulses and edible oils commensurate with growing population in the country."

306. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the steps taken to keep the spiralling prices of potato, onion, edible oils, pulses and other essential commodities under check in the country."

307. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the need to take effective steps to curb adulteration, bribery and black marketing."

308. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about connecting all the village, particularly the backward villages of the country through roads."

309. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about providing the basic facilities to the schools not having adequate buildings/teachers and exist in a dilapidated condition, particularly in backward and rural areas of the country."

310. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the steps taken to put a check on prostitution."

311. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the need to formulate the development schemes for farmers, labourers, youths and women."

312. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about development of natural resources like drainage of river water to launch irrigation projects towards development of agriculture and development of minerals and petroleum resources in India."

313. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about dealing with the threat of naxal terrorism in the country."

314. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the steps taken to improve the level of sports in the country."

315. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the growing number of *pending* cases in various courts including supreme courts."

316. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about preventing the growing terror activities in North-Eastern State."

317. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about an effective warning system to save people from storms claiming a large number of human lives every year."

318. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing an insurance cover to farmer in the entire country who face a loss of their crops on account of natural calamities."

319. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the adoption of modern technology towards development of agriculture sector."

320. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing employment to all the educated youths in the country."

[Shri Sanjay Seth]

321. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about adopting new technologies to enhance the production of sugar in the country."

322. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing adequate financial assistance to sugar cane producers in the country."

323. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing assistance to persons who are forced to commit suicide owing to their poverty in the different parts of the country."

324. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the progress of villages in the rural areas to stop migration from villages to towns."

325. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the arrangement of pucca roads in the remote areas of the country."

326. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about to implement the new educational system for common masses of the country."

327. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about to bring improvement in the literacy rate of the country."

328. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to establish Agriculture Science Centres in all the districts of the country."

329. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the black-marketing of kerosene oil on a large scale meant for supply to the poor under Public Distribution System on a large scale."

330. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about to provide central assistance to the farmers affected by flood and drought."

331. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the problem of shortage of electricity in the country."

332. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to provide loan assistance by refixing the loans being provided to the farmer by the nationalised banks/ Co-operative banks in view of the adverse climatic conditions and natural calamities."

333. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the drought condition due to which a number of farmers of the country are being trapped in the dept."

334. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to provide assistance to the cotton producers of the country."

335. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to provide health care centre in every village of the country."

336. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to set up at least one small industry in every village of the country."

337. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to provide sports facilities in every village of the country."

338. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to implement the family planning programmes in every village of the country."

339. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to improve the industrial production in the country."

340. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about to achieve the annual export targets."

[Shri Sanjay Seth]

341. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to check the increasing number of infiltrators in India."

342. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to check the increasing activities of ISI in the country."

343. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to resolve the border disputes among different States in the country."

344. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention resolving water disputes among different States of the country."

345. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking welfare measures for agricultural labourers in the country."

346. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making the right to work a fundamental right in our constitution."

347. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to enact a law to ensure participation of workers in management."

348. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide proper medical facility to beedi workers."

349. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to ensure availability of drinking water for every person in the country."

350. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to maintain balance between export and import."

351. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide essential commodities to the rural people by ensuring subsidy from the Central Government."

352. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to make the right to health a fundamental right."

353. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to make the right to information a fundamental right."

354. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing employment and education to all."

355. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing telephone connection to every Panchayat office."

356. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the national economy getting totally affected by the policy of liberalisation."

357. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rising unemployment."

358. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need of a national Pension and Welfare policy for the handicapped, old-aged and disabled persons."

359. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about statutory schemes for providing compensation to the victims of violence, particularly to those of communal riots and for their rehabilitation."

360. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about including the right to shelter as fundamental right in the constitution."

[Shri Sanjay Seth]

361. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide free ration and other essential commodities to the persons living below poverty line."

362. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about depreciation of rupee as compared to dollar."

363. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to enact a suitable law to impose ban on exit polls during the elections."

364. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the facilities provided for the development of women in the backward and rural areas of the country."

365. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures for helping the entrepreneurs stuck in debt traps of banks due to faulty loan recovery policy of the Government and the fact that industries are becoming sick."

366. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for implementing a comprehensive legislation for agriculture labourers."

367. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about overcoming the shortage of coldstorages for the storage of vegetable, Potatoes, Onions and other perishable items in the country."

368. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about giving adequate encouragement to small scale industries in view of stiff competition with multinational companies."

369. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the lack of transport facilities in more than half of the rural areas of the country."

370. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any comprehensive scheme for generating more employment opportunities in the rural areas."

371. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about reviewing of the Forest Protection Act, as a result of which the developmental projects in dense forests and extreme affected states are hindered to a great extent at present."

372. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing free education to all the children upto graduation level without making any gender discrimination."

373. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about abolition of lakhs of posts in all the Central Government offices, PSUs, Railways and other such organisations."

374. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the repayment of loan to various banks and financial institutions by big business houses and industrialists."

375. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the reopening and rejuvenation of lakhs of small and big factories that have been shut down or have become sick."

376. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about extending the benefit of economic reforms to labourers and the poor."

377. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures contemplated by the Government for reducing Government expenses."

378. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for providing electricity and irrigation facilities for the development of the farmers."

[Shri Sanjay Seth]

379. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the upliftment of women in the education sector, service sector, social, economic and political sector."

380. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the stand of the Government for the protection of indigenous industries particularly in the public sector."

381. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the conversion of all the unmetalled roads into metalled ones and all the metalled roads into black topped roads under central sponsorship in the rural areas."

382. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the justified demand of the workers of the unorganised sector for equal pay for equal work."

383. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for removing the current restriction imposed on fresh recruitments in various Government departments, Government organisations and Semi-government bodies."

384. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the overwhelming numbers of incidents of banking scams and staggering the amount of money that turned into bad debts which have allegedly been registered as non-performing assets."

385. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for taking steps for protecting small scale and traditional Indian industries and providing financial and basic help to them after the entry of multi national companies and big business houses."

386. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for resolving the issues being faced by the sugarcane growers and the sugar industry in the country."

387. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for increasing domestic production in order to achieve self reliance in the field of crude oil production in view of the continuous import of the same."

388. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing reservation in Government services to the people of economically weaker section in the country."

389. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any time bound programme for providing pucca houses to the poors of the country with central assistance."

390. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any programme for good relation with our neighbouring countries by making our foreign policy more effective."

391. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about safeguarding the interests of the poor farmers and labourers against multinational companies."

392. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the basis for ascertaining the sectors for withdrawal of subsidy therefrom."

393. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to check in the loss of public enterprises by preventing extravagant *expenditures* and enhancing efficiency and responsibility therein."

394. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any specific programme to reduce the unproductive *expenditure* by Government."

395. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to develop and expand indigenous industries to provide employment to the youth of the country."

[Shri Sanjay Seth]

396. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any effective steps to arrest decreasing contribution of agriculture sector in the gross domestic production."

397. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any plan to introduce computer based education system in the rural areas."

398. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing change in the current census policy to ascertain exact economic progress in the country."

399. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making essential modifications to bring authenticity, effectiveness and responsibility in the administration."

400. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about enriching Indian industries by reducing the fuel prices."

401. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about creating any special fund to modernise small industries."

402. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about guidelines for news channels to telecaste programmes as per civilization and moral values of the country."

403. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the restructuring of loss incurring banks enable them to compete with private sector banks and foreign banks."

404. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the all round development of backward areas of the country."

405. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing employment to the poor youth belonging to all communities in armed and paramilitary forces."

406. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about involving any strategy at national level to tackle the problem of growing maoist menace in the border areas of the country."

407. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to check the black marketing of foodgrains allocated under various schemes of the Central Government and providing the same to the poor and the needy."

408. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the constant price-rise in the country."

409. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing better medical facilities to the poor citizens of the country."

410. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing pure drinking water to the people living in the rural areas of the country."

411. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about cent per cent electrification of the entire rural areas of the country."

412. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about sports facilities to be provided in the rural areas of the country."

413. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating sports policy at national level."

414. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient amount for specific programme for encouraging women participation in sports."

[Shri Sanjay Seth]

415. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about for allocating more funds to promote sport and physical education."

416. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about strengthening the National Service Scheme."

417. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient financial grants to remove the financial constraints of the Sports Authority of India."

418. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about selection of players for international level competitions on die basis of merit."

419. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about imparting compulsory physical education to the students of school and college levels."

420. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making judo and karate popular among women."

421. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about addressing shortcomings in the functioning of Nehru Yuva Kendras."

422. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about promoting sports in the rural areas."

423. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about optimal utilization of the playgrounds of the Government schools lying unutilized."

424. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing adequate pension to excellent former sports persons."

425. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about recommendations of the names of excellent sport persons for the Padmashree award."

426. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about adoption of modern technology for agricultural development in the country."

427. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about acceptance of the demand for "One Rank—One pension for defence personnel."

428. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about fulfilling the demand for enhanced pension for defence personnel."

429. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about procurement of defence equipment of state of the art technology on time."

430. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about stopping the procurement of arms and ammunition which have turned obsolete."

431. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the development of sanctuary."

432. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about encouraging incandescent technology for storage of agro products."

433. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about easy access to scientific research, especially in the field of bio-diversity for farmers."

434. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about easy access to scientific research and development work in agriculture for farmers."

[Shri Sanjay Seth]

435. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing financial aid to voluntary sports clubs situated in cities, villages and labour colonies"

436. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sports facilities to the youth through Resident Welfare Associations."

437. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about promoting sports culture among youth."

438. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of a comprehensive policy and action plan to redress the issues concerning the youth."

439. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing aid and conducting youth leadership training camps to young students and non-students"

440. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about releasing imprisoned Indians in the jails in Pakistan."

441. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about ensuring permanent membership of India to the United Nations Security Council."

442. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the traditional role being played by our country to promote non-alignment in international affairs."

443. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the effective role to be played in the United Nations."

444. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about respecting the line of control and international border by Pakistan and *end* cross-border terrorism."

445. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

"but regret that the Address does not mention about checking alarming rise in killings of the old persons, women and children and provide them adequate protection."

446. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up a special task force to encourage the use of Rajbhasha Hindi."

447. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing employment to the poor persons of all communities in armed and para-military forces."

448. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about giving pension and other benefits to the freedom fighters in a time-bound manner."

449. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing security to all major plants and establishments."

450. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about curtailing expenditure on hospitality."

451. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about improving facilities being provided to Central Reserve Police Force and other Central Security Forces."

452. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about proper maintenance of Village Panchayat Telephone in rural areas of the Country."

453. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about achievement of the targets fixed by banks for loan disbursement."

454. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about damage to crops due to water shortage in the country."

[Shri Sanjay Seth]

455. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-compliance of official language rules strictly."

456. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about action not being taken by Government with respect to making provision for publishing photos of voters in the voter's list by Election Commission to check bogus voting."

457. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any concrete progress in integrated cost-effective sanitation scheme."

458. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any steps taken to address the problem of polluted water in areas which are in the grip of polluted water containing fluoride, arsenic silt, iron and nitrate especially rural and backward areas in the country."

459. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about imposing a ban on all kinds of lotteries in the country."

460. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any step taken to check unfair practices in defence procurement."

461. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about sharing of some burden by Reliance industries including other refineries to compensate for loss to the oil marketing companies selling LPG and kerosene."

462. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about implementing any scheme to make world-famous Dal lake pollution-free."

463. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making the public administrative system effective in the country."

464. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about filling up thousands of vacant posts of officers and soldiers in Indian Army, Air Force and Navy."

465. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing basic facility of water supply in slums and small colonies."

466. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the efforts made for rehabilitation of beggars and for putting a check on begging."

467. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about serving good quality food to children during recess period."

468. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking stringent action against those fly by light companies which have, caused loss of crores of rupees to the investors."

469. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening various monuments/ heritage sites like Taj Mahal during night for common people."

470. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about excavation and re-establishment of temples which are submerged in lakes/river in various states of the country."

471. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about issuing no objection certificate to new colleges including monitoring of engineering colleges and about not controlling their regulations."

472. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishing any regulatory authority for monitoring and regulating the income by means of the telecast of sports events."

[Shri Sanjay Seth]

473. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-formulation of a pricing policy due to huge difference between the manufacturing cost and retail price of drugs in the country."

474. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishing medical universities for dealing with malnutrition and the problem of contagious diseases in the country."

475. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing more amount for scientific and industrial research."

476. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about plan to coordinate between various Ministries and departments in terms of technology, information and forecast and latest scientific, research and technological development work being carried out by them."

477. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the supply of coal in consistent with the demand of thermal power houses of the country,"

478. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about not taking action on the suggestion of Supreme Court regarding deputing para-military forces and installing cameras on voting centres to check unfair practices of election staff."

479. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fact that lakhs of tonnes of wheat and rice allotted to state Governments under various central schemes does not reach the needy."

480. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-imposition of a ban on spurious medicines in the country."

481. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about failure on achieving the target of agricultural loan disbursement by nationalised banks."

482. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-establishment of a fund, for encouraging the hidden talent in schools/colleges."

483. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-accessibility of lakh of tonnes of wheat and rice allocated to state Governments under various schemes to needy people."

484. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-imposition of ban on spurious drugs in the country."

485. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-achievement of the target of disbursing agriculture loans by nationalised banks."

486. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-establishment of any fund for bringing out hidden talents among students of schools/colleges."

487. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about non-implementation of any special scheme for the development of backward and rural areas of the country."

488. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of new education policy."

489. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about not formulating any scheme for deputing a special magistrate in each district in order to prevent corruption in the country."

490. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about doing away with the Devdasi system."

491. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating an insurance scheme for the livestock of the farmers after that of their agricultural product".

[Shri Sanjay Seth]

492. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on smoke emitting vehicles."

493. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on the increasing number of sick units of small industry sector."

494. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making Khadi and Village Industries Commission more result oriented and productive."

495. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about development of tourist destinations of the country in order to attract domestic and foreign tourists."

496. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on unprecedented increase in prices of essential commodities."

497. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating a new tourist policy for depicting Indian culture and tradition appropriately."

498. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing free ration and other essential commodities to the people living below poverty line in backward and rural areas of the country."

499. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about development of handicrafts."

500. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about increasing the transmission capacity of All India Radio and Doordarshan in highly backward and rural areas."

501. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about rehabilitation of those workers who became jobless due to closure of textile units."

502. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the welfare of textile mill workers."

503. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing fair share of the amount received from selling of land and other assets of closed textile mills to the workers *rendered* jobless due to closure of said units."

504. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about continuous import of crude oil and increasing of domestic production to be come self reliant in the matter of crude oil."

505. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the formulation of a national level action plan for water conservation."

506. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about farming a comprehensive plan for diverting excess water from flood prone and river flowing areas of the country to drought hit areas."

507. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to protect farmers from natural calamities and national disasters."

508. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about issuing guidelines to ensure change in appropriate crops and their diversification as per necessity and demands."

509. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the provision to provide sufficient storage capacity for agriculture produce in government sector and to promote creation of storage facility in private sector."

510. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to save farmers from being forced to sell their produce at cheap rate due to lack of options."

[Shri Sanjay Seth]

511. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to save the farmers from bumper import of agricultural produces under liberalized system of World Trade Organisation."

512. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to prevent the decline in share of agriculture in gross domestic product (GDP)."

513. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increase in domestic price of paddy and wheat."

514. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing assistance by Central Government to such farmers of the country, whose crops have been destroyed by natural calamity."

515. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the provision to encourage the farming of coarse grains, including grams, bajra, jowar."

516. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the provision to promote and accelerate the production of pulses and edible oils."

517. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the provisions to provide loans to farmers at their door steps by mobile banking."

518. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to promote the use of bio-fertilizers."

519. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing a special programme for production of Medicinal plants in backward areas of the country."

520. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to provide highly productive cotton seeds to farmers."

521. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to ensure purchase of wheat at minimum support price from farmers."

522. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to ensure purchase of rice at minimum support price from farmers."

523. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about encouragement to farmer community and to promote the usage of bio fertilizers by way of giving subsidy."

524. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of milk plant for development of dairy works."

525. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of animal husbandary and dairy work research centre for helping the farmers."

526. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about preparing national livestock policy."

527. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about developing the production of fodder and feed and increasing its production."

528. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient funds for development of beneficial new varieties of crops."

529. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about implementing labour reforms on priority basis."

530. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about constituting a regulatory authority for preventing the exploitation of labour and strictly enforcing the labour laws."

[Shri Sanjay Seth]

531. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing housing facility to miners."

532. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking welfare measures for agriculture labour."

533. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient number of doctors, medical instruments, medicines in E.S.I, hospitals."

534. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about early dispositions of events increasing *pending* cases in Supreme Court including various courts."

535. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishing tribunal with the objective to overcome delay in justice and providing speedy justice."

536. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about running the drawbacks of the policy being adopted for giving loans and its recovery by banks and financial institutions to poor, deprived people, unemployed youth, labourers and marginal farmers."

537. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about effecting implementation of various laws enacted for ascertaining the safety and security of women and child labour."

538. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking steps to ensure minimum wages to labour community in the country."

539. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to strengthen the autonomy of District Rural Development Authority."

540. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to check the privatisation, commercialisation and communalisation of education."

541. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention providing reservation government jobs to the people of economically weaker sections of the country."

542. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to provide drinking water to every person living in the rural areas of the country."

543. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to provide the proper health facilities especially to the villagers of rural areas of the country."

544. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to ensure the participation of Hon'ble Members of Parliament in the central drinking water scheme at district or state level."

545. That at the *end* of motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention to allocate funds to the Panchayat according to the population ratio for balanced development under sampoorna gramini rojgar yojana."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.546 to 555) by Shri Kiranmay Nanda; not present. Amendments (Nos.556 to 642) by Dr. T. Subbarami Reddy; not present. Amendments (Nos.643 to 644) by Shri Derek O' Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I move:—

643. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to pay respect to the 135 lives lost due to demonetization and the hardship faced by farmers, textile, construction and plantation workers, small business owners, trading communities, fishermen, housewives, students and large sections of middle class."

644. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Government imposed withdrawal and deposit limits, restricting the public to access their own hard earned money."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos.645 to 651) by Shri Nazir Ahmed Laway.

SHRI NAZIR AHMED LAWAY (Jammu and Kashmir): Sir, I move:

645. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to develop tourism infrastructure in state of J&K which largely depends upon tourism sector."

646. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any action plan for the resumption of peace talks with Pakistan."

647. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that an additional assistance of Rs 30000 crore will be provided in the budget for all round development of Jammu and Kashmir."

648. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that the recovery of loans from the farmers of Kashmir should be stopped and debt be waived off as the last year has witnessed a complete turmoil in the region and the loans taken could not be properly utilized."

649. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the time frame to complete the Jammu-Srinagar National Highway Project."

650. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the time frame of completion of Jammu-Srinagar Railway Project."

651. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any action plan to deal with the problem of unemployment in the state of Jammu and Kashmir."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Motion and Amendments have already been moved. Both are open for discussion. Shri Ghulam Nabi Azad.

The questions were proposed.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं यहां माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए और माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो उन्होंने दोनों सदनों के एमपीज़ को परसों सेंट्रल हॉल में सम्बोधित किया।

माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, the year of 2016 has been a year of depression, recession, suppression and regression. मैं सोचता था कि ...(व्यवधान)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Also frustration for some.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मैं सोचता हूँ कि उस तरफ से हमेशा अंग्रेज़ी में शायरी होती है, तो हिन्दी में थोड़ी हम भी पहल करें।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरी तबियत आज ठीक नहीं है और यह सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छी बात है, तो शायद जिस जोश से मैं बोलता हूँ, आज उस जोश से नहीं बोल पाऊँगा ...(व्यवधान)... Low Blood Pressure की वजह से।

सर, माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, उसमें कश्मीर के हालात के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है, प्रकट की गई है। यह चिन्ता स्वाभाविक है। सरकार को भी चिन्ता है, कश्मीर की जनता को भी चिन्ता है, विपक्ष को भी चिन्ता है, पूरे देशवासियों को भी चिन्ता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू में 'सबका साथ, सबका विकास' की बात कही और पूरी पार्टी तथा पूरी सरकार 24 घंटे सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हमेशा जम्मू-कश्मीर भारत का सिर या भारत का ताज़ माना जाता है और जम्मू-कश्मीर के बारे में, चाहे वह infiltration हो या बाकी हालात हों, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख है। माननीय प्रधान मंत्री जी जब प्रधान मंत्री बनने के बाद पहले कुछ महीनों में कश्मीर गए थे, तो आपने शुरुआत 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत' से की थी। सब लोग खुश हो गए थे, पूरा भारत खुश हो गया था, कश्मीर की जनता खुश हो गई थी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जनता खुश हो गई थी कि कई अरसे के बाद 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत' की फिर बात की गई। लेकिन उस 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत' का क्या हुआ? ग़ालिब का एक शेर है, जो आज जम्मू-कश्मीर के लोग दोहराते हैं:

"तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना,

कि खुशी से मर न जाते, अगर ऐतबार होता।"

उस 'कश्मीरियत', उस 'जम्हूरियत' और उस 'इंसानियत' ने इन ढाई सालों में किस तरह से सिसक-सिसक कर दम तोड़ दिया, इसे पूरी दुनिया ने देख लिया है। 2016 में उस 'जम्हूरियत' और 'इंसानियत' का कत्ल हो गया। मैं आज कश्मीर की आवाम से शुरू नहीं करता हूँ, 1947 से लेकर आज तक हमारे फौजी केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्णाटक से लेकर ओडिशा, बंगाल से लेकर यूपी, बिहार, गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कोई भी कोना शायद नहीं होगा, जहां हमारे फौजी.... हमारे security forces उस कश्मीर का हिस्सा बन कर रह गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। वह भी उस कश्मीरियत का एक हिस्सा बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आज उन फौजियों से शुरुआत करता हूँ कि कितने security forces के लोग मारे गए और कितने सीज़फायर वायलेशन्स हुए। मैं अगर यह कहूँगा कि 2014-15 और 2015-16 में सबसे ज्यादा सीज़फायर वायलेशन्स हुई हैं। जितनी सीज़फायर वायलेशन्स इन थोड़े से समय में एनडीए की सरकार में हुई हैं, शायद इतनी दस

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

या बीस सालों में नहीं हुई है। अगर 2015-16 के ही आंकड़े लें, तो पाते हैं कि 2015 में आतंकवादियों के हमले से जितने security forces के लोग मारे गए, जानें ज़ाया हो गई, उनकी संख्या 39 थी और पिछले साल इनकी संख्या बढ़ कर दोगुने से ज्यादा 82 हो गई और सैंकड़ों जख्मी हो गए, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए समाधान होना चाहिए। अगर सरकार इसको चिंता का विषय कहेगी, तो फिर मेरे ख्याल में पूरे देश को सरकार पर चिंता करनी चाहिए कि सरकार चिंता कर रही है। सरकार हल निकालती है, सरकार चिंता नहीं करती है, सरकार समाधान निकालती है, सरकार चिंता प्रकट नहीं करती है। चिंता तो जनता करती है। यह सरकार infiltration रोकने और हमारे security forces की जानें बचाने में असफल हुई। अगर मैं यह कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण में जो कश्मीर के बारे में, security forces के बारे में आपने कहा था, जब ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, इसकी वजह से 60 परसेंट आपकी पार्टी को मिला है, लेकिन आज कश्मीर के हालात ज्यादा खराब हो गए।

सर, मैं उन सिपाहियों और फौजियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में भारी बर्फबारी की वजह से avalanches में जानें चली गईं। Security forces की 20 जानें चली गईं, गुरेज में 14 फौजी मारे गए, 5 फौजी मछेल में मारे गए और मेजर अमित सोनमर्ग में बर्फ के नीचे आ गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ जानें बचाई जा सकती थीं। उनको बर्फ से निकाला गया था, लेकिन तीन दिन तक वे श्रीनगर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ता बंद था। इस संबंध में सरकार को मेरा एक सुझाव है कि 1998 से पहले बर्फ पड़ने से पहले security forces की कुछ जगहों पर, सेफर जगहों पर लोकेशन की जाती थी, लेकिन 1998-99 के बाद उनको एक ही जगह रखा जाने लगा, चाहे वह सेफ जगह हो या नहीं हो और यह इतिहास की बात है कि 1998 से लेकर आज तक दूसरी बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई। 1998 के बाद पहली बार 2008 में इतनी बर्फबारी हुई थी, लेकिन उस समय avalanches नहीं आए, बहुत कम आए, उसमें उतनी जानें नहीं गईं, लेकिन इस बार avalanches ज्यादा आए। मेरा यह सुझाव है कि उनके लिए दोबारा बंदोबस्त करना चाहिए, connectivity बढ़ानी चाहिए। हमारे पहाड़ों में वैसी connectivity नहीं है, जैसे कुछ बॉर्डर एरियाज़ में connectivity है। आप कच्छ में देखें, तो वहां जापान की जैसी सड़कें हैं। जहां में 20 साल पहले की, 25 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं वहां टूरिज्म मिनिस्टर था और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कच्छ जाता था, उस समय जापान जैसी सड़कें थीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में और वहां के पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बहुत कम है। उसका असर आम जनता पर तो पड़ता ही है, फौजियों पर भी पड़ता है और विशेष रूप से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जैसे ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, वे वहां से पैदल निकलना चाहें, तो उसमें भी कई दिन लग जाते हैं। इसलिए मेरी दरखास्त होगी कि विंटर के दौरान हमें वहां खास ध्यान देना होगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं यहां सजेशन नहीं दे सकता हूँ, सरकार को अलग से विस्तार में बता सकता हूँ।

इसके साथ ही, सिविलियन्स के साथ वहां क्या हुआ? बुरहान वानी के बाद जो हालात पैदा हुए, उसमें 90 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, सिक्योरिटी फोर्स और जनता के बीच की लड़ाई के दौरान, मुठभेड़ के दौरान, और वह नम्बर बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी फोर्स और जनता के बीच लॉ एंड ऑर्डर

मेन्टेन करने में 90 से ज्यादा लोग मारे जाएं और 12,000 लोग जख्मी हो जाएं, एक छोटी सी स्टेट में, यह बहुत बड़ी संख्या है। उनमें से एक चौथाई लोग, जिन 12 हजार लोगों को पैलेट इंजरीज आई, उनमें से खास तौर से बच्चों में पैलेट इंजरीज हो जाएं, बहुत सारे बच्चे हमेशा-हमशा के लिए अपनी आंखें खो दें, इस बारे में जहां हमारे मीडिया में बहुत छपा, टेलीविजन में बहुत आया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत छपा। न्यूयार्क टाइम्स ने तो यहां तक कहा, and I quote: "An Epidemic of 'Dead Eyes in Kashmir'". ये घटनाएं सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहीं, दुनिया के हर कोने में इस पर चर्चा हुई। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है, प्रदेश के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं है। जहां हम 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करते हैं, जहां देश का एक हिस्सा और वह भी सिर, यदि सिर ही महफूज न हो, सिर ही सुरक्षित न हो तो धड़ कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसलिए सिर को बचाने के लिए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को बचाने के लिए, इस देश का सिर बचाने के लिए, मेरे ख्याल में, इस सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

उसके बाद तकरीबन 10 हजार नौजवान लॉ एंड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए गिरफ्तार किए गए। उसमें से सैंकड़ों लोग पी.एस.ए. में डाल दिए गए। पी.एस.ए. में दो साल के लिए जेल में आप कम से कम रख सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के। कर्फ्यू वहां 90 दिन रहा और इन 90 दिनों में से 53 दिन वहां, पैली में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से कहीं एक दिन के लिए भी कर्फ्यू में रिलैक्सेशन नहीं दी गई। यह 'सबका साथ, सबका विकास' नहीं कहलाता।

माननीय उपसभापति साहब, कश्मीर के बारे में, मैं आने वाले बजट सेशन में जब चर्चा होगी, उस समय अलग से बोलूंगा, लेकिन पिछले बीते साल, जहां भारत के ताज के हालात के बारे में मैंने चर्चा की, हमारे भारत का जो धड़ है, जिस्म है, उसमें पिछले एक साल में क्या हो गया। डिमॉनेटाइजेशन की वजह से, जब उस पर चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है, 24 घंटे होती है, भारतीय जनता पार्टी और मंत्री चर्चा करते हैं, मैं सोच रहा था कि इतनी घटनाएं होने के बाद, सरकार डिमॉनेटाइजेशन या नोटबंदी के बारे में कम से कम क्रेडिट लेने की कम कोशिश करेगी, चर्चा कम करेगी और अपोलोजेटिक ज्यादा होगी। ज्यादा apologetic होंगे, कोई remorse की बात होगी, पछतावे की बात होगी, माफी की बात होगी, लेकिन वह नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में भी कैबिनेट ने डाला, उनके मुँह से भी तारीफ करवाई, लेकिन इस demonetisation में क्या है? इस नोटबंदी के बारे में सरकार की तरफ से जो शुरू में कहा गया था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, जो नकली नोट हैं, वे बन्द हो जाएंगे, terrorism खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, उन तीनों चीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। जितना पैसा बाहर था, वह तकरीबन सब बैंकों में वापस आ गया, तो ब्लैक मनी रही कहाँ?

इसी के साथ-साथ terrorism की बात आती है। बाँदीपुरा, जो कि पीओके के साथ लगा हुआ कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जब हमारी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, तो उसकी जेब से दो-दो हजार के नोट निकले, जबकि तब नोटबंदी को कुछ हफ्ते ही हुए थे। शायद तब यहाँ के बहुत सारे एमपीज को भी चेक के द्वारा दो-दो हजार और चार-चार हजार रुपए नहीं मिले थे, लेकिन बाँदीपुरा में उस आदमी की जेब में वे पहले ही पहुँच गए थे, तो यह तर्क भी गलत निकला।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

अब मैं counterfeit currency के बारे में पढ़ना चाहूँगा, जो एक मजाक है। अभी तक कई जगह counterfeit पैसे पकड़े गए हैं। उसके साथ ही, मैं दो और चीज़ें बताता हूँ। भारत की हिस्ट्री में शायद यह पहली दफा हुआ होगा या मुझे नहीं मालूम यह विश्व की हिस्ट्री में भी पहली दफा हुआ हो। मेरे पास "The Times of India" पेपर है और दूसरा पेपर भी है। इसमें लिखा है 'Bapu goes missing from a bundle of genuine two thousand rupee notes'. इसमें बापू ही नहीं हैं। The Father of the Nation के बगैर भी सरकार ने नोट छाप दिए। यह भी पहली दफा है। "The Times of India" ने ये फोटोज़ छापे हैं और यह दूसरे पेपरों में भी हैं, जिसको मैं सदन में रखूँगा। दूसरा है, '500 rupee notes with one side printed and the other side blank found in Madhya Pradesh.' वह यह है। यह एक साइड से प्रिंटेड है और दूसरी साइड से ब्लैंक है और फिर बैंक वाले कहते हैं कि यह भी ठीक है और वह भी ठीक है, यह प्रिंटिंग की गलती है। क्या यह टाइपिस्ट है? मैंने typographical error तो सुना था, लेकिन नोट पर गाँधी जी की फोटो न हो और नोट एक ही तरफ से छपे हों, यह हम पहली दफा सुन रहे हैं। हमसे ज्यादा शायद किसी और की इंटरनेशनल नॉलेज होगी, वह बता पाएगा कि किस देश में इस तरह के नोट्स छपते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है।

सर, इस demonetisation में एक और चीज़ देखने में आई और हमारी आँखें खुलीं। उस समय हम एक हफ्ते में 2,000 रुपये ले सकते थे, फिर 4,000 रुपये ले सकते थे और फिर 4,500 रुपये ले सकते थे। यह कई हफ्तों के बाद 4,500 रुपये हुआ था। हमने यह तो सुना था कि अगर बैंक में लोन लेने जाओ, तो वे दो परसेंट officially नहीं, बल्कि unofficially लेते हैं, वरना आपका लोन पास नहीं होगा। यह हम बचपन से सुनते आए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इनकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, लेकिन हमने यह पहली दफा देखा कि इस नोटबंदी के बाद बैंकों में दो दरवाजे हो गए। एक दरवाजे से 4,000-4,500 रुपये मजदूर को, किसान को, गरीब को, बूढ़े को, सड़क पर काम करने वाले को, एमपी को, लीडर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जा रहे थे। आप अगले दरवाजे से तो 4,000 रुपये ले सकते थे, लेकिन पिछले दरवाजे से लेने की कोई सीमा नहीं थी। आप उसमें, कोई वह 10 करोड़ ले सकते हो, 20 करोड़ ले सकते हो, 50 करोड़ ले सकते हो। यह तो कह सकते हैं कि इस वक्त हिन्दुस्तान में बैंक के मैनेजर शायद सबसे ज्यादा अमीर हो गए। मैंने ये घर के आंकड़े नहीं बनाए हैं, ये पेपरों से मैंने लिए हैं। सर, नई दिल्ली में साढ़े तीन करोड़ लेते हुए एक आदमी पकड़ा गया, यह तभी, उन्हीं दिनों की बात है। यह सब नई करेंसी थी। यह नवम्बर-दिसम्बर की बात है। जनवरी के आंकड़े नहीं हैं, सेशन उन दिनों चला नहीं, मैंने तब उसके भी आंकड़े निकाले थे। 30 नवम्बर को दूसरा वाकया हुआ। 6 करोड़ रुपये आई.टी. ऑफिशियल्स ने कर्णाटक, गोवा रीजन में पकड़े। 6 करोड़ में से 4 करोड़ 70 लाख रुपए नए नोट थे। अभी तक महीना पूरा नहीं हुआ था 30 नवम्बर को। 6 दिसम्बर को 35 लाख पकड़े गए। नाराज होंगे मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बी.जे.पी. के लीडर को वैस्ट बंगाल में एस.टी.एफ. ने पकड़ा, जिसके पास 35 लाख के दो-दो हजार के नोट थे। उसके साथ ही सी.बी.आई. ने और लोकल पुलिस ने गोवा में रेड किया, जहां डेढ़ करोड़ के नए नोट निकले। इसके साथ ही, 8 दिसम्बर को चेन्नई में आई.टी. ऑफिशियल्स ने एक racket bust किया, जहां 90 करोड़ रुपए सीज किए। इसमें 70 करोड़ रुपए नए थे। यह कौन सा बैंक है जिसमें अगले दरवाजे से 4 हजार निकलते हों, और पिछले दरवाजे से 90 करोड़ निकले हैं। कहीं से तो गए हैं, या तो जहां प्रिंटिंग होती है वहां से गए हैं या बैंक से गए हैं, कहीं न कहीं से तो गए हैं। मैं सब जगह नहीं, लेकिन अगली जगह से 1 करोड़ 57 लाख, दूसरी

जगह से 24 करोड़, फिर 7 करोड़ 2 लाख, फिर 5 करोड़ 7 लाख, फिर 8 करोड़ जिसमें से 2 करोड़ नए, 6 करोड़ पुराने। इसके बारे में भी तो डिसक्रेडिट सरकार को लेना पड़ेगा। यह डिसक्रेडिट कौन लेगा कि यह दो किस्म की करेंसी कहां से चल रही थी, ब्लैक मनी। तो यह है ब्लैक मनी, जो जेनेरेट हुई है इस नोटबंदी की वजह से, जो पिछले दरवाजे से जाती। ब्लैक मनी यह है। ब्लैक मनी वह नहीं है जो बैंकों में जमा हुई है, जो लोगों ने जमा कर दी। यह ब्लैक मनी जेनेरेट हुई है। This is just a tip of the iceberg. कितने लोग पकड़े गए हैं। कितने हजारों करोड़ इस तरह से बदल लिए। इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा कि इंटरनेशनल प्रेस ने इसके बारे में क्या कहा। तो यह था ब्लैक मनी के बारे में, जो जेनेरेट हुई, खत्म तो नहीं हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बीच में होम मिनिस्टर साहब भी आए कि लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आज यह सब करो, आगे सब ठीक होगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब मीडिया वाले पहुंच जाते थे बाइट लेने के लिए, तो लोग कहते थे कि परेशानी तो है लेकिन सब ठीक होगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और इसी शहर में रहते हैं, उसी हिन्दुस्तान में रहते हैं, इसी हिन्दुस्तान के वासी हैं, सरकार में रहने के बाद लोगों के साथ मिलना कम होता है, आना-जाना कम हो जाता है, सरकार की फाइल में गुम हो जाता है। विपक्ष ज्यादा घूमता है। पहले तीन दिन तो रिपोर्टिंग बढ़िया होती थी, क्योंकि पहले दो-तीन दिनों में लाइनों में जो लोग रहते थे, वे पैसे निकालने वाले होते थे। लेकिन जब सरकार की तरफ से और आर.एस.एस., बी.जे.पी. की तरफ से हिदायत हो गई कि सब आर.एस.एस., बी.जे.पी. वर्कर्स लाइनों में रहो और बाइट्स दे दो कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब की यह बात है। मैंने शुरू में कहा कि हम भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं तो जाहिर है कि बाइट्स को dilute होना ही था। हमने दिल्ली के एक शहर में देखा कि बाजू वाली दुकान में, एटीएम में लोग हॉकी लेकर गए। जब एक 65 साल के आदमी ने आवाज़ उठायी तो उसको हॉकी से मारा। दुकान में जो हॉकी लेकर बैठा था, वह दुकानदार नहीं था, वह हॉकी वाला कहीं बाहर से आया था और उस आदमी को कितने stitches लगे, वह हमने देखा। वह सीपीएम का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था, हमारा आदमी था - वह आपका आदमी था। इन पैंतरों से सरकार नहीं चलती। सर, Demonetization का, नोटबंदी का असर क्या हुआ? माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के बारे में उल्लेख किया गया है। In Kisan's welfare lies the nation's prosperity. बहुत अच्छा है - कहने को, देखने को, सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सरकार में किसानों का क्या हुआ? National Crime Records Bureau क्या कहता है? वह कहता है कि 2014-15 में किसानों की 42 परसेंट आत्महत्याएं, suicides बढ़ गए। इस प्रकार हम उनका वेलफेयर देख रहे हैं? इस नोटबंदी की वजह से किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, fertilizer खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, insecticides के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी हम वेलफेयर की बात करते हैं! हमारे वक्त में भी ऐसी स्थिति आयी थी जब किसानों से आत्महत्या करने का आह्वान किया या शुरुआत की। उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने सन् 2008 में उनके 72,000 करोड़ रुपये माफ किए। सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के वाइस प्रेजिडेंट राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में एक किसान यात्रा की, मैं उनके साथ कुछ हफ्ते रहा और दो करोड़ मांग पत्र आ गए। हम माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गए थे कि उनका कर्ज माफ करें। हम राष्ट्रपति जी के पास भी गए, उनसे भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। सर, यूपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के घरों के

[श्री गुलाम नबी आजाद]

सामने, सड़कों पर किसानों के टमाटरों और आलुओं के ट्रकों के ट्रक फेंक दिए। कल मुझे यूपी के उरैया का एक किसान मिला। उसने कहा कि demonetisation के पहले, जिसे देसी भाषा में पचास किलो का एक कट्टा कहते हैं, पचास किलो की एक बोरी आठ सौ रुपए में जाती थी। वह एक बोरी, जो आठ सौ रुपए में जाती थी, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए एक दिन के 125 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन demonetisation के बाद उस बोरी की कीमत 800 रुपए से गिरकर 20 से 50 रुपए हो गयी। चूंकि बोरी की कीमत 20 से 50 रुपए हो गयी और उसका किराया 125 रुपए था, इसलिए हमने दस हजार बोरे फेंक दिए - दस हजार बोरे एक किसान ने फेंके। यह हाल सभी किसानों का है, यह घर-घर की कहानी है। किसान की ऐसी हालत कर दी है कि मुझे नहीं लगता है कि किसान अगले दस साल तक भी उठ पाएगा। सर, हमारी बहनें, बहू-बेटियां हमेशा पैसा बचाकर रखती हैं, बुरे समय के लिए कुछ पैसा बचाकर रखती हैं। उनके नोट भी कागज बन गए। हमने टेलिविजन पर देखा है कि सीनियर सिटीजन्स किस तरह से तीन, चार, पांच दिन लाइनों में लग कर चले जाते थे और कई सीनियर सिटीजन्स की जानें चली गईं। सर, कहीं सुना है कि 120 लोगों की किसी पॉलिसी की वजह से जानें चली गईं। यह तो मीडिया में आया है, उनके नाम आए हैं। बूढ़े, नौजवान हार्ट अटैक की वजह से मर गए। छोटे मासूम बच्चे ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया, क्योंकि अस्पताल नहीं जा सके। सर, और तो और एक गर्भवती महिला जिसको अस्पताल में दाखिल होना था, उसके घर में और कोई नहीं था, शायद उसे अस्पताल में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। 9 महीने की गर्भवती भी लाइन में बैठ गई और लाइन में ही बच्चा पैद हो गया। इससे ज्यादा और क्या आपकी सरकार कर सकती थी? आपने गर्भवती महिलाओं के भी बच्चे खड़े-खड़े लाइन में पैदा करवा दिए, 75 साल के बूढ़े को भी लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया और फिर भी, नोटबंदी अद्भुत, यह अद्भुत नहीं है, यह भूत है। यह इस देश की जनता के लिए भूत बनकर आया है, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। भगवान के लिए, खुदा के लिए ऐसे भूत आप अपने पास ही रखिए। जनता में बिल्कुल मत छोड़िए।

लेबर्स का क्या हाल हुआ है? लेबर्स जेनरेशन तो कम हो गई, लेकिन जो लेबर थी, हमारा जो कंस्ट्रक्शन था, उसका क्या हाल हो गया? कंस्ट्रक्शन को लोग आमतौर पर सोचते हैं कि बड़ा ठेकेदार है बस, लेकिन कंस्ट्रक्शन के साथ कितनी इंडस्ट्रीज चलती हैं, यह आपको मालूम है। आप नोएडा जाइए। आजकल मैं यू.पी. के इलेक्शन में जा रहा हूं और लोगों को बिठाकर पूछता हूं। वहां पर सब कंस्ट्रक्शन बंद है। एक कंस्ट्रक्शन से जब कुछ बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उससे कई हजार मजदूर रोजगार से वंचित हो जाते हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाता है। रोजगार सिर्फ मजदूर का ही खत्म नहीं होता है बल्कि हजारों जो मेसन काम करते हैं, वे बेरोजगार हो जाते हैं। हजारों कारपेंटर्स होते हैं, वे बेरोजगार हो जाते हैं। लोहे की और स्टील की जो फैक्टरियां हैं, वे बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद है और उस स्टील फैक्टरी में मालिक ही नहीं, बल्कि कितने entrepreneurs और कितने मजदूरों की नौकरी चली जाती है। बिल्डिंगों में सीमेंट लगता है, सीमेंट लेना बंद हो गया, तो सीमेंट की फैक्टरियों में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। ईट के भट्टों में हजारों-लाखों मजदूर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद होने के कारण ईंटों का खरीदना बंद हो गया, इससे मजदूरों की मजदूरी चली गई। यह तो एक सेक्टर की मैं बात करता हूं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, बाकी कितनी फैक्टरियां बंद हो गईं। गुजरात के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी खुद जानते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री का

क्या होगा? हैंडलूमस का क्या होगा, डायमंड्स का क्या होगा? सूरत में बीजेपी को कोई पैसा नहीं देगा। हां, डरा-धमका कर आप ले लें, लेकिन प्यार से नहीं देंगे।

जीडीपी, मैं economist नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के economists कहते हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी, जो economist हैं, वे भी जीडीपी दो-ढाई परसेंट कम होने की बात करते हैं। सर, पूरे देश में हमारे पेपरों ने, टेलिविजन ने क्या कहा, उसकी सबको जानकारी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने क्या कहा नोटबंदी पर, सबको मालूम है। हाई कोर्ट्स और कोलकाता की हाई कोर्ट बेंच ने क्या कहा, इस की जानकारी सब को है, लेकिन दुनिया ने क्या कहा, मैं उसका एक नमूना बताता हूँ। What has the international media said about demonetisation? I quote New York Times. 'It called the plan "poorly thought out and executed", given the pain it would inflict and its small, temporary gains.' UK's The Guardian says, "Modi has brought havoc to India", saying that "the rich will not suffer, as corruptly acquired fortunes have almost all been converted to shares, gold and real estate", but the poor would be hit hard." The Economist of UK says and I quote, "cautionary tale of the reckless misuse of one of the most potent of policy tools: control over an economy's money". It said that demonetisation would make only limited strides in shrinking the black economy, but would affect all of India's 1.3 billion citizens, the poorest most of all." The Financial Times of UK says and I quote, "India's cash bonfire was poorly designed, and was too much, too soon". Steve Forbes in Forbes magazine called the decision "breathtaking in its immorality". I quote again, ""What India has done is, commit a massive theft of people's property without even the pretence of due process - a shocking move for a democratically elected government."

सर, यह मैंने रिसर्च नहीं की है। मैंने यह जानकारी गूगल से निकाली है, जिसे कोई भी निकाल सकता है। इसलिए यह कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है।

सर, हमने यहां हमेशा आवाज उठायी है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आवाज उठायी, जिस का हम पूरा समर्थन करते हैं। अगर सरकार और सर्जिकल स्ट्राइक्स कराएंगी तो हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन लोकतंत्र में अपोजिशन को यह पूछने का हक होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने जवान मरे, कहां मरे? लेकिन हमने ज्यों ही नंबर पूछना शुरू किया तो हम एंटी-नेशनल हो गए, इस तरफ के वहां से लेकर यहां तक सब लोग एंटी-नेशनल हो गए। सर, हमने नोटबंदी के खिलाफ कहा, तो पूरी opposition ब्लैक मनी वाली हो गयी या हिंदी में जिसे कहते हैं, "चित भी तेरी, पट भी तेरी।" सरकार जो भी पॉलिसी लाए, अगर उसे क्वेश्चन करो, तो या तो आप एंटी-नेशनल हो गए या ब्लैक मनी वाले हो गए। यह एक तरीका अच्छा निकाला। इसलिए चुप रहो, हम जो करते हैं उसे सुनो वरना एंटी-नेशनल कहलाओगे। सर, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जहां भी प्लानिंग में

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

4.00 P.M.

shortcomings रही हैं या lack of planning रही है, उसका कारण था कि एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं किया गया, पैसे का बफर स्टॉक नहीं था, एटीएम्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। सर, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सरकार का यह भी रिकॉर्ड जाएगा कि किसी एक पॉलिसी को implement करने के लिए 50 दिनों में 135 दफा सर्कुलर इश्यू करने की सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ी। यह है "भूत", इस अद्भुत को हम मानने के लिए तैयार हैं कि यह गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड बन गया कि किसी एक पॉलिसी को, चूंकि यह इतनी ill-conceived policy थी कि उस ill-conceived policy को बगैर सोचे-समझे implement करने के लिए 120 से 135 दफा सर्कुलर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने पड़े हैं। यह वाकई में अद्भुत है, यह मैं मानता हूँ। डिप्टी चेयरमैन साहब, बड़ी देर से मुझे घूर कर देख रहे हैं, इसलिए मैं अगले पांच-छः मिनट में ही अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

सर, क्या वजह है कि कुछ लोगों को यह 8 नवम्बर से पहले ही मालूम हो गया था? हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जमीन के नीचे स्कैम है, जमीन के ऊपर स्कैम है और हवा में स्कैम है। आपने जो undeclared emergency लगाई है, आप एक हफ्ते के लिए उसको खोल दीजिए, तो आप देखेंगे, आपको इस सरकार के कितने स्कैम्स नजर आएंगे? 6 नवम्बर को.... आप लोग हंस क्यों रहे हैं? वे बेचारे कुछ कह नहीं सकते, उनको अगली दफा पार्लियामेंट का मेम्बर बनाना चाहेंगे और जो एक और मीडिया से थे, आपने उसको मंत्री बना दिया। पंजाब के एक आदमी ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, अगर आप एक मिनट दें, तो मैं आपकी कृपा से कहना चाहूंगा कि आपने इमरजेंसी को गलत माना है, यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा, मेहरबानी।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जब इमरजेंसी लागू की जाती है, वह हो या न हो, उसके लिए स्वयं प्रधान मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, लेकिन वह declare तो होता, एक process तो follow किया जाता। यहां तो कोई process ही नहीं है। आप कह दो इमरजेंसी है, हम मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने undeclared emergency कहा है। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक... मेरे पास नाम है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, 6 नवम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी के announcement के दो दिन पहले ही ट्वीट पर दो-दो हजार के नोट दिखाए थे। यह क्या वजह है कि बीजेपी की यूनिट ने वेस्ट बंगाल में उससे एकाध दिन पहले या उसी दिन तीन करोड़ रुपए जमा किए? यह क्या वजह है कि उसी महीने में बिहार और ओडिशा में बीजेपी के नेशनल ऑफिस के नाम पर जमीनें कैश में खरीदीं? हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को पहले ही लीक कर दिया था, उनको पहले से मालूम था। क्या वजह है कि बैंकों में इनकी वजह से इस साल आखिर के तीन महीनों में लाखों, करोड़ रुपया जमा हुआ है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है? आप देखिए कि को-ऑपरेटिव बैंक का क्या हाल हुआ, उसमें कितना पैसा किसका है? मैं कह रहा हूँ कि अभी undeclared emergency है,

इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। जब emergency हट जाएगी, तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो पूरा हिन्दुस्तान receiving end पर है, लेकिन किसी न किसी दफा तो ये तमाम चीजें निकलकर आएंगी।

सर, मैं दो लफ्ज बजट पर कहना चाहूंगा कि जो बजट आया है, इसमें employment के लिए कुछ भी नहीं है। वह 6 हजार करोड़ कहां हैं? हमसे तो यह भी वायदा किया गया था कि दस करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अभी तक एक लाख, दो लाख भी नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया है। नौजवानों को सिर्फ रोजगार, रोजगार और रोजगार चाहिए। यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, यह देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता है, जब तक देश के युवकों और युवतियों को रोजगार नहीं मिल जाता, यह सरकार को मानना पड़ेगा। यूथ को सिर्फ रोजगार की जरूरत है। आज ग्रोथ का क्या हाल है - इंडस्ट्री का क्या हाल है, रिट्रेंचमेंट कितनी हुई है? मैंने farmers के बारे में भी उल्लेख किया है, रूरल इकोनॉमी के बारे में क्या हो रहा है और जो मिल्क को-ऑपरेटिक्स हैं, उनमें क्या हुआ? 'मनरेगा' के लिए बड़ा पैसा बढ़ाया है, लेकिन 'मनरेगा' का काम नहीं चलता है। तमाम ऑयल इंडस्ट्री का क्या हुआ? मैंने रियल एस्टेट और डायमंड इंडस्ट्री की बात की। सर, इतने सालों में हमें एक बड़ी चिंता रहती थी कि देहातों से शहर की तरफ exodus हो रहा है, migration हो रहा है। शहर में यह एक चिंता हो रही थी, लेकिन इस नोटबंदी के बाद reverse migration हो गया है, क्योंकि तमाम काम ठप हैं। इंडस्ट्रीज में काम ठप है, कंस्ट्रक्शन में काम ठप है, रियल एस्टेट में काम ठप है। बेचारे लोग फिर वहीं देहात में गए, लेकिन देहात में जमीन कहाँ है? वहाँ तो घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। Except तीन-चार स्टेट्स, यू.पी., आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी स्टेट्स में अब kitchen garden रह गया है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। एक के दो, दो के चार, चार के सोलह, सोलह के चौंसठ होते हैं, अब उन्हें घर बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है। जो यहाँ काम करते थे, जब वे वापस जाएंगे, तब वे खुद क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? मेरा यही कहना है कि यह सरकार न सिर्फ एक साल में ही नहीं, बल्कि पूरे ढाई साल में हर फ्रंट पर, हर मोड़ पर नाकाम हुई है, असफल हुई है। देश को - मैंने जो पहले ही शुरू में regression कहा था, उसमें यह देश आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : مائنے ڈیپٹی چیئر صاحب، میں یہاں مائنے راشٹر پتی جی کے ابھیہاشن پر چرچا کرنے کے لئے اور مائنے راشٹر پتی جی کا دھنیواد کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں، جن انہوں نے دونوں سڈنوں کے ایم پیز کو پرسوں سینٹرل ہال میں سمبودھت کیا۔

the year of 2016 has been a year of depression, مائنے ڈیپٹی چیئرمین سر

recession, suppression and regression. ... (مداخلت) ...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Also frustration for some.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

† جناب غلام نبی آزاد : سر، میں سوچتا ہوں کہ اس طرف سے ہمیشہ انگریزی میں شاعری

ہوتی ہے، تو بندی میں تھوڑی ہم بھی پہل کریں۔

مائنے ڈپٹی چیئرمین صاحب، میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے اور یہ سٹہ دھاری پارٹی کے لئے اچھی بات ہے، تو شاید جس جوش سے میں بولتا ہوں، آج اس جوش سے نہیں بول پاؤں گا۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے۔

سر، مائنے راشٹر پتی جی کا جو ابھیہاشن تھا، اس میں کشمیر کے حالات کے بارے میں چنتا ظاہر کی گئی ہے، پرکٹ کی گئی ہے۔ یہ چنتا سوا بھاوک ہے۔ سرکار کو بھی چنتا ہے، کشمیر کی چنتا کو بھی چنتا ہے، وپکش کو بھی چنتا ہے، پورے دیش واسیوں کو بھی چنتا ہے۔ مائنے پردھان منتری جی نے شروع میں 'سب کا ساتھ، سب کا وکاس' کی بات کہی اور پوری پارٹی اور پوری سرکار چوبیس گھنٹے سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں۔ میں شروعات کرتا ہوں، کیوں کہ ہمیشہ جموں کشمیر بھارت کا سر یا بھارت تاج مانا جاتا ہے اور جموں کشمیر کے بارے میں، چاہے وہ infiltration ہو یا باقی حالات ہوں، راشٹر پتی جی کے ابھیہاشن میں جموں کشمیر کا الیکھ

ہے۔ مائنے پردھان منتری جی جب پردھان منتری بننے کے بعد پہلے کچھ مہینوں میں کشمیر گئے تھے، تو آپ نے شروعات 'کشمیریت'، جمہوریت اور انسانیت' سے کی تھی۔ سب لوگ خوش ہو گئے تھے، پورا بھارت خوش ہو گیا تھا، کشمیر کی چنتا خوش ہو گئی تھی، جموں کشمیر اور لڈاخ کی چنتا خوش ہو گئی تھا کہ کئی عرصے کے بعد 'کشمیریت'، جمہوریت اور انسانیت کی پھر بات کی گئی۔ لیکن اس 'کشمیریت'، جمہوریت اور انسانیت' کا کیا ہوا؟ غالب کا ایک شعر ہے، جو آج جموں کشمیر کے لوگ دوبراتے ہیں:

تیرے وعدے پر جنے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا،

کہ خوشی سے مر نہ جائے، اگر اعتبار ہوتا"

اس 'کشمیریت'، اس 'جمہوریت' اور اس 'انسانیت' نے ان ڈھائی سالوں میں کس طرح سے سسک سسک کر دم توڑ دیا، اسے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ 2016 میں اس 'جمہوریت' اور 'انسانیت' کا قتل ہو گیا۔

میں آج کشمیر کی عوام سے شروع نہیں کرتا ہوں، 1947 سے لیکر آج تک ہمارے فوجی کیرل سے لے کر تمل ناڈو، کرناٹک سے لیکر اوڈیشہ، بنگال سے لے کر یوپی، بہار، گجرات سے لیکر پنجاب، ہریانہ سے لے کر دہلی تک کوئی بھی کونا شاید نہیں ہوگا، جہاں ہمارے فوجی ہمارے سیکورٹی فورسز اس کشمیر کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ بھی اس کشمیریت کا ایک حصہ بن گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں آج ان فوجیوں سے شروعات کرتا ہوں کہ کتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے اور کتنے سیز فائر وائلشنس ہوئے۔ میں اگر یہ کہوں گا کہ 15-2014

اور 16-2015 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلشن ہوئی ہیں۔ جتنی سیز فائر وائلشنس ان تھوڑے سے وقت میں اینڈی۔اے۔ کی سرکار میں ہوئی ہے، شاید اتنی دس یا بیس سالوں میں نہیں ہوئی ہیں۔ اگر 16-2015 کے ہی آنکڑے لیں، تو پاتے ہیں 2015 میں آتک وادیوں کے حملے سے جتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے، جانیں ضائع ہو گئیں، ان کی تعداد 39 تھی اور پچھلے سال ان کی تعداد بڑھ کر دو گنے سے زیادہ

82 ہو گئی اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ بہت امپروومینٹ ہے۔ یہ چننا کا وشنے ہے۔ چننا کا وشنے ہمارے لئے ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کے لئے سمدھان ہونا چاہئے۔ اگر سرکار اس کو چننا کا وشنے کہے گی، تو پھر میرے خیال میں پورے دیش کو سرکار پر چننا کرنی چاہئے کہ سرکار چننا کر رہی ہے۔ سرکار حل نکالتی ہے، سرکار چننا نہیں کرتی ہے، سرکار سمدھان نکالتی ہے، سرکار

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

چنٹا ظار نہیں کرتی ہے۔ چنٹا تو چنٹا کرتی ہے۔ یہ سرکار infiltration روکنے اور ہمارے سیکورٹی فورسز کی جانیں بچانے میں ناکام ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ مائٹے پردھان منتری جی کے بھائین میں جو کشمیر کے بارے میں، سیکورٹی فورسز کے بارے میں آپ نے کہا تھا، جب یہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، اس کی وجہ سے ساٹھ فیصد آپ کی پارٹی کو ملا ہے، لیکن آج کشمیر کے حالات زیادہ خراب ہو گئے۔

سر، میں ان سپاہیوں اور فوجیوں کو بھی شرمناکجلی اربت کرتا ہوں، جن کی حال ہی میں، ابھی کچھ دن پہلے پچھلے مہینے میں بھاری برفباری کی وجہ سے avalanches میں جانیں چلی گئیں۔ سیکورٹی فورسز کی بیس جانیں چلی گئیں، گوریز میں چودھ فوجی مارے گئے، پانچ فوجی ماچھیل میں مارے گئے اور میجر امت سونبرگ میں برف کے نیچے آ گئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کچھ جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ ان کو برف سے نکالا گیا تھا، لیکن تین دن تک وہ سرینگر نہیں پہنچ پائے، کیوں کہ راستہ بند تھا۔ اس سمبندھ میں سرکار کو میرا سبھاؤ ہے کہ 1998 سے پہلے برف پڑنے سے پہلے سیکورٹی فورسز کی کچھ جگہوں سے محفوظ جگہوں پر، سیفر جگہوں پر لوکیشن کی جاتی تھی، لیکن 98-99 کے بعد ان کو ایک جگہ ایک ہی جگہ رکھا جائے لگا، چاہے وہ سیف جگہ ہو یا نہیں ہو اور اتفاق کی بات ہے کہ 1998 سے لے کر آج تک دوسری بار اتنی زیادہ برفباری ہوئی۔ 1998 کے بعد پہلی بار 2008 میں اتنی برفباری ہوئی تھی، لیکن اس وقت avalanches نہیں آئے، بہت کم آئے، اس میں اتنی جانیں نہیں گئیں، لیکن اس بار avalanches زیادہ آئے۔ میرا یہ سبھاؤ ہے کہ ان کے لئے دوبارہ بندوبست کرنا چاہئے، connectivity بڑھانی چاہئے۔ ہمارے پہاڑوں میں

ویسی connectivity نہیں ہے، جیسے کچھ بارڈر کے علاقوں میں connectivity ہے۔

آپ کچھ میں دیکھیں، تو وہاں جاپان کی جیسی سڑکیں ہیں۔

جہاں میں بیس سال پہلے کی، پچیس سال پہلے کی بات کرتا ہوں، جب میں وہاں ٹورزم منسٹر تھا اور ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے کچھ جاتا تھا، اس وقت جاپان جیسی سڑکیں تھیں، لیکن جموں کشمیر میں اور وہاں کے پہاڑی علاقوں میں connectivity بہت کم ہے۔ اس کا اثر عام جنتا پر تو پڑتا ہی ہے، فوجیوں پر بھی پڑتا ہے اور خاص طور سے ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں۔ جیسے ہی برقیاری شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے پیدل نکلنا چاہیں، تو اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اس لئے میری درخواست ہوگی کہ ونٹر کے دوران ہمیں وہاں خاص دھیان دینا ہوگا۔ کیوں کہ اس سے زیادہ میں یہاں سرجیشن نہیں دے سکتا ہوں، سرکار کو الگ سے وسٹار میں بتا سکتا ہوں۔

اس کے ساتھ ہی، سویلینس کے ساتھ وہاں کیا ہوا؟ برہان وانی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس میں 90 سے زیادہ سویلینس مارے گئے، سیکورٹی فورسز اور جنتا کے بیچ کی لڑائی کے دوران، مڈبھیڑ کے دوران، اور وہ نمبر بہت بڑا ہے۔ سیکورٹی فورسز اور جنتا کے بیچ لاء اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں 90 سے زیادہ لوگ مارے جائیں اور بارہ ہزار لوگ زخمی ہو جائیں، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ میں، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ان میں سے ایک چوتھائی لوگ، جن بارہ ہزار لوگوں کو پبلیٹ انجریز آئیں، ان میں سے خاص طور سے بچوں میں پبلیٹ انجریز ہو جائیں، بہت سارے بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھیں کھو دیں، اس بارے میں جہاں ہمارے میڈیا میں بہت چھپا، ٹیلی ویژن میں بہت آیا لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت چھپا۔ نیویارک ٹائمز نے تو یہاں تک کہا، and I

quote : "An Epidemic of 'Dead Eyes in Kashmir'"

[श्री गुलाम नबी आजाद]

یہ گھنٹائیں صرف ہمارے دیش کی سیماؤں تک ہی محدود نہیں رہیں، دنیا کے ہر کونے میں اس پر چرچا ہوئی۔ یہ دیش کے لئے اچھی بات نہیں ہے، پردیش کے لئے تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن بھارت کے لئے ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں ہم 'سب کا ساتھ، سب کا وکاس' کی بات کرتے ہیں، جہاں دیش کا ایک حصہ اور وہی بھی سر، اگر سر ہی محفوظ نہ ہو، سر ہی سرکشت نہ ہو تو دھڑ کیسے سرکشت رہ سکتا ہے؟ اس لئے سر کو بچانے کے لئے، جموں کشمیر اور لڈاخ کے بچانے کے لئے، اس دیش کا سر بچانے کے لئے، میرے خیال میں، اس سرکار کو ٹھوس قدم اٹھانے چاہئیں۔

اس کے بعد تقریباً دس ہزار نوجوان لاء اینڈ آرڈر کو میٹین کرنے کے لئے گرفتار کئے گئے۔ اس میں سے سینکڑوں لوگ پی۔ایس۔اے۔ میں ڈال دیئے گئے۔ پی۔سی۔ایس۔ میں دو سال کے لئے جیل میں آپ کم سے کم رکھے سکتے ہیں، بنا کسی ٹرائل کے۔ کرفیو وہاں نوے دن رہا اور نوے دنوں میں سے 53 دن وہاں، ویلی میں جو دس ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں سے کہیں ایک دن کے لئے بھی کرفیو میں رلیکسیشن نہیں دی گئی۔ یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس' نہیں کہلاتا۔

مائنے اپ سبھا پتی صاحب، کشمیر کے بارے میں، میں آنے والے بجٹ سیشن میں جب چرچا ہوگی، اس وقت الگ سے بولوں گا، لیکن پچھلے بیٹے سال، جہاں بھارت کے تاج کے حالات کے بارے میں میں نے چرچا کی، ہمارے بھارت کا جو دھڑ ہے، جسم ہے، اس میں پچھلے ایک سال میں کیا ہو گیا۔ demonetization کی وجہ سے، جب اس پر چرچا ہوتی ہے، بہت چرچا ہوتی ہے، چوبیس گھنٹے ہوتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی اور منتری چرچا کرتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اتنی گھنٹائیں ہونے کے بعد، سرکار demonetization نوٹ بندی کے بارے میں کم سے کم کریڈٹ لینے کی کم کوشش کرے گی، چرچا کم کرے گی اور اپولوجیک زیادہ ہوگی۔

زیادہ papologetic ہوں گے، کوئی remorse کی بات ہوگی، پچھتاوے کی بات ہوگی، معافی کی بات ہوگی، لیکن وہ نہیں ہے۔ مائنے راشٹرپتی جی کے بھاشن میں بھی کیپنیٹ نے ڈالا، ان کے منہ سے بھی تعریف کروائی، لیکن اس demonetization میں کیا ہے؟ اس نوٹ بندی کے بارے میں سرکار کی طرف سے جو شروع میں کہا گیا تھا کہ بلیک منی ختم ہو جائے گی، جو نقلی نوٹ ہیں، وہ بند ہو جائیں گے، ٹیریزم ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، ان تین چیزوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جتنا پیسہ باہر تھا، وہ تقریباً سب بینکوں میں واپس آ گیا، تو بلیک منی رہی کہاں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ٹیریزم کی بات آتی ہے، باندی پورہ، جو کہ پی۔او۔کے۔ کے ساتھ لگا ہوا کشمیر کا ایک بارڈر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں جب ہماری پولیس نے ایک آدمی کو پکڑا، تو اس کی جیب سے دو دو ہزار کے نوٹ نکلے، جبکہ تک نوٹ بندی کو کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے۔ شاید تک یہاں کے بہت سارے ایمپیز کو بھی چیک کے ذریعے دو دو ہزار اور چار چار ہزار روپے نہیں ملے تھے، لیکن باندی پوری میں اس آدمی کی جیب میں وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے، تو یہ ترک بھی غلط نکلا۔

اب میں counterfeit currency کے بارے میں پڑھنا چاہوں گا، جو ایک مذاق ہے۔ ابھی تک کئی جگہ counterfeit پیسے پکڑے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، میں دو اور چیزیں بتاتا ہوں۔ بھارت کی ہسٹری میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا یا مجھے نہیں معلوم یہ دنیا کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہوا ہو۔ میرے پاس "The Times of India" پیپر ہے اور دوسرا پیپر بھی ہے۔ اس میں لکھا ہے 'Bapu goes missing from a bundle of genuine two thousand rupee notes.' اس میں باپو ہی نہیں ہے۔ 'The father of the Nation' کے بغیر بھی سرکار نے نوٹ چھاپ دیے۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہے۔ "The Times of India" نے یہ فوٹوز چھاپے ہیں اور یہ دوسرے پیپروں میں بھی ہیں، جس کو

[श्री गुलाम नबी आजाद]

میں سدن میں رکھوں گا۔ دوسرا ہے '500 rupee notes with one side printed and the other side blank found in Madhya Pradesh.' یہ ایک سائڈ سے پرنٹڈ ہے اور دوسری سائڈ سے بلینک ہے اور پھر بینک والے کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ کیا یہ ٹائپسٹ ہے؟ میں نے typographical error بتا سنا تھا، لیکن نوٹ پر گاندھی جی کی فوٹو نہ ہو اور نوٹ ایک طرف سے چھپے ہوں، یہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ شاید کسی اور کا انٹرنیشنل نالج ہوگا، وہ بتا پائے گا کہ کس دیش میں اس طرح کے نوٹس چھپتے ہیں، کیوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔

سر، اس demonetization میں ایک اور چیز دیکھنے میں آئی اور ہماری آنکھیں کھلیں۔ اس وقت ہم ایک ہفتے میں دو ہزار روپے لے سکتے تھے، پھر چار ہزار روپے لے سکتے ہیں اور پھر ساڑھے چار ہزار روپے لے سکتے تھے۔ یہ کئی ہفتوں کے بعد ساڑھے چار ہزار روپے ہوا تھا۔ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اگر بینک میں لون لینے جاؤ، تو وہ دو فیصد پیسے آفیشنلی نہیں، بلکہ ان-آفیشنلی لیتے ہیں، ورنہ آپ کا لون پاس نہیں ہوگا۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو، ان کی سرکار ہو یا ہماری سرکار ہو، لیکن ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ اس نوٹ بندی کے بعد بینکوں میں دو دروازے ہو گئے۔ ایک دروازے سے 4000-4500 روپے مزدور کو، کسان کو، غریب کو، بوڑھے کو، سڑک پر کام کرنے والے کو، ایم۔پی۔ کو، لیڈر کو، انٹسٹرلسٹ کو دئے جا رہے تھے۔ آپ اگلے دروازے سے تو چار ہزار روپے لے سکتے تھے، لیکن پچھلے دروازے سے لینے کی کوئی سیما نہیں تھی۔

آپ اس میں، دس کروڑ لے سکتے ہو، بیس کروڑ لے سکتے ہو، پچاس کروڑ لے سکتے ہو۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں بینک کے منیجر شاید سب سے

زیادہ امیر ہو گئے۔ میں نے یہ گھر کے آنکڑے نہیں بنائے ہیں، یہ پیپروں سے میں نے لئے ہیں۔ سر، نئی دہلی میں ساڑھے تین کروڑ لیئے ہوئے ایک آدمی پکڑا گیا، یہ تبھی، انہیں دنوں کی بات ہے۔ یہ سب نئی کرنسی تھی۔ یہ نومبر دسمبر کی بات ہے۔ جنوری کے آنکڑے نہیں ہیں، سیشن ان دنوں چلا نہیں، میں نے تب اس کے بھی آنکڑے نکالے تھے۔ تیس نومبر کو دوسرا واقعہ ہوا۔ چھ کروڑ روپے آئی۔ٹی۔ آفیشنل نے کرنٹک، گوا ریجن میں پکڑے۔ چھ کروڑ میں سے چار کروڑ ستر لاکھ روپے نئے نوٹ تھے۔ ابھی تک مہینہ پورا نہیں ہوا تھا۔ تیس نومبر کو۔ چھ دسمبر کو 35 لاکھ پکڑے گئے۔ ناراض ہوں گے، میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن بی۔جے۔پی۔ کے لیڈر کو ویسٹ بنگال میں ایس۔ٹی۔ایف۔ نے پکڑا، جس کے پاس 35 لاکھ کے دو دو ہزار کے نوٹ تھے۔ اس کے ساتھ ہی سی۔بی۔آئی۔ نے اور لوکل پولیس نے گوا میں ریڈ کیا، جہاں ڈیڑھ کروڑ کے لئے نوٹ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ دسمبر کو چئی میں آئی۔ٹی۔ آفیشنل نے ایک jacket bust کیا، جہاں نوے کروڑ روپے سیز کئے۔ اس میں ستر کروڑ روپے نئے تھے۔ یہ کون سا بینک ہے جس میں اگلے دروازے سے چار ہزار نکلتے ہوں اور پچھلے دروازے سے نوے کروڑ نکلے ہیں۔ کہیں سے تو گئے ہیں، یا تو جہاں پر تنگ ہوتی ہے وہاں سے گئے ہیں یا بینک سے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو گئے ہیں، میں سب جگہ نہیں، لیکن اگلی جگہ سے ایک کروڑ ستاون لاکھ، دوسری جگہ سے چوبیس کروڑ، دوسری جگہ سے چوبیس کروڑ، پھر سات کروڑ دو لاکھ، پھر پانچ کروڑ سات لاکھ، پھر اٹھ کروڑ جس میں سے دو کروڑ نئے، چھ کروڑ پرانے۔ اس کے بارے میں بھی تو ٹس۔کریڈٹ سرکار کو لینا پڑے گا۔ یہ ٹس۔کریڈٹ کون لے گا کہ یہ دو قسم کی کرنسی کہاں سے چل رہی تھی، بلیک منی۔ تو یہ بے بلیک منی، جو جنریٹ ہوئی ہے اس نوٹ بندی کی وجہ سے، جو پچھلے دروازے سے جاتی۔ بلیک منی یہ ہے۔ بلیک منی وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہوئی ہے، جو لوگوں نے جمع کر دی۔ یہ بلیک منی جنریٹ ہوئی

[श्री गुलाम नबी आजाद]

ہے۔ This is just a tip of the iceberg اکتے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ کتنے ہزاروں کروڑ اس طرح سے بدل لئے۔ اس کے بارے میں بھی بعد میں بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل پریس نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ تو یہ تھا بلیک منی کے بارے میں، جو جنرل ہونی، ختم تو نہیں ہوئی۔ مائٹے پردھان منتری جی، مائٹے فائننس منسٹر صاحب اور بیچ میں ہوم منسٹر صاحب بھی آئے کہ لوگوں کو یہ وشواس دلانیں کہ آج یہ سب کرو، آگے سب ٹھیک ہوگا۔ مائٹے لاء منسٹر صاحب نے کہا کہ جب میڈیا والے پہنچ جاتے تھے، ہائٹ لینے کے لئے، تو لوگ کہتے تھے کہ پریشانی تو ہے، لیکن سب ٹھیک ہوگا۔ مائٹے لاء منسٹر صاحب آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی ہندوستان میں رہتے ہیں، اسی ہندوستان کے واسی ہیں، سرکار میں رہنے کے بعد لوگوں کے ساتھ ملنا کم ہوتا ہے، آنا جانا کم ہو جاتا ہے، سرکار کی فائل میں گم ہو جاتا ہے۔ ویکس زیادہ گھومتا ہے۔ پہلے تین دن تو رپورٹنگ بڑھیا ہوئی تھی، کیوں کہ پہلے دو تین دنوں میں لائنوں میں جو لوگ رہتے تھے، وہ پیسے نکالنے والے ہوتے تھے۔ لیکن جب سرکار کی طرف سے اور آر۔ایس۔ایس۔ بی جے پی۔ کی طرف سے ہدایت ہو گئی کہ سب آر۔ایس۔ایس۔ بی جے پی۔ ورکرس لائنوں میں رہو اور ہائٹس دے دو کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تب کی یہ بات ہے۔

میں نے شروع میں کہا کہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں، آپ بھی یہیں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہائٹس کو ڈائلیوٹ ہونا ہی تھا۔ ہم نے دہلی کے ایک شہر میں دیکھا کہ بازو والی دکان میں، اے ٹی ایم میں لوگ ہاکی لیکر گئے۔ جب ایک پینسٹھ سال کے آدمی نے آواز اٹھائی تو اس کو ہاکی سے مارا۔ دکان میں جو ہاکی لیکر بیٹھا تھا، وہ دکاندار نہیں تھا، وہ ہاکی والا کہیں باہر سے آیا تھا اور اس آدمی کو کتے اسٹچیز لگے، وہ ہم نے دیکھا۔ وہ سی پی ایم کا آدمی تھا، کانگریس کا آدمی تھا، ہمارا آدمی تھا۔ وہ آپکا آدمی تھا۔ ان پینٹروں سے سرکار نہیں چلتی۔ سر، Demonetization، گا، نوٹ بندی کا اثر کیا ہوا؟ مائٹے

In Kisan's راشٹریتی جی کے ابھیہاشن میں کسانوں کے بارے میں الیکھ کیا گیا ہے۔ welfare lies the nation's prosperity. بہت اچھا ہے۔ کہنے کو، دیکھنے کو، سننے کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس سرکار میں کسانوں کا کیا ہوا؟ National Crime Records Bureau کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 2014-15 میں کسانوں کی 42 فیصد آتم ہتھیائیں، سوسائٹس بڑھ گئے۔ اس طرح ہم ان کا ویلفئیر دیکھ رہے ہیں؟ اس نوٹ بندی کی وجہ سے کسانوں کے پاس بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، فرٹیلائزر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، insecticide کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹرانسپورٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹریکٹر کے لیے پیسے نہیں تھے، تیل کے لیے پیسے نہیں تھے، پھر بھی ہم ویلفئیر کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے وقت میں بھی ایسی پوزیشن آئی تھی جب کسانوں سے آتم ہتھیاں کرنے کا آہوان کیا یا شروعات کی۔ اس وقت یوپی اے گورنمنٹ نے سن 2008 میں ان کے 72,000 کروڑ روپے معاف کئے۔ سبھی پارٹیوں نے اپنی اپنی طرف سے پریاس کیا لیکن ہماری پارٹی نے، کانگریس کے وائس پریزیڈنٹ رابل گاندھی جی نے اترپردیش میں ایک کسان یاٹرا کی، میں ان کے ساتھ کچھ ہفتے رہا اور دو کروڑ مانگ پتر آگئے۔ ہم مانیئے پردھان منتری جی کے پاس گئے تھے کہ ان کا قرض معاف کریں۔ ہم راشٹریتی جی کے پاس بھی گئے، ان سے بھی کہا کہ کسانوں کا قرض معاف ہونا چاہیے۔ سر، یوپی اور چھتیس گڑھ کے مکھیہ منتریوں کے گھروں کے سامنے، سڑکوں پر کسانوں نے ٹماٹروں اور آلوؤں کے ٹرکوں کے ٹرک پھینک دیئے۔ کل مجھے یوپی کا 'اُرے با' کا ایک کسان ملا۔ اس نے کہا کہ نوٹ بندی کے پہلے، جسے دیسی بھاشا میں پچاس کلو کا ایک کٹا کہتے ہیں، پچاس کلو کی ایک بوری آٹھ سو روپے میں جاتی تھی۔ وہ ایک بوری، جو آٹھ سو روپے میں جاتی تھی، اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کے لیے ایک دن کے 125 روپے دینے پڑتے تھے، لیکن نوٹ بندی کے بعد اس بوری کی

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

قیمت آٹھ سو روپے سے گر کر بیس سے پچاس روپے ہو گئی۔ چونکہ بوری کی قیمت بیس سے پچاس روپے ہو گئی اور اس کا کرایہ 125 روپے تھا، اس لیے ہم نے دس ہزار بورے پھینک دیے۔ دس ہزار بورے ایک کسان نے پھینکے۔ یہ حال سبھی کسانوں کا ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ کسان کی ایسی حالت کردی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسان اگلے دس سال تک بھی آٹھ پائے گا۔ ہماری بہنیں، بہو بیٹیاں ہمیشہ پیسہ بچا کر رکھتی ہیں، بُرے وقت کے لیے کچھ پیسہ بچا کر رکھتی ہیں۔

ان کے نوٹ بھی کاغذ بن گئے۔ ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے کہ سینئیر سٹیزن کس طرح سے تین، چار، پانچ دن لائنوں میں لگ کر جلے جاتے تھے اور کئی سینئیر سٹیزن کی جانیں چلی گئیں۔ سر کہیں سنا ہے کہ 120 لوگوں کی کسی پالیسی کی وجہ سے جانیں چلی گئیں۔ یہ تو میڈیا میں آیا ہے، ان کے نام آئے ہیں۔ بوڑھے، نوجوان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گئے۔ چھوٹے معصوم بچے نے اپنی ماں کی گود میں دم توڑ دیا، کیوں کہ اسپتال نہیں جاسکے۔ سر، اور تو اور ایک گریبہ وئی مہیلا جس کو اسپتال میں داخل ہونا تھا، اس کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، شاید اسے اسپتال میں کچھ پیسے کی ضرورت پڑی۔ نو مہینے کی گربہ وئی بھی لائن میں بیٹھ گئی اور لائن میں ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا آپ کی سرکار کرسکتی تھی؟ آپ نے گریبہ وئی مہیلاؤں کے بھی بچے کھڑے کھڑے لائن میں پیدا کروا دیئے، 75 سال کے بوڑھے کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا، پورے دیش کو لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر بھی، نوٹ بندی ادبھت، یہ ادبھت نہیں ہے، یہ بھوت ہے۔ یہ اس دیش کی جنتا کے لینے بھوت بن کر آیا ہے، غریب کے لینے، کسان کے لینے، مزدور کے لینے۔ بھگوان کے لینے، خدا کے لینے ایسا بھوت آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ جنتا میں بالکل مت چھوڑیں۔

لیبرس کا کیا حال ہوا ہے؟ لیبرس جینریشن تو کم ہوگئی، لیکن جو لیبرر تھی، ہمارا جو کنسٹرکشن تھا، اس کا کیا حال ہوگیا؟ کنسٹرکشن کو لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ بڑا ٹھیکیدار ہے بس، لیکن کنسٹرکشن کے ساتھ کتنی انڈسٹریز چلتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ نوئیڈا جائیے۔ آج کل میں یوپی کے الیکشن میں جا رہا ہوں اور لوگوں کو بٹھا کر پوچھتا ہوں۔ وہاں پر سب کنسٹرکشن بند ہے۔ ایک کنسٹرکشن سے جب کچھ بلڈنگس بنتی ہیں، تو اس سے کئی ہزار مزدور روزگار سے ونچت ہو جاتے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ روزگار صرف مزدور کا ہی ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہزاروں جو میسن کام کرتے ہیں، وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں کارپینٹرس ہوتے ہیں، وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ لوہے کی اور اسٹیل کی جو فیکٹریاں ہیں، وہ بند ہونے کے کگار پر ہیں، کیوں کہ کنسٹرکشن بند ہے اور اس اسٹیل فیکٹری میں مالک ہی نہیں، بلکہ کتنے entrepreneurs اور کتنے مزدوروں کی نوکری چلی جاتی ہے۔ بلڈنگوں میں سیمینٹ لگتا ہے، سیمینٹ لینا بند ہوگیا، تو سیمینٹ کی فیکٹریوں میں ہزاروں بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اینٹ کے بھٹوں میں ہزاروں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن بند ہونے کی وجہ سے اینٹوں کا خریدنا بند ہوگیا، اس سے مزدوروں کی مزدوری چلی گئی۔ یہ تو ایک سیکٹر کی میں بات کرتا ہوں۔ کنسٹرکشن سیکٹر، بلڈنگ سیکٹر، باقی کتنی فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ گجرات کے بارے میں مائینے پردھان منتری جی خود جانتے ہیں۔ کپڑے کی انڈسٹری کا کیا ہوگیا۔ ہینڈلومس کا کیا ہوگیا، ڈانمنڈس کا کیا ہوگیا؟ سورت میں بی جے پی

[श्री गुलाम नबी आजाद]

کو کوئی پیسہ نہیں دیگا۔ ہاں ٹرا دھمکا کر آپ لے لیں، لیکن پیار سے نہیں دیں گے۔
 جی ڈی پی، میں اکائومنٹ نہیں ہوں، لیکن دنیا کے اکائومنٹ کہتے ہیں، ہمارے
 سابق پردھان منتری جی، جو اکائومنٹ ہیں، وہ بھی جی ڈی پی دو ڈھائی فیصد کم ہونے
 کی بات کرتے ہیں۔ سر، پورے دیش میں ہمارے پیپروں نے، ٹیلی ویژن نے کیا کہا، اس
 کی سب کو جانکاری ہے۔ چیف جسٹس کی بینچ نے کیا کہا، نوٹ بندی پر سب کو معلوم
 ہے۔
 ہائی کورٹ اور کولکاتہ کی ہائی کورٹ بینچ نے کیا کہا، اس کی جانکاری سب کو
 ہے، لیکن دنیا نے کیا کہا، میں اس کا ایک نمونہ بتاتا ہوں۔

What has the international media said about demonetisation? I quote New York Times. 'It called the plan "poorly thought out and executed", given the pain it would inflict and its small, temporary gains.' UK's The Guardian says, "Modi has brought havoc to India", saying that "the rich will not suffer, as corruptly aquired fortunes have almost all been converted to shares, gold and real estat", but the poor would be hit hard." The Economist of UK says and quote, "cautionary tale of the reckless misuse of one of the most potent of policy tools: control over an economy's money". It said that demonetisation would make only limited strides in shrinking the black economy, but would affect all of India's 1.3 billion citizens, the poorest most of all." The Financial Time of UK Says and I quote, "India's cash bornfine was poorly designed, and was too much, too soon". Steve Forbes in Forbes magazine called the decision "breathtaking in its immorality." I quote again, "What India has done is, commit a massive theft of people's property without even the pretence of due process-a shocking move a democratically elected government."

سر، یہ میں نے ریسرچ نہیں کی ہے۔ میں نے یہ جانکاری گُوگل سے نکالی ہے، جسے کوئی بھی نکال سکتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی اسٹیٹ سیکریٹ نہیں ہے۔

سر، ہم نے یہاں ہمیشہ آواز اٹھائی۔ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں آواز اٹھائی، جس کا ہم پورا سمرنہن کرتے ہیں، اگر سرکار اور سرجیکل اسٹرائک کرائے گی تو ہم اسے، لیکن لوکنتر میں اپوزیشن کو یہ پوچھنے کا حق ہوتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک میں کتنے جوان مرے، کہاں مرے؟ لیکن ہم نے جیوں ہی نمبر پوچھنا شروع کیا تو ہم اینٹی نیشنل ہو گئے، اس طرف کے وہاں سے لیکر یہاں تک سب لوگ اینٹی نیشنل ہو گئے۔ سر ہم نے نوٹ بندی کے خلاف کہا، تو پوری اپوزیشن بلیک منی والی ہو گئی یا بندی میں جسے کہتے ہیں، ”جٹ بھی تیری پٹ بھی تیری“ سرکار جو بھی پالیسی لائے، اگر اسے کونشنج کرو، تو یا تو آپ اینٹی نیشنل ہو گئے یا بلیک منی والے ہو گئے۔ یہ ایک طریقہ اچھا نکالا اس لیے چپ رہو، ہم جو کرتے ہیں اسے سنو ورنہ اینٹی نیشنل کہلاؤ گے۔ سر، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی پلاننگ میں شارٹ کمنگس رہی ہیں یا لیک آف پلاننگ رہی ہے، اس کی وجہ تھی کہ ایکسپرٹس کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، پیسے کا بفر اسٹاک نہیں تھا، اے ٹی ایم فنکشن نہیں کر رہے تھے۔ سر، گنیز آف بک ورلڈ ریکارڈ میں سرکار کا یہ بھی ریکارڈ جائے گا کہ کسی ایک پالیسی کو امپلی منٹ کرنے کے لیے 50 دنوں میں 135 دفعہ سرکولر ایشو کرنے کی سرکار اور ریزرو بینک آف انڈیا کو ضرورت پڑی۔ یہ ہے ”بھوت“ اس ادبھت کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ گنیز بُک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک نیا ریکارڈ بن گیا کہ کسی ایک پالیسی کو، چونکہ وہ اتنی conceived policy ہے کہ اس conceived policy کو بغیر

[श्री गुलाम नबी आजाद]

سوچے سمجھے امپلی مینٹ کرنے کے لیے آپ کو 120 سے 135 دفعہ سرکولر ریزرو بینک آف انڈیا اور فائننس منسٹری کو بھیجنے پڑے ہیں۔

یہ واقعی میں ادبہت ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ ڈپٹی چئیرمین صاحب، بڑی دیر سے مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں اگلے پانچ چھ منٹ میں ہی اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔

سر، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ آٹھ نومبر سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا؟ ہمارے لا منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ زمین کے نیچے اسکیم ہے، زمین کے اوپر اسکیم ہے اور ہوا میں اسکیم ہے۔ آپ نے جو آن ٹکلینرڈ ایمرجنسی لگائی ہے، آپ ایک ہفتے کے لیے اس کو کھول دیجیئے، تو آپ دیکھیں گے، آپ کو اس سرکار کے کتنے اسکیمس نظر آئیں گے؟ چھ نومبر کو... آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ بے چارے کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کو اگلی دفعہ پارلیمنٹ کا ممبر بنانا چاہیں گے اور جو ایک اور میڈیا سے تھے، آپ نے اس کو منتری بنادیا۔ پنجاب کے ایک آدمی... (مداخلت)۔

شری روی شنکر پرساد: سر، اگر آپ ایک منٹ دیں، تو میں آپ کی کریپا سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایمرجنسی کو غلط مانا ہے، یہ سن کر بڑا سکون ملا، آچھا لگا، مہربانی۔

جناب غلام نبی آزاد: جب ایمرجنسی لاگو کی جاتی ہے، وہ ہو یا نہ ہو، اس کے لیے خود پردھان منتری جی نے معافی مانگی ہے، لیکن وہ ٹکلینر تو ہوتا، ایک پروسیز تو فلو کیا جاتا۔ یہاں تو کوئی پروسیز ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ دو ایمرجنسی ہے، ہم مائنس کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں نے آن ٹکلینرڈ ایمرجنسی کہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک... میرے پاس نام ہے، میں بولنا نہیں چاہوں گا، چھ نومبر کو مائنس پردھان منتری جی کے انائنسمنٹ کے دو دن پہلے ہی ٹوئیٹ پر دو دو ہزار کے نوٹ دکھائے تھے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بی جے پی کی یونٹ نے ویسٹ بنگال میں اس سے ایک

دو دن پہلے یا اسی دن تین کروڑ روپے جمع کیئے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اسی مہینے میں بہار اور اڑیسہ میں بی جے پی کے نیشنل آفس کے نام پر زمینیں کیش میں خریدیں؟ ہمارا ماننا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی لیک کر دیا تھا، ان کو پہلے سے معلوم تھا۔ کیا وجہ ہے کہ بینکوں میں ان کی وجہ سے اس سال آخر کے تین مہینوں میں لاکھوں ، کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے؟ ان کو پہلے سے معلوم تھا۔ کیا وجہ ہے کہ بینکوں میں ان کی وجہ سے اس سال آخر کے تین مہینوں میں لاکھوں، کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے؟ کیا یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سمرٹھک نہیں ہیں؟ آپ دیکھئیے کہ کوآپریٹو بینک کا کیا حال ہوا، اس میں کتنا پیسہ کس کا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اُن ٹکنیرڈ ایمرجنسی ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب ایمرجنسی ہٹ جائے گی، تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوجائے گا۔ ابھی تک تو پورا ہندستان receiving end پر ہے، لیکن کسی نہ کسی دفعہ تو یہ تمام چیزیں نکل کر آئیں گی۔

سر، میں دو لفظ بجٹ پر کہنا چاہوں گا کہ جو بجٹ آیا ہے، اس میں ایمپلائمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چھ ہزار کروڑ کہاں ہیں؟ ہم سے تو یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ دس کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا۔ ابھی تک ایک لاکھ، دو لاکھ بھی نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو صرف روزگار، روزگار اور روزگار چاہیئے۔ یہ دیش تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ دیش تب تک پرگتی نہیں کر سکتا ہے، جب تک دیش کے یووکوں اور یووتیوں کو روزگار نہیں مل جاتا، یہ سرکار کو ماننا پڑے گا۔ یوتھ کو صرف روزگار کی ضرورت ہے۔ آج گروتھ کا کیا حال ہے، انڈسٹری کا کیا حال ہے، ری ٹرینچمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ میں نے فارمرس کے بارے میں بھی اُلکھ کیا ہے، رورل اکانامی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اور جو ملک کوآپریٹوز ہیں، ان میں کیا ہوا؟ 'منریگا' کے لیے بڑا پیسہ بڑھایا ہے، لیکن 'منریگا' کا کام نہیں چلتا ہے۔

[श्री गुलाम नबी आजाद]

تمام انڈسٹری کا کیا ہوا؟ میں نے ریٹیل اسٹیٹ اور ڈائمنڈ انڈسٹری کی بات کی۔ سر، اتنے سالوں میں ہمیں ایک بڑی چنٹا رہتی تھی کہ دیہاتوں سے شہر کی طرف exodus ہو رہا ہے، مانیگریشن ہو رہا ہے۔ شہروں میں یہ ایک چنٹا ہو رہی تھی، لیکن اس نوٹ بندی کے بعد reverse migration ہو گیا ہے، کیونکہ تمام کام ٹھپ ہے۔ انڈسٹریز میں کام ٹھپ ہے، کنسٹرکشن میں کام ٹھپ ہے، ریل اسٹیٹ میں کام ٹھپ ہے۔ بے چارے لوگ پھر وہیں دیہات میں گئے، لیکن دیہات میں زمین کہاں ہے؟ وہاں تو گھر بنانے کے لیے بھی زمین نہیں ہے۔ Except تین چار اسٹیٹس، یوپی، آندھرا پردیش کو چھوڑ کر باقی اسٹیٹس میں اب کچن گارڈن رہ گیا ہے، کیوں کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ ایک کے دو، دو کے چار، چار کے سولہ، سولہ کے چونتیس ہوتے ہیں، اب انہیں گھر بنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ جو یہاں کام کرتے تھے، جب وہ واپس جائیں گے، تب وہ خود کیا کھائیں گے اور اپنے پرہیز کو کیا کھلائیں گے؟ میرا یہی کہنا ہے کہ یہ سرکار نہ صرف ایک سال میں ہی نہیں، بلکہ پورے ڈھائی سال میں ہر فرنٹ پر، ہر موڑ پر ناکام ہوئی ہے، آسفل ہوئی ہے۔ دیش کو میں نے جو پہلے ہی شروع میں regression کہا تھا، اس میں یہ دیش آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ مانیٹریں راشنریٹی جی کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں۔ جے ہند۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Thank you very much. Now, Shri Neeraj Shekhar.

श्री नीरज शेखर: उपसभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें जन्मदिवस पर देश को जो शुभकामनाएँ दीं, मैं राष्ट्रपति जी

के अभिभाषण पर बात इससे शुरू करूंगा। उसके बाद उन्होंने चंपारण के आंदोलन का जिक्र किया। गाँधी जी के सौ साल हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि अभिभाषण में गाँधी जी का नाम भी लिया गया है, मैं इसके लिए इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि नोट से गाँधी जी गायब हो रहे हैं और चरखे से गाँधी जी गायब हो रहे हैं। अब चरखे पर हमारे प्रधान मंत्री जी आ गए हैं। अब चरखे पर वे रहेंगे। यह तो इन लोगों का एजेंडा है कि गाँधी जी का नाम नोट से नहीं, चरखे से नहीं, इस देश से ही खत्म कर दें, लेकिन गाँधी जी का नाम इनके खत्म करने से खत्म नहीं होगा, गाँधी जी का नाम इस देश के लोगों के दिलों पर है। इन्होंने यह जो शुरुआत की है, इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी।

[उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) पीठासीन हुए]

मैं जो अपनी बात कहूंगा, उसमें अपने नेताओं का स्तुतिगान करने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे पक्ष के दो नेताओं ने यह किया है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने यह किया, प्रधान मंत्री जी ने वह किया, अरे, आपकी भी सरकार है, आप यह बोलिए कि सरकार ने यह किया है। प्रधान मंत्री जी का - मैं हर बार सुनता था, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता था कि ये लोग अपने नेताओं के लिए बड़ी प्रेज या हमेशा ऐसे स्तुतिगान करते हैं, लेकिन आज मुझे आश्चर्य है और मैं कभी यह नहीं सोचता था, मैं आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी से - मैं डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे जी को तो जानता नहीं, लेकिन रवि शंकर प्रसाद जी से मुझे यह आशा नहीं थी कि ऐसा स्तुतिगान होगा, प्रधान मंत्री जी की ऐसी चालीसा पढ़ी जाएगी। मुझे इस बात का अफ़सोस है। मैं इसीलिए कह रहा था, मैं तो यह कहना चाहता हूँ, मैं यह प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि अब राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होना चाहिए, प्रधान मंत्री जी का अभिभाषण होना चाहिए। यह बड़े दुख की बात है। मैं उस दिन उनका भाषण सुन रहा था, मैं राष्ट्रपति जी की शक्ल देख रहा था। * मैं उसको समझ सकता था। ...**(व्यवधान)**... मैं समझ सकता था। ...**(व्यवधान)**... यह मेरी विचारधारा है। ये मेरे विचार हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: मैं अपने विचार रखूंगा। ...**(व्यवधान)**... आप इस पर कैसे खड़े हो सकते हैं?। am not yielding, Sir. ...**(Interruptions)**... I am not yielding. ...**(Interruptions)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह राष्ट्रपति जी की आलोचना हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): यह उचित नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: इन लोगों को आपत्ति हो, अगर मैंने कोई आपत्तिजनक बात बताई हो ...**(व्यवधान)**... तो आप बाहर निकाल दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह राष्ट्रपति जी की आलोचना हो रही है। ...**(व्यवधान)**... यह राष्ट्रपति जी की आलोचना हो रही है ...**(व्यवधान)**... उनके चेहरे की, उनके बोलने के ढंग की ...**(व्यवधान)**... मुझे आपत्ति है इस पर। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: मैंने सबका भाषण बड़े ही शांतिपूर्वक सुना। ...**(व्यवधान)**... मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, मैंने तब भी शांतिपूर्वक सुना। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: यह नहीं किया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**... इसको देख लें आप। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यदि आपत्तिजनक है ...**(व्यवधान)**... तो इसको निष्कर्ष के लिए जाँचा जाएगा ...**(व्यवधान)**... और यदि गलत है तो इसको निकाला जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: सर, अगर कोई आपत्तिजनक होगा, तो मैं अपनी तरफ से अनुरोध कर रहा हूँ कि उसको निकाल दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... अगर कोई आपत्तिजनक होगा ...**(व्यवधान)**...

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंत कुमार): सर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में उनके चेहरे के बारे में कोई निंदा नहीं हो सकती है, उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: सर, मैं यील्ड भी नहीं कर रहा हूँ और मंत्री लोग बोले जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अनंत शेखर: माननीय सदस्य ने जो उसका जिक्र किया है, उसको आप रिकॉर्ड से हटवाएं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अगर आपत्तिजनक है, तो उसको निकाला जाएगा। ...**(व्यवधान)**... आपत्तिजनक है, तो उसको निकाला जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। मैंने बड़ी शांतिपूर्वक सबको सुना है। मैं अपनी बात कह लूँ, उसके बाद जो इनको कहना है, ये कह लें। इसके लिए मेरा समय देखा जाए। मैं उस दिन राष्ट्रपति जी को देख रहा था। * मुझे भी उनकी बात सुनने में पीड़ा हो रही थी।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यह नजरिया है अपना-अपना।

श्री नीरज शेखर: मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरे विचार हैं। उनके विचार भिन्न हैं, मगर ये मेरे विचार हैं। मुझे आपत्ति इस चीज से है। ...**(व्यवधान)**... मुझे आपत्ति इसी चीज से है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने फिर वही बात दोहरा दी। यह तो उचित नहीं है। राष्ट्रपति जी के बारे में इस प्रकार से चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: मैं तो बोलूंगा।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैंने कह दिया है कि यदि आपत्तिजनक है, तो उसको निकाला जाएगा।

श्री थावर चन्द गहलोत: ठीक है।

श्री नीरज शेखर: सर, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रहा था। अभी गुलाम नबी जी ने भी कहा। मुझे आपत्ति इसी बात से है कि अगर कोई प्रश्न कर दे, तो कहेंगे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न कर दिया, जवानों पर प्रश्न कर दिया! आखिर हम अपनी आने वाली जेनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, वे किसी चीज़ पर क्वेश्चन न करें! अगर हम सेना पर क्वेश्चन कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि आप इस पर कैसे बोल सकते हो? अगर न्यायालय पर क्वेश्चन कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि जजों के बारे में कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? अगर हम प्रधान मंत्री जी के बारे में बोलते हैं, तो क्या-क्या टिप्पणियां हमको सुननी और पढ़नी पड़ती हैं? उसको लेकर तो मैं यहां पर अपनी बात नहीं कह सकता हूँ। हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि प्रश्न मत करो, किसी चीज़ के लिए कोई प्रश्न नहीं कर सकते, सरकार जो कहती है, चुपचाप सुनो। आगे आने वाली अपनी जेनरेशन के लिए हम यह अच्छा उदाहरण नहीं रख रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर इस देश में अपने बच्चों को खुले दिमाग से और खुले मन से सोचना सिखाना है, तो यह मत सिखाइए कि किसी चीज़ पर कोई प्रश्न नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक पर क्यों प्रश्न नहीं उठा सकते? अगर नहीं उठा सकते, तो आपने क्यों मिलिट्री वालों से इस बात को कहलवाया? अगर सीक्रेट है, तो जो सेना के अधिकारी थे, उनको बुलाकर क्यों कहा कि हमने बड़ा तीर मारा है और हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है? यह कहने की क्या जरूरत थी? क्या उसके पहले इस देश ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की? कितनी बार की और क्या कभी सरकार ने बताया? यह पहले और अब में इतना फर्क है। आप करते इतना सा हैं और इतना अधिक बनाते हैं, क्योंकि आपके नेताओं को बोलना सिखाया जाता है। मेरे ख्याल से नागपुर में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बोला जाए, काम मत करना, लेकिन कैसे बोला जाए, कैसे बताया जाए, उसकी शिक्षा दी जाती है।...(व्यवधान).... मुझे दिशा-भ्रमित मत कीजिए। मैं इसी पर रहना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप अपने विषय पर आइए।

श्री नीरज शेखर: सर, इस अभिभाषण में "स्वच्छ भारत" की बात हुई। इसकी क्या हालत है? आप कह रहे हैं कि हमने तीन करोड़ टॉयलेट बना दिए। इनमें से ये कितने काम कर रहे हैं? ये कैसे काम करेंगे? क्योंकि पानी की व्यवस्था वहां है या नहीं है, इस पर आपने सोचा ही नहीं। आप बना दीजिए "प्रधान मंत्री जी का आदर्श ग्राम", लेकिन आप वहां जाकर टॉयलेट देख लीजिए, मैं और कहीं का नहीं कहूंगा। मैं बार-बार इस बात को इसीलिए दोहराता हूँ कि आप सोचते नहीं हैं, बस काम कर दो, उसके बाद देखेंगे, जो परिणाम होगा। बिना सोचे समझे काम करने का कोई मतलब नहीं है। आपको देखना चाहिए था, आपको नीति बनानी चाहिए थी कि अगर हम गांवों में टॉयलेट बना रहे हैं, तो वे टॉयलेट कैसे आगे चलेंगे? उसकी कोई नीति नहीं है, मगर बना दिए और पूरी दुनिया में "स्वच्छ भारत" हो गया। अभी मुझे आश्चर्य है, जैसा रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि हमने इतना महान काम किया, उस दिन प्रधान मंत्री जी झाड़ू लेकर हरे पत्तों को झाड़ रहे थे। ये कैसी बातें हो रही हैं?

[श्री नीरज शेखर]

अगर माननीय रवि शंकर प्रसाद जी को उदाहरण देना चाहिए था, तो महात्मा गांधी जी का देना चाहिए था, जिन्होंने अपनी पत्नी को विवश किया कि तुमको टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। वे अपने जीवन में हर रोज अपना टॉयलेट साफ करते थे। कभी वहां जाएं, उनका आश्रम देखें। आप लोगों को उनका आश्रम देखने में दुख होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीजेपी, आरएसएस के लोग वहां जाते नहीं हैं। आप लोगों को दुख होगा, लेकिन आप लोग वहाँ जाकर देखिए। आप वहाँ जाकर देखिए कि उनकी जीवन पद्धति कैसी है। आप उसका उदाहरण दीजिए। आप यह दिखा रहे हैं, एक दिन मैं भी चला जाऊँ। एक दिन मैंने झाड़ू दे दिया, हम नेता बन गए और उस दिन स्वच्छ भारत हो गया। उसके बाद क्या आपने वहाँ जाकर गाँव की हालत देखी? अब मैं पढ़ रहा हूँ कि तीन राज्यों में बाहर शौच नहीं होता है, इतने डिस्ट्रिक्ट में यह काम हो गया है। क्या आपने इस देश में हालत देखी है? भाषण ऐसे दिया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इन्होंने बसंत ऋतु की बात से अपना भाषण शुरू किया, मैं सावन की बात कहना चाहूँगा कि सावन के अंधे को हर चीज हरी-हरी दिखाई देती है। वही इस सरकार का हाल हो रहा है। इनको सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। 'India Shining', 2003 वाला, फिर से शुरू हो गया है। 2016 में यह शुरू हो गया है। जिस तरह से 'India Shining' था, उसी तरह से शुरू हो गया है - 'Feel Good'। सब कुछ अच्छा हो रहा है। इन्होंने 'स्वच्छ भारत' बोला, तो भारत स्वच्छ हो गया। इन्होंने योग सिखाया, तो अब सारा देश योग कर रहा है। स्वस्थ हो गया है, ऐसा नहीं, अभी भी सबसे ज्यादा heart patients और diabetes patients हमारे देश में हैं। क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? आपने जितना पैसा इसके advertisement पर खर्च किया था, अगर सही जगह लगाते, तो कई अस्पताल बन गए होते। आप अपनी फोटो देखना चाहते हैं, अपनी बात सुनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। इस देश का पैसा लग रहा है, तो लगने दो। रोज हम अखबार खोलते हैं, तो फोटो देखते हैं, 'स्वच्छ भारत', 'India Shining', 'Standup India'। अभी कोई बोल रहा था, 'Sit Down India' नहीं, यह है - 'Slogan India'। स्लोगन दिए जाओ, धड़ाधड़, एक के बाद एक - 'India Shining', 'Make in India'। सब कुछ बोलते जाओ, लेकिन कोई एक धेले का काम हो रहा हो, तब बताइए।

मैं तो आज पूछना चाहता हूँ कि इस अभिभाषण में पेट्रोल के बारे में क्यों नहीं बोला गया? मैं तो हमेशा इसके बारे में प्रश्न पूछता हूँ कि जब इसका दाम 110 डॉलर प्रति बैरल था, तब भी यह 71 रुपए प्रति लीटर था, तब आप लोगों की सरकार थी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप लोग यह बात क्यों नहीं उठाते हैं कि अगर आज इसका दाम 58 डॉलर है, तब भी यह 71 रुपए है। ऐसा क्यों, जब आपने इसको सीधे मार्केट से जोड़ दिया है? मेरे ख्याल से अभी उस नीति में बदलाव नहीं हुआ है। क्या इसमें बदलाव हो गया है? मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हो गया है, तो मुझे बताइएगा, मुझे correct करिएगा। मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया और मैं इसे समझने की बड़ी कोशिश करता हूँ। मैं जब भी पेट्रोल या डीजल भरवाने जाता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो सकता है। अभी यह आधे दाम पर है, तो मान लिया कि देश के लिए कुछ sacrifice करना है, लेकिन ये राज्य सरकार, बैठे हुए नेता और बड़े उद्योगपति sacrifice नहीं करेंगे, sacrifice करना होगा, तो चाहे आप लोग हों, चाहे ये लोग हों, sacrifice बेचारा किसान करेगा, इस देश का गरीब करेगा, इस देश का मजदूर करेगा। Sacrifice उसी को करना है, क्योंकि आप लोग sacrifice नहीं करेंगे। पेट्रोल के दाम से हर चीज जुड़ी हुई है, डीजल के दाम से हर चीज जुड़ी हुई है, आप लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आप

चाहते, मैं यह नहीं कहता कि आप उसको आधे दाम पर कर दीजिए, लेकिन आप कुछ तो दीजिए। नहीं, जब भी इसका दाम एक डॉलर बढ़ता है, तो आप दो रुपए बढ़ा देते हैं। यह कैसे हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जब आप लोग ही इधर थे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस समय आप लोगों ने सदन के सामने जो नाटक किया था, कोई प्याज की माला लिए खड़ा था, कोई किसी चीज़ की माला पहन कर खड़ा था। अब आप लोगों को वह चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप जो बोलते हैं, उसको करिए, उस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए। आप लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। बस आप लोगों का भाषण चालू है, एक के बाद एक। मुझे तो लगता है कि आप लोग हमेशा election mode में रहते हैं। प्रधान मंत्री जी का ही कहना था कि बहुत ज्यादा चुनाव होते हैं। अगर विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होने लगें, तब तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रधान मंत्री जी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। प्रधान मंत्री जी को बस चुनावी भाषण ही देते हैं। हमेशा, कोई बात हो, अभी वहाँ भाषण, फिर वहाँ भाषण। कभी-कभी मुझे लगता है कि वे पार्लियामेंट में भी चुनावी भाषण दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप अभी लोक सभा का चुनाव करवा लीजिए। उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव हो रहा है, आप लोक सभा का चुनाव भी साथ करा लीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please address the Chair. ...**(Interruptions)**... Please address the Chair.

श्री नीरज शेखर: आप उनको नहीं बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप सीधे बात कीजिए, इधर-उधर ध्यान मत दीजिए।

श्री नीरज शेखर: जब कोई व्यवधान डालता है, तो मुझे बोलने की आदत है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि न बोलूँ, लेकिन मेरी आदत है। अब जन-धन एकाउंट की बात है, President's address में इसका बड़ा उल्लेख है। उसमें 26 करोड़ जन-धन एकाउंट्स की बात कही गई है। 8 नवम्बर से पहले जब हम लोग सुनते थे, तो पता चलता था कि जीरो बैलेंस के बहुत सारे एकाउंट्स हैं। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि अब जीरो बैलेंस के कितने एकाउंट्स हैं? जन-धन एकाउंट्स का किस तरह इस्तेमाल हुआ? प्रधान मंत्री जी से मैं ऐसी आशा नहीं कर रहा था, लेकिन जिस समय शायद वे मुरादाबाद गए हुए थे, उस समय उन्होंने बोला कि आप लोगों के जन-धन एकाउंट्स में जो पैसा जमा करवाया गया है, उसको वापस मत करिएगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम देश से भ्रष्टाचार को, काले धन को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को इस तरह की बात सिखा रहे हैं? मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी को हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि अगर प्रधान मंत्री जी यहां खड़े होकर बोलेंगे, तो इस तरह की बात कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वे बाहर रहते हैं तो उत्तेजना में न जाने क्या-क्या बोल जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि बाद में वे उन बातों पर सोचते भी हैं या नहीं सोचते। जन-धन एकाउंट के बारे में लोगों ने सोचा होगा कि इस सरकार ने हम लोगों को यह मौका दिया है। अब आप लोग ही निर्णय लेंगे कि आगे चलकर जन-धन एकाउंट वालों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

[श्री नीरज शेखर]

अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि आप लोग 18 लाख लोगों को इन्कम टैक्स के नोटिसेज़ भेजने वाले हैं, जिनके एकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं। मुझे नहीं पता कि 18 लाख लोगों को नोटिसेज़ भेजने के लिए इतनी manpower कहाँ से आएगी, इसके बारे में तो आप लोगों को ही पता होगा।

महोदय, मैं नोटबंदी पर भी जरूर कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को पिछले सेशन में इस विषय पर बोलने का मौका नहीं मिला था।

एक माननी सदस्य: चेंज करने का मौका नहीं मिला?

श्री नीरज शेखर: चेंज करने का मौका आप लोगों ने जिनको देना था, जिनकी सरकार है, अडानी और अम्बानी की सरकार है, उनको आप लोगों ने मौका दे दिया है और वे लोग चेंज कराकर आप लोगों को दे रहे हैं। यह बात सबको पता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन पैसा खर्च कर रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा मत बोलिए और अपनी पोल मत खोलिए। आपको समझ में आया?

मैं demonetization पर यह कहना चाहता हूँ, उस दिन तो मैंने प्रधान मंत्री जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन बाद में समाचारों में मैंने सुना। उन्होंने कहा कि रात्रि 12.00 बजे के बाद ये नोट रद्दी का टुकड़ा हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि Demonetisation को मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इससे आतंकवाद में कमी होगी, काला धन खत्म हो जाएगा, उग्रवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य है, पिछली बार भी मुझे किसी ने बताया था या सदन में ही मैंने यह सुना था कि नकली नोट तो बस 400 करोड़ ही हैं और उन्होंने अपने जवाब में यह कहा था कि ये 0.02 per cent of total currency हैं।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जितनी fake money आई, उसमें से कितनी पकड़ी गई? कितनी counterfeit money पकड़ी गई? आप लोग तो बैंकों में गए नहीं होंगे, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। एक बार जब मैं बैंक गया और जब मैं अपने पैसे ले रहा था, तो देख रहा था कि नकली नोट की कोई चेकिंग नहीं हो रही है, ऐसे ही वे नोट ले रहे हैं। जब पहले हम बैंक में पैसा जमा करवाने जाते थे, तो वे लोग एक-एक नोट चेक करते थे कि कहीं कोई नकली नोट तो नहीं आ गया। चूंकि इस समय बैंकों पर इतना प्रेशर है, इसलिए वे बिना चेक किए ही नोट लिए जा रहे हैं। जब सारी करेंसी एक साथ मिल जाएगी, तो बाद में यह तय नहीं हो पाएगा कि वे नोट तोमर जी ने जमा किए, अनन्त जी ने किए या नीरज शेखर ने किए। जब सारी करेंसी एक साथ मिल जाएगी, तो बाद में यह पता नहीं चल सकेगा कि उसमें fake money कितनी आई। हम लोगों को पता तो चले कि कितनी करेंसी बैंकों में डिपॉजिट हुई है।

पहले हर हफ्ते टीवी पर यह बताया जा रहा था। 15 नवम्बर को टीवी में आया कि बैंकों में इतना पैसा जमा हो गया है, लेकिन 10 दिसम्बर या 23 दिसम्बर के बाद से अब तक कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं। क्या आपसे यह कल्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है कि अब तक कितना पैसा आया है? अगर आपके पास आंकड़े आ गए हों तो मुझे बताएं। मुझे पता नहीं है कि बैंकों के पास कितना पैसा वापस आया है।

साथ ही हम यह जानना चाहते हैं कि कितना पैसा आपने नये नोटों के रूप में दिया है? उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि नोटबन्दी के आदेशों को 80 से 100 बार बदला गया। नोटबन्दी के संबंध में प्रधान मंत्री जी के भाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 50 दिन के बाद, यह देश जो सजा उन्हें देना चाहे, दे, लेकिन 50 दिन का समय उन्हें जरूर दिया जाए। अब 50 दिन तो हो गए। प्रधान मंत्री जी भी जानते हैं कि उन्हें कौन सजा देने वाला है, लेकिन देश का प्रधान मंत्री जो बोलता है, उसके बारे में जनता सोचती है कि वे इस बारे में वचनबद्ध हैं। वे जो बोलेंगे, वह जरूर कर के दिखाएंगे। ...**(व्यवधान)**... वही मैं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वह बिल्कुल हो रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक यदि कोई, किसी कारण से अपने रुपए बैंक में जमा नहीं करा पाए, तो वह 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई में जमा करा सकता है। यदि आप 2.50 लाख रुपए से कम जमा करेंगे, तो आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इस बारे में सूचना हर पेट्रोल पम्प पर लगी हुई है। मुझे तो आश्चर्य है कि इसे प्रचारित करने पर कितना भारी धन खर्च किया गया है। इसके बावजूद अब उन्हें दंडित करने की बात कही जा रही है कि जितना भी पैसा आपने जमा कराया है, उस सबकी इन्क्वायरी होगी।

महोदय, पहले कहा गया कि जो गृहिणी है, यदि वह अपने पैसे बैंक में जमा कराती है, तो उसकी जांच नहीं होगी, लेकिन अब उसकी भी जांच किए जाने की बात कही जा रही है। आप लोगों ने नोटबन्दी कर के एक बात तो जरूर की है कि इस देश की जितनी भी गृहिणियां हैं, वे आपसे नाराज हो गई हैं, क्योंकि जो स्त्री धन होता है, जिस धन को वह अपने पति से छिपाकर, घर खर्च से बचाकर रखती हैं, उसे आपने उजागर करने पर विवश कर दिया है और इस कारण उन्हें आपने अपना दुश्मन बना लिया है।

महोदय, प्रधान मंत्री, इस बात को नहीं समझ सकते, इसलिए यह बात मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग विवाहित और बाल-बच्चे वाले हैं, आप तो इसे अच्छी तरह से समझते हैं। स्त्री धन वह पैसा है, जिसे स्त्री अपने पास जमा करती थी, जिसे वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी, अब उसे बताना पड़ रहा है। आप ट्रांसपेरेंसी और कीजिए। मैं ट्रांसपेरेंसी करने के विरुद्ध नहीं हूं। ट्रांसपेरेंसी हर तरह से होनी चाहिए। मेरा कहना यही है कि लोगों को बताइए कि कितना पैसा आया, इस बारे में आप ट्रांसपेरेंसी कीजिए। आपने कहा था कि आरबीआई में 31 मार्च, 2017 तक पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन अब नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों, क्यों तब तक आरबीआई में पैसा जमा नहीं कराया जा सकता, क्या कारण है, आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? रोज नए कानून आ जाते हैं कि अब नहीं कर सकते, 30 तारीख तक यह करना है और 31 तारीख तक यह करना है। यह क्या है? हर बार आप नया कानून ले आते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार क्या करना चाहती है? अगर आप लोगों ने तय किया था कि मैं डिमॉनेटाइजेशन करना है, तो आपने उसका कोई फॉर्मूला बनाया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं आपने इसे किस-किस को बताया होगा। आप जैसे विद्वान लोग थे, तभी इस देश की यह हालत हुई है कि नोटबन्दी के बाद देश भर में लाइन में लगे हुए लोगों में से 135 लोग मर गए और इस देश की यह दुर्दशा हुई है।

महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तर्क दिया जाता है कि इस देश के लोग हमारे साथ हैं। क्या कहीं कोई घटना हुई है, आप लोग क्या चाहते थे, क्या आप लोग चाहते थे कि सड़कों पर दंगे हों,

[श्री नीरज शेखर]

बैंकों में जगह-जगह लूटमार हो, क्या आप यह चाहते थे? अगर इस देश का आदमी समझदार है, तो इस पर आप लोगों को दुख हो रहा है। क्या आपको इस बात पर दुख हो रहा है कि इस देश के आदमी ने लड़ाई नहीं की और सब कुछ चुपचाप सहता रहा? जो वेनेजुएला में हुआ, क्या आप यह चाहते थे कि वैसा ही इस देश में भी हो, सड़कों पर लड़ाई हो? मेरी समझ में नहीं आता कि यह तक कौन सा है? मैं आश्चर्य करता हूँ कि इतने विद्वान और महापंडित लोग, ऐसी बात कर सकते हैं। अगर इस देश का आदमी समझदार है और अगर वह अपने देश के बारे में सोच रहा है, तो क्या गलत सोच रहा है? अगर वह नहीं चाहता कि नोटबन्दी के कारण देश में मार पीट हो, तो क्या यह गलत है? वह बताएगा, उसका जब समय आएगा, तब वह आपको बताएगा और उसकी सज़ा आपको देगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप तो चुप हो गए। अब तो नोटबन्दी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। इस सरकार का यह कार्य मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है।

महोदय, अब मैं किसान के बारे में कहना चाहता हूँ। इस बात को कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं इस बात को बराबर उठाना चाहता हूँ कि किसान के बारे में आपने न कभी सोचा है और न कभी सोचेंगे। आप बार-बार कह रहे हैं कि नोटबन्दी की वजह से बुआई ज्यादा हुई और आने वाले समय में इसके कारण फसल ज्यादा होगी। मैं भी मानता हूँ कि ज्यादा फसल होगी, लेकिन फिर जो व्हीट पर 10 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वह आपने क्यों खत्म कर दी? यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। जो भी इसका जवाब देगा, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अगर आने वाले समय में व्हीट का उत्पादन बढ़ने वाला है, तो इसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी 10 परसेंट है, उसे आपने खत्म क्यों कर दिया? क्या आप बाहर से मँगाएँगे? इस देश के किसान की जो एमएसपी है, जिसे बढ़ाने के लिए आपने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा था कि ढाई गुना करेंगे, उससे पीछे होकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम यह कर ही नहीं सकते। तो आप किसानों के साथ क्या-क्या कर रहे हैं? इस किसान के साथ सबसे बड़ा छल आप लोग कर रहे हैं। इस देश के किसान के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ था। इस देश में सिंचाई के लिए क्या सिर्फ 5,000 करोड़ चाहिए? सिंचाई तो दूर की बात है, आज तक हम लोग अपने लोगों को पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। इसकी बात तो कहीं नहीं है। आज भी देश में लोग आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं। वह बात तो कहीं नहीं आ रही है! यह नहीं होता है कि पढ़ाई अच्छी कैसे होगी। आज सुबह एक प्रश्न था कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में अध्यापकों की कमी है, लाखों अध्यापकों की कमी है। उसके बारे में कोई बात नहीं है। वह कहाँ से आएगी? अपने एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, रोज-रोज विज्ञापनों में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वह पैसा उनमें लगाइए और अच्छे अध्यापक लाइए।

मुझे खुशी है कि इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी बलिया गए और वहाँ से उन्होंने 'उज्ज्वला' योजना का शुभारम्भ किया। मैं बार-बार आश्चर्य करता हूँ, जब सब लोग कहते हैं - मुफ्त है, मुफ्त है। मैं आप लोगों को अपनी जानकारी से कह रहा हूँ कि 1,600 रुपये लिए गए। ...**(व्यवधान)**... अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ, तो मुझ पर प्रिविलेज लाइएगा। ...**(व्यवधान)**... आप प्रिविलेज लाइएगा और मैं आप लोगों से माफी माँगूँगा। 1,600-1,600 रुपये लिए गए। इसमें मुफ्त क्या है? 3,200 की जगह 1,600 रुपए और उसके बाद जब वह गैस लेगा, तो उसको क्या आप मुफ्त में देंगे? ...**(व्यवधान)**... आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में जवाब दीजिएगा। उसके बाद उसको जो गैस देंगे, तो क्या आप मुफ्त में

देंगे? उसके लिए तो उसे पैसा देना ही होगा। उस दिन भाषण में सुना कि प्रधान मंत्री जी को बड़ा कष्ट था कि जब वे वहाँ जाते थे, तो अंधेरे में अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाते थे। इसमें मुझे आश्चर्य है। हम लोगों के यहाँ पूर्वांचल में तो चूल्हा ऐसी जगह नहीं होता है। चूल्हा तो ऐसी जगह होता है, जहाँ से धुआँ बाहर निकल जाए। वहाँ पूरा ऐसा होता है। ऐसे कोई कोठरी में चूल्हा नहीं बनता है। इस देश के जितने समझदार लोग हैं, वे चूल्हा एक बंद कमरे में नहीं बनाएँगे। लेकिन अलग-अलग चीजें हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी की विदेश नीति के बारे में बड़ी तारीफ की गई। प्रधान मंत्री जी ऐसे विदेश गए, सारे देशों में गए, हमारे प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान भी गए। माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने बताया, आज तक हमारे 82 जवान मारे गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो घटनाएँ हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जवान मारे गए हैं। आपने कहा नोटबंदी से cross border insurgency बंद होंगे, लेकिन वे ज्यादा बढ़ गये हैं। आप जानते हैं कि आज ओडिशा में क्या हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि वहाँ नक्सलियों ने क्या किया है। उसमें एक महीने का ठहराव हुआ और बाकी फिर से वही स्थिति है। काले धन का तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि काला धन कब आएगा। जो 15 लाख करोड़ था और सुना था तथा आपने एफिडेविट दिया था कि 15 लाख करोड़ में से बस 10 लाख करोड़ बैंकों में आएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ का 15 लाख करोड़ आ गया, तो इसका मतलब इस देश में काला धन तो नहीं है। हर बार जब ऐसी इनकी योजना फेल हो जाती है, तो उसके बाद ये एक नयी योजना ले आते हैं।

अब एक और योजना के बारे में कहा गया है। मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। इतने नाम हैं कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। उसका नाम 'गरीब कल्याण' योजना है। आप जो डिक्लेयर करेंगे, मैं जानना चाहूँगा कि उसमें कितना डिक्लेयर हुआ? मैं जानना चाहूँगा कि 'गरीब कल्याण' में कितना डिक्लेयर हुआ, जो आप करेंगे? 50 परसेंट ले लिया जाएगा, 25 परसेंट रोक दिया जाएगा। इस देश का आदमी तो यहीं confused है। बेचारा calculation ही कर रहा है। सुबह अखबार उठाता है, तो वह calculation करने लगता है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इन सब चीजों को देखें, सिर्फ स्लोगन मत दें, अपना काम करें। इस देश को स्लोगन और भाषण से ज्यादा काम की जरूरत है। आप लोग हर चीज में अपने को बढ़ा कर बताते हैं कि हम ये-ये कह रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि रवि शंकर प्रसाद जी ने करप्शन पर आकाश-पाताल सब एक कर दिया था। यह Transparency International की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 2014-15 में हम लोग 76वें स्थान पर थे और 2015-16 में 79वें स्थान पर आ गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में करप्शन बढ़ रहा है। जितना करप्शन 2014-15 में था, उससे बढ़ रहा है। हम लोग बोलेंगे, तो आप लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग तो भगवान के अवतारित हैं, सब लोग नागपुर से शिक्षा लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग करप्शन के बारे में तो जानते ही नहीं हैं, बस इधर के लोग जानते हैं, उधर के लोग तो करप्शन के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनको समझ ही नहीं आता है। ...**(समय की घंटी)**... सर, हमारी पार्टी का 54 मिनट का समय है और हमारी पार्टी के दो वक्ता हैं, आगे वाले वक्ता थोड़ा कम बोल लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपके और साथी भी बोलने वाले हैं।

श्री नीरज शेखर: सर, हमारी पार्टी से एक और साथी बोलने वाले हैं। 'डिजिटल इंडिया' के बारे में कहा जाता है। अब सारा देश डिजिटल होने वाला है, बिल्कुल हो गया, प्रधान मंत्री जी ने बोल दिया,

[श्री नीरज शेखर]

तो हो गया। जो प्रधान मंत्री जी बोल देते हैं, वह हो जाता है। हो गया, योगा हम सब लोगों ने सीख लिया, 'स्वच्छ भारत' हो गया, 'स्टैंड अप इंडिया' हो गया, 'मेक इन इंडिया' हो गया, 'स्टार्ट अप इंडिया' हो गया, 'स्किल इंडिया' हो गया, सब कुछ हो चुका है। अब नया है 'डिजिटल इंडिया'। 'डिजिटल इंडिया' के बारे में अभी तक मुझे नहीं समझ में आया है, मैं बलिया का हूँ, दिल्ली में पढ़ाई जरूर की है, लेकिन बलिया का हूँ, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। किसी एक साथी से समय लेकर सीखूंगा कि कैसे 'डिजिटल इंडिया' होगा? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पूरी दुनिया में एक ही देश ऐसा है, जो पूरी तरह से कैशलेस और डिजिटल है और वह है स्वीडन। वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी 100 परसेंट है और वहां पर सारे लोग पढ़े-लिखे हैं। इस देश में वह कैसे होगा, मैं यह जानना चाहूंगा। पता नहीं, हमारे वित्त मंत्री जी कभी बलिया गए हैं या नहीं, कभी छपरा गए हैं या नहीं, कभी चम्पारण गए हैं या नहीं, कभी कालाहांडी गए हैं या नहीं, कभी बोलांगीर गए हैं या नहीं, कभी छत्तीसगढ़ गए हैं या नहीं? इस देश को पहले जानिए, फिर बोलिए कि 'डिजिटल इंडिया' हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस कल्पना में जी रहे हैं? मैं तो हमेशा यह बात कहता हूँ। मुझे तो लगता है कि प्रधान मंत्री जी इस देश की वास्तविकता जानते हैं या नहीं जानते हैं? 15 साल तक वे मुख्य मंत्री रहे हैं और अब ढाई साल से प्रधान मंत्री हैं, तो इस प्रकार से वे 17 साल से जनता से दूर हैं। बताइए, जब वे मुख्य मंत्री थे, तब भी वे रोड से गए और किसी को रोक कर कुछ पूछा? वे हेलिकॉप्टर से गए होंगे, भाषण दिया होगा, फिर गांधीनगर आ गए होंगे। वे बताएं कि क्या वे कभी किसी गांव में गए, किसी गरीब के यहां गए? वहां जाकर किसी से पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है?

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात): वह गरीब के घर में पैदा हुआ है।

श्री नीरज शेखर: गरीब के घर में सब पैदा होते हैं। इस देश के जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वे चाल में रहते थे। इस देश के जो सबसे अमीर आदमी हैं, वे चाल में रहते थे, आज 5,500 करोड़ का उनका घर है। आप मुझे मत सिखाइए कि क्या है। अपनी पिछली जिन्दगी को भूल जाने के लिए 18 साल बहुत समय होता है। आपको आज जाकर देखना पड़ेगा कि इस देश में क्या हालत है, इस देश में गरीब कैसे रह रहा है। ऐसे ही सिर्फ भाषण दे देने से नहीं हो जाएगा कि मैं इस देश को जानता हूँ। इस देश के एक-एक गाँव में चल कर जाना पड़ेगा और गाँव के लोगों की तकलीफ को समझना पड़ेगा, सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा।

सर, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि आप लोग समझिए, इस देश को जानिए, ऐसे डिजिटल नहीं हो जाएगा। डिजिटल होने के लिए आप लोगों को और काम करना पड़ेगा। इस देश के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। हम लोग अपने देश के लोगों को पानी नहीं दे पाए और हम लोग डिजिटल होने की बात करते हैं। मुझे आश्चर्य है, मैंने लोक सभा में प्रधान मंत्री जी का एक भाषण सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 18 हजार गांवों को बिजली दे दी।

श्री शंकरभाई एन. वेगड़: आप गलत बोल रहे हैं, इसमें इनका भाषण नहीं है।

श्री नीरज शेखर: मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा लोक सभा में दिए गए एक भाषण के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसमें बोला था कि हमने सरकार में आने के बाद 18 हजार गांवों को बिजली दी है।

एक माननीय सदस्य: यह टारगेट है।

श्री नीरज शेखर: टारगेट नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा था। आप फिर से वह भाषण सुनिएगा, जिसमें उन्होंने 'मनरेगा' पर टिप्पणी की थी। आप फिर से उस भाषण को सुनिए, ऐसा उन्होंने वहां कहा था? ...**(व्यवधान)**... चलिए, मैं 18,000 मान लेता हूं जबकि आपने 11,000 कर दिया। ...**(व्यवधान)**... वह काम किसके द्वारा हुआ है। वह राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्यक्रम पहले से चल रहा है। आपने दीनदयाल उपाध्याय योजना में कितना पैसा दिया है? मैं आश्चर्य करता हूं कि आप कोई भी भाषण दे देते हैं और हम सुनते जाते हैं। मैं यही कहता हूं कि आप अपने बच्चों को सिखाइए कि वे प्रश्न कर सकें, इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका या सेना, जिससे भी प्रश्न करना चाहें, वे प्रश्न कर सकें। मैं चाहता हूं कि देश में ऐसे हालात बनें, लेकिन आप कोई प्रश्न नहीं चाहते हैं, ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री जी ने बोल दिया, अगर आप उनसे प्रश्न करेंगे तो आप देशद्रोही बन जाएंगे। ...**(व्यवधान)**... हमने इतनी गालियां सुनीं ...**(व्यवधान)**... मुझे एक गाना पसंद आया जो नोटबंदी पर था। वह था कि क्यों देश लाइन में खड़ा है? मेरा फेसबुक तो चला नहीं, मैं सिर्फ अपलोड करना जानता हूं और मैंने उसे अपलोड कर दिया। मैं यहां कोई नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने क्या कोई टीम यह काम करने के लिए रखी हुई है? मुझे इस बात का आश्चर्य है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बड़े दिल का बनिए। आप लोगों को बड़े दिल का बनने की आवश्यकता है। अभी सहस्रबुद्धे जी कह रहे थे कि हम लोग लाल बत्ती और घर के लिए नहीं आए हैं। आप लोगों ने सबसे बड़ा काम जो आने के बाद किया, वह यही किया कि सबसे घर खाली कराओ, सबसे बड़े घर में हम लोग रहेंगे, चाहे फर्स्ट टर्म का हो या सैकेंड टर्म का हो, वे नहीं। पहले हम लोग रहेंगे और लाल बत्ती में चलेंगे। आज मैं यह देखकर हैरान होता हूं कि किसके घरों पर ज्यादा बैरिकेडिंग है? मैं समझता हूं कि जो लोग पहले सिद्धांत की बात करते थे, आज सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उनके साथ चल रही है। इसलिए सिद्धांत दूसरों पर ही नहीं, अपने ऊपर भी लागू करिए।

मैंने समय ज्यादा ले लिया। मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। कुछ टिप्पणियां हुईं, लेकिन मैं अंत में, माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा और इस सदन से भी आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण न हो और प्रधान मंत्री जी का भाषण हो, ऐसा हो। धन्यवाद। जय हिन्द।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): I pray hon. Amma to give me the strength to discharge my duties faithfully and sincerely and guide me in all my endeavours. Hon. Amma is more than the God to me. I invoke her blessings before commencing my speech on the Motion of Thanks on the President's Address.

I thank His Excellency the President for his fine speech delivered in the Joint Session of Parliament. The speech deals with many aspects of India. We are very happy to note that our India is making progress. There is no doubt about it. The AIADMK also joins the Central Government in making the progress.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

In the course of his speech, His Excellency the President has referred to the centenary year of great leaders of India. But no mention has been made of a very popular leader, *Puratchi Thalaivar, Makkal Thilagam*, Dr. M. G. Ramachandran. This year is the centenary year of MGR. Of course, the Central Government released postal stamps. We thank the Central Government for that. But that is not sufficient. The AIADMK is celebrating the centenary year of MGR under the able and dynamic leadership of hon. Chinamma, our General Secretary of AIADMK. The Central Government must also allocate sufficient funds and celebrate the centenary year of MGR in a fitting manner. I think MGR and Amma are the most popular leaders of our nation. MGR cannot be forgotten. So, very humbly, I request the Central Government to celebrate the centenary year of MGR in an appropriate and befitting manner.

Then, I thank our hon. Foreign Minister for saving our national honour. She has made Amazon to apologise or to express regret. So, I thank the hon. Foreign Minister. With regard to Jallikattu, at the risk of repetition, we thank the hon. Prime Minister, the Home Minister, the Finance Minister, the Law Minister and the learned Attorney General, who intervened appropriately and took all legal steps to see that Jallikattu is conducted very smoothly in Tamil Nadu. I request the Central Government on a very sensitive issue which is there in Tamil Nadu, that is called NEET. In Tamil Nadu, there is no competitive examination to admit students in professional colleges like MBBS, BE, etc. Hon. Amma had given many memoranda to our Prime Minister to see that NEET is not implemented or imposed in Tamil Nadu. This kind of examination cannot be successfully faced by rural students and also poor students. Now, in our State, we have made a special enactment by which there is no competitive examination for admission to professional colleges. But, last year, the Central Government had given one-year exemption to Tamil Nadu from NEET. But, that exemption is not sufficient. Permanently, Tamil Nadu must be exempted from NEET. The reason is very simple. The syllabus for NEET is CBSE-based whereas we are following State Board syllabus. The questions based on CBSE syllabus cannot be answered by the students who have studied under the State Board. So, it is a natural thing. It is against natural justice. Of course, now, the Central Government has announced that NEET examination can be written in Tamil. But, that is not sufficient. So, again, like Jallikattu, I urge the Central Government to do the needful. A Bill has been passed by the Tamil Nadu Legislature seeking exemption from NEET examination with regard to admission to professional colleges. So, it must be followed up by the Central Government and appropriate legal measures and steps must be taken by the Central Government. It is a highly sensitive issue. Now, Tamil Nadu fully knows as to what is happening throughout

the world. They are making use of the latest technologies for achieving their goals. So, at the risk of repetition, I urge the Central Government that appropriate legal steps must be taken to get the Presidential assent to the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature seeking exemption from NEET.

With regard to Bhavani River, now the Kerala Government is going ahead with construction. Of course, the Tamil Nadu Government has moved the Supreme Court but the Central Government must intervene and do the needful. Now, entire Tamil Nadu is suffering from drought. Our Government has also declared the entire State as a drought State but the Cauvery Management Board must be constituted by the Central Government. It is in the hands of the Central Government. If water is released from Karnataka and water is flown into the river, there will be some relief to the farmers of Tamil Nadu. That must be done at an earliest point of time.

Also, with regard to the fishermen issue, I would like to submit that to find out a permanent solution, Kachchatheevu must be retrieved permanently from the hands of Sri Lanka. Our hon. Amma already moved to Supreme Court for filing a writ declaring that cessation of Kachchatheevu to Sri Lanka is unconstitutional so the Central Government must take appropriate steps to see that the fishermen issue must be settled permanently and Kachchatheevu must be retrieved.

With regard to laying of GAIL gas pipeline in Coimbatore and Erode districts, the GAIL is invoking provisions of a certain Act. That is not correct because the farmers are losing their land and they are unnecessarily burdened with many consequences. Not only are they losing the land but there are other consequences also. Hon. Amma had taken all legal steps but the desired effect is yet to be achieved. So, my humble request to the Central Government is that the GAIL gas pipeline must be realigned so as not to affect the farmers of the Tamil Nadu. It is also another sensitive issue. Now, people cannot be satisfied with what the courts say or what we politicians say. They must get justice because unless and until they achieve their goal, until they get satisfaction from the efforts of the Government, they will not allow the Government to function. It is a ground reality. I humbly urge and request the Central Government that the laying of GAIL gas pipeline should not affect the Tamil Nadu farmers. Appropriate steps must be taken.

Our hon. Chief Minister has also given a memorandum to our hon. Prime Minister seeking many reliefs, especially, the compensation for the damages suffered by Tamil Nadu due to Vardah cyclone and also drought conditions at other places. I urge the Central Government to release the funds as early as possible. The entire amount which has been

[Shri A. Navaneethakrishnan]

sought by the hon. Chief Minister, to the extent possible, must be released immediately. Otherwise the people of entire Tamil Nadu are now suffering. Some relief may be given by the Central Government. Though our hon. Amma is not with us but AIADMK is ruling Tamil Nadu. We are still having the rule of hon. Amma under the able and dynamic leadership of hon. Chinamma, the General Secretary of AIADMK. The State of Tamil Nadu will continue to be number one State in the whole of India. Thank you.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, before I make any points on the Motion of Thanks on the President's Address, we would like to sincerely acknowledge our hon. *Rashtrapatiji*; we start with an appreciation for him. He had been known to us from the time he was a Political Science professor in Vidyasagar College in South 24 Parganas. Now, 52 years later, he is our hon. *Rashtrapatiji* with a wealth of experience. We wish him happiness, we wish him health and good luck in whatever he does because as we know, in this term, this will be the last time he addressed the Joint Session of Parliament. Sir, the speaker, who moved the Motion, on behalf of the Government started off with telling us about Yoga, which we think is a very nice way to start his speech. And, after that, he went on to tell us some wonderful stories about little known people who have won the *Padma Shri* and how the Government had found these people and awarded them with the *Padma Shri*. They are not celebrities. They are kind of unknown people who had done good work. In that same tone, I wish to enlighten this House about a few more unknown people with three or four little stories before I get down to the main points of my speech.

Sir, Sudarsin Surin lives in Marangabahal Village in Odisha. Sir, when his two year old son fell ill, he took his son on a bicycle and travelled 7 kilometres to reach the Meghapal hospital. On reaching there, the doctors advised him to take his child to Sambalpur hospital which was about 40 kilometres away from Meghapal as the baby was critical. Sir, he asked the auto-rickshaw drivers to take him there but he only had 500-rupee notes with him. After three hours, sadly, the baby succumbed to his injuries. Sir, there are many stories like this. Sir, there is one Komali, an 18 months old baby. The parents didn't have the new currency to buy medicines and the private hospital in Andhra Pradesh — it is not about Andhra Pradesh alone, it is across the country but this particular incident was in Andhra Pradesh — refused to accept old currency notes. Komali is now no more with us. Suresh was of 18 years from Uttar Pradesh. He was a B.Sc. 2nd Year student. He hanged himself. Why? Because he could not withdraw money to pay the college examination fees. Take the case of Noel Topno in West Bengal. Suresh was 18 years old while Noel Topno was 52 years old. He was the Chief Manager of a Central Bank of India branch. He lost consciousness and he had a cardiac arrest while he was working.

5.00 P.M.

Sir, I ask this Government, they don't have to give *Padma Shris* for these families, *Padma Shri* is not required, but one minute silence, at least, in Parliament, in Lok Sabha and Rajya Sabha! 120 people or some people say 135 people have died. My party, The Trinamool Congress, from day one has been very clear on our views within 50 minutes of the hon. Prime Minister finishing his speech on November the 8th and I use the word historic because history has two sides. History can be good and history can be bad. So, it was historic. No doubt about it. So, this list has been compiled. The media has this list of 120 deaths. Sir, no *Padma Shri* but one minute silence. But, the question is: Has the Government even acknowledged these deaths? Have they expressed any condolences for these deaths? Have they told us in November, December and January, how these deaths will be prevented? What measures did they take? Sir, in a situation like this, it cannot be business as usual. It cannot and it must not be business as usual. We have been focussing on the pains of demonetisation and that is why, Sir, today, I will be sticking only to the President's Address. Fifty six seems to be a favourite number of this Government. In terms of 56 or *chappan*, I am only sticking to 55 because this is Para 55 on page 11, in the 4,902 words of the Presidential Address, which refers to demonetisation in about eight or nine lines.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

We are asking for withdrawal of deposit limits. Sir, yesterday, the Finance Minister made a speech. We did not come from our party to listen to his speech, nor did we come the previous day because we believe and our point was that for demonetisation, Parliament was ignored and that was our way of stating over the last two days that you people don't need Parliament because you have a one-man band. To quot from the Finance Minister's speech — and I am going back to Para 55 of the President's speech — the Finance Minister said, 'a trusted custodian of public money.' That is the Government's role. I ask, Sir, are you the only trusted custodian of the public money because you are not allowing the public to withdraw their private money for which they pay tax? So we appeal and urge upon this Government to please stay away from platitudes. From tomorrow or Monday, please stop all the restrictions that you have placed on the withdrawal limit. One thing got confirmed after the speech, in this booklet of about 4,000 words, and the Finance Minister's speech. The good thing, at least, which the Government has confirmed is that demonetisation has not worked because if it had worked, they would have given us some numbers. They would have

shared as to how much has been collected and how much has been given out. I read the Economic Survey with a great deal of interest and I must congratulate the Government on the literary part of it. There were some beautiful quotations including Ramakrishna Paramahansa, Arvind Adiga. There were very, very nice literary quotations. I am not getting into the content or the financial part because there was nothing there. There was nothing there in the Budget, anything worthwhile. Sir, this is a story of demonetisation. When my party spoke here in this House on 24th November and the hon. Prime Minister was sitting there, eyeball to eyeball, I told him, through you, Sir, "You can arrest all 46 Trinamool Congress MPs here. You can even try and arrest Mamata Banerjee in Bengal but that will not stop us from opposing your policy and it is nothing personal. We are opposing you for economic reasons. We are opposing you because we think that this is anti-people. We are opposing you because we think that these are draconian measures. We are opposing you because you have not thought this out. We are opposing you for this reason." We have said, with all humility, "धमकी मत दिखाओ don't do political vendetta on us." And exactly on this, Sir, you gave me an opportunity to speak in the morning. I managed to express myself for three minutes; so, I will not repeat those points. The leader of our party in Lok Sabha and our MP were arrested on 30th December and 3rd January, hardly two weeks after we made our points on demonetisation. Political vendetta is not a solution in a democracy. Sir, interestingly, on demonetisation — it has been around for about 12 weeks — after every two weeks, the Government has been coming up with a new reason as to why demonetisation took place. First, it was terrorism. For the next two weeks, it became black money. For the next two weeks, to remove corruption. For the next two weeks, something crazier, that is, to improve the digital economy. The day before yesterday we were hearing, to widen the tax net. And now yesterday we are hearing, to boost the real estate market. Sir, these are not the reasons. But I am not surprised because when it comes to slogans, it is very difficult to beat this Government. They have come up with some really good slogans like Start up India, Skill India, Make in India, Digital India. Our request to this Government is to make all these slogans and come up with a new slogan, 'Be India'; just, 'Be India'. Sir, Para 5 of the President's Address says, "At the core of all my Government's policies is the welfare". Sir, I beg to differ. Our belief from the Trinamool Congress is, at the core of this Government's policy is the PM. Not the hon. PM, but the PM. The PM means, Photo Mantri. Sir, I have a mother. She is 79. We all have our mothers. She was also required to go to a bank in Kolkata. I was travelling. I couldn't go to the bank to collect the money. So, I had sent two of my colleagues with her to collect the money from the bank. I had also another Option. I could have put her in a

queue. I could have sent some cameras there. I could have got those pictures shot. I could have put it on the social media. Then, I said, Derek what a good son you are. But there are others who may be having 96-year old mother who indulge in being a Photo Mantri, whether it is a Photo Mantri, whether it is a Coldplay concert, there also you were giving messages just a few days after *Notebandi*. In fact, I am completely bored with this name of Notebandi, or, demonetisation. I think, we need to come up with a new name. But on this issue, Sir, in Japan, same thing, ridiculing people who were standing in the queues. This is all the result of being 24x7 PM and the most hon. PM.

I can give you another example of Khadi which is fabulous. My colleagues here are talking about Mahatma Gandhi's picture disappearing from the currency notes. I do not know whether the Finance Minister will get into trouble. Yesterday, he had mentioned the name of Mahatma four times in his Budget Speech. In the last two years, I have been reading a lot about Golwalkar. After listening to the views of Golwalkar, I was wondering whether there was a need to make a choice. Is it Golwalkar or is it Mahatma? Sir, Khadi calendar is the same thing. This photo opportunity is not the solution for this problem. Because now if you really examine the demitronisation, sorry, I said it wrong, demitronisation or demonetisation or notebandi, you call it by whatever name you want, ...*(Interruptions)*... Sir, on a serious note, I appreciate we are having a debate, we didn't interrupt them and they are not interrupting us, so, that is all in good spirit. Although I was little focussed on my left side, if I may say to my senior Member and Minister, Ravi Shankarji, that he is going to get a lot of brownie points today because he mentioned the name of somebody thirteen times in his speech. That is very, very good. He is still nowhere compared to my colleagues from the AIADMK but he is getting there. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: This is too much. On the lighter vein it is okay.

SHRI DEREK O'BRIEN: Thank you. I am not so on a lighter vein.

Para 17 of the President's Address deals with transforming the lives of farmers and the like. Sir, I have five or six very important points to make on this. The informal sector accounts for 45 per cent of the GDP, and about 80 per cent of employment. The unemployment has increased by double percentage in the last few weeks and months. We told you this by the way on the 8th of November. I did it. Mamta Didi did it. I am mentioning her name for the second time.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not counting. You can go ahead.

SHRI AHMED PATEL (Gujarat): Only once he has mentioned her name.

SHRI DEREK O'BRIEN: About 25 crore daily wage workers have lost their employment. About 12 lakh power looms were shut down. The leather industry in West Bengal is headed towards trouble. We all know what is happening to tea gardens. I do not want to repeat reverse migration because the LoP made the point. Let us move to agriculture. Cooperative Banks were not allowed to exchange demonetised notes. No money to buy seeds. No money to buy fertilizers. The APMC says prices dropped by 40 to 46 per cent. Sir, you take auto sales. Auto sales are down to a 16-year low. It is not only about farmers and the unorganized sector, it is happening everywhere. Auto sales reduced by 19 per cent for four wheelers, 9 per cent for two wheelers, and this big second hand car market, which was growing in India, is down to zero. Take MSMEs. My State has one of the highest MSME growth rate in the country. But the overall decline in MSMEs has been to the extent of 50 per cent, with 35 per cent job losses in this sector. Sir, these are hard numbers. I started off with emotion and real stories, but these are hard numbers. Take *kirana* stores! Did no one think that in FMCG, in *kirana* stores, 90 to 92 per cent of transactions take place in cash? This is not black money. The transactions take place in cash. There is a 40 per cent drop in FMCG sales. Take MNREGA! My favourite quote about MNREGA came in March, 2015. Now, with the jugglery of numbers, they are saying MNREGA numbers have gone up. You can check it. MNREGA numbers didn't go up; they went down. Now, the numbers seem to have gone up. But my favourite quote on MNREGA was 'आज़ादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा! Who said this? The hon. Prime Minister said this. And now, they want to take credit for MNREGA also. Sir, the average days of employment under MNREGA per household last year were 34.84 days. I am giving you these numbers; you can dispute these numbers. I am very happy that in my State, Bengal, MNREGA provides at least 100 days of wage employment and 85 lakh person days of work has been generated, with ₹ 18,000 crores in the last few years. That is why Bengal is number one in MNREGA. I have got all these figures here, Sir. If you compare Bengal on any parameter to the national average in the last three years, Bengal is ahead. Take the manufacturing sector; it is the same problem.

Sir, I want to move on to the next point. I am a bit surprised, shocked actually, that this was not mentioned. It was mentioned in Para 55 of the President's Address when it came to funding. I just want to get to Para 55 so that we all are on the same page, and I am not going off the subject. Para 55 talks about the evils of black money, corruption, counterfeit currency, and so on. None of the two speakers who spoke from the Government

side today touched on this. I don't know why they didn't, but I would like to. There is not a word about offshore accounts! The Government has refused to disclose the data about Indian citizens who hold large sums of money in foreign accounts. No action on SIT! And I must be thankful to the hon, President for using the term 'money power' in Para 55. We have been saying this for the last more than a decade. It is money power which leads to bad media power — not all media is bad — which leads to muscle power. Muscle power is dangerous in politics! That is why we hear these stories, stories of people who try to be 'holier than thou', stories of people who try to be more pious than everybody else. But you have to see what percentage of BJP accounts are from undisclosed sources. And now, again, what is this * about bringing this amount of ₹ 20,000 down to ₹ 2,000?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, * is unparliamentary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Oh yes! * is an unparliamentary word. It won't go on the record.

SHRI DEREK O'BRIEN: Okay, Sir. I will give you a better word. What is this delusion...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: 'Senseless'.

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no. 'Delusion' is better. It is a delusion; actually it is an illusion because you bring the amount of ₹ 20,000 down to ₹ 2,000 for your electoral funding. Sir, nothing is going to happen. But the fun part is — and that is a good part — that they also know nothing is going to happen. चलाओ, अभी यूपी इलैक्शन्स चलाओ! Because we said 'corruption', so let us just slip this in! Sir, we have been talking about the Panama Papers. There are 11095 Indians; 25,000 in a single HSBC's account in Switzerland. Please bring this money back to India; prescribe a time-limit.

Then Sir, in the money, they talk about the Non Performing Assets. That is another fine number. There are six lakh crores of Non Performing Assets, and what did you do yesterday? Who are you kidding? Sorry. This is not in the President's Address, but as I am taking the advice in a holistic way, you have got 6 lakh crore of Non Performing Assets in your bank, and you give ₹ 10,000 crores yesterday for capitalization of banks.

Let us come to Para 23. Shri Ravi Shankar Prasadji today was talking a lot about women and children through Para 23 because the Indian woman has truly progressed. In 1960, on an average, Indian woman was bearing 5.7 children per woman. How beautiful!

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Derek O'Brien]

In fifty years, that number has come down to about 2.5. That is a huge progress. Hats off to the Indian woman.

Let us talk about the Kanya Shri scheme. They spoke about Beti Bachao Beti Padhao. I want to speak about Kanyashree scheme because in my State West Bengal, lakhs and lakhs of young girls have benefited from this Scheme. No wonder, this is one of the many reasons why in April, May, June, we won such a fabulous re-endorsement of Mamtaji in West Bengal. Sir, here is a very interesting number, and then you will know, who is serious about looking after the girl child and who is not because our State has also got U.N. Award. U.N. Award is less important. Look at this number. Take the case of Beti Bachao Beti Padhao. Good. They saw the scheme of the State; rebranded it and used it. That is good Federalism. There is no problem about it. The budget for that scheme for the whole country is ₹ 200 crores. It is not my number. It is their number. West Bengal is one State where the budget for this purpose is Rs. 1,000 crores. So, we are serious about it. But, with ₹ 200 crore budget, you please look at the advertising budget for that.

Sir, then, I come to women reservation. There is not a word about women's reservation today in the speech. They talk about women's reservation. We have been asking for 33 per cent women in Parliament. Then we said, what do we do? If nobody wants 33 per cent women, and they lecture about women, what did we do? In the Lok Sabha elections of 2014,— I am saying about 2016 also because we even did better there — out of the 34 seats the Trinmool Congress won, 34 per cent are already women. Sir, this is not photo *manch*. Otherwise, this will only become photo opportunity. Sir, look at the children. I was looking through the President's Address. Half of class V students in rural India cannot read at the class-II level. I asked this Government, what have they done? What have you done? Have you mentioned even once in the President's Address the ICDS thing? You have not mentioned ICDS in your entire document.

Sir, now, we come to Para 37. This talks about communal harmony, and both the speakers from the Government side, they were all praise, as they should be, for their hon. Prime Minister for his track record on communal harmony for the last two-and-a-half years. My brother is a student of Modern History. So, I try to be his shisya. I have the very interesting views from 2002 on communal harmony. There was a Chief Election Commissioner in 2002. Now, the election is coming up. The BJP will not get angry with it because I am quoting Atal Behari Vajpayeeji. Atal Bihari Vajpayee had some serious things to say about the then Chief Minister of Gujarat on this issue. I quote Vajpayeeji: "One may have differences over the decision or observation of the Chief Election

Commissioner with regard to the Assembly polls in Gujarat, There are constitutional means to deal with such matters." I didn't say this. The former Prime Minister Vajpayeeji said this about someone in 2002. All is very well when you come to Delhi. Then, you talk about the last two-and-a-half years and you are the paragon of virtue. I come from a city and a State where, when the India-Pakistan match could not be held anywhere, they had to come to Kolkata. When Gulam Ali had nowhere to perform, he had to come to Bengal where we welcomed him.

This is in September, 2002 which is documented. I am quoting from the speech in my broken Hindi: 'हम पांच हमारे पच्चीस'. The Gujarat Government conveniently could not find a copy of the speech. Thankfully, we managed to find a copy. I am reading it to you in English, because I am still learning Hindi. I quote: "What should we do? Do we go and run relief camps? Should we open child-producing centres? "हम पांच हमारे पच्चीस". Those who have got no education, those who have got only religious education, would they not become a burden on Gujarat?" Who said this? The current hon. Prime Minister of India. So, when we are in praise, there is nothing wrong in praise. My brother-in-law is from Gujarat. My wife's sister's husband tells me that apparently there is a tradition in Gujarat — I don't know whether he is a good Gujarati or not a good Gujarati. He said, "The tradition is that before a wedding, when the new bridegroom comes, everyone praises the bridegroom because they don't know whether he turns out to be good or bad." That also might be a case, but that is perfectly fine with me.

Sir, Digital India is one of my favourite subjects. It finds a mention in Para 60 and both the speakers have spoken about it. I am on this medium for the last six years. I know this medium. Is this about Digital India? No. This is about divisive India. Sir, I ask, through you, the Government to name me one democracy in the world where the Head of the Government attacks its own citizens for holding divergent views. It is only, sadly, our democracy. I am not just speaking up in the air; Sir, I have the facts. Twenty-six Twitter handles that give out rape threats, communal threats, are followed by the Prime Minister of India. Twenty-six! Two of these Twitter handles have been suspended by Twitter. This is not Trinamool or Congress or CPM or DMK. This is an international company called Twitter. Do you want the names of these handles? * is not unparliamentary because that is the name, * and * are the names suspended by Twitter. Where are we heading, Sir? These Twitter trolls are paid handles. They are invited. This is not some private thing, but it is public information. It is even published on a book. They are invited to the Prime

*Expunged as ordered by the Chair.

Minister's House for a nice digital social media party. When you talk to me about Digital India, give me these examples because these are real examples. Give me the example of Aamir Khan. There is documentary evidence to prove that Aamir Khan's entire thing where he lost the contract to the company was created.

Sir, I tell you, we are mainstreaming hate. I am saying this with responsibility. We are mainstreaming hate. Today, within a matter of minutes, we can create a hash tag, something like '#BengalBurning'.

Somebody throws a piece of beef on a temple; inhouse, they take a picture and it will go over. This is bad. Sir, I appeal, with all humility. As I said, the big slogan we need is 'Be India'. I don't blame only the BJP for this. That would be very unfair. The RSS is even worse when it comes to this kind of social hate mongering on Twitter. Sir, on the digital economy, now leave that digital part, I have made my point. Four out of five villages in India don't have a bank. Where do we have internet connectivity all over India? You are looking at the time; I will take a few minutes as we have only one speaker, so little extra. Seven per cent of debit card transactions when they are made in India, only six per cent have transactions and the rest are used only to withdraw money. Sir, we are all for a Digital India, in that sense we are all for empowerment, but you want to go from point one to point ten. You can miss one or two steps, but you cannot miss all the steps. Eighty per cent of women today in India don't have a bank account. The national optic fiber network which is a great idea, the targets have not been met. So, it is not about digital. You talk about the *kisan*, you talk about the Jawan. It has been a great monsoon, Sir, so, things have been better. You want a credit for that. Nobody today in the President's Address, mentioned a word about the global tailwinds, what was the 2014-15 international oil price and what is that price now. So, you have got that. Good. Then you talked about bringing the money back. Yesterday I heard that a new Bill is coming to tax the thing of good times and bringing back to the bad times. Then you tell me about Jawans. Sir, it is very good that Jawans can book their tickets on line, But also please see the videos of the Jawans who are getting food in some places which we would not even give to our pet animals at home. It is so bad, They are expressing themselves. Sir, I have two broad points to make before I conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many more minutes?

SHRI DEREK O' BRIEN: I will take five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, then.

SHRI DEREK O' BRIEN: Para 66, this Government calls it 'cooperative federalism', Mamata Banerjee and Trinamool Congress call it 'operative federalism' because just seeing 'cooperative federalism' will not be good enough. I want to share with you one example, Sir, of 'cooperative federalism' and the 'operative federalism'. 'Operative' means you can make it happen. We, from this side of the House to that side of the House made this GST happen. That was operative federalism at its best. What view the Congress Party had when they were in Government, what view the BJP had, that sometimes it happen where you sit depends on what stand you take. We have not sat this side or that side for a long time. The GST is a very, very good example. I think we all take pride in 'operative federalism'. Now let me give you one example of so-called 'cooperative federalism' because it is mentioned in Para 66 and I will take yesterday's example. This great grand design to merge the Rail Budget with the General Budget, three points on that, Sir, in doing this yesterday, the General Budget has been used to mask all the deficiencies in the Rail Budget. This is the first thing which has happened. What the Finance Minister did not tell you yesterday and what everybody in this country should know because we had the Rail Budget yesterday, but did the Finance Minister tell you that this is for the first time since 1978 that freight earnings have dropped? Challenge the figure. We have a few Railway Minister, including Mamata Di, who gave the Vision-2020 Document. I am glad that one or two points in that Railway Budget were taken from that Vision-2020 Document. But freight earnings are lower than last year. For the first time it happened, Sir, since 1968. Did the Finance Minister tell you or did this President's Address tell you that for the first time in 68 years, 67 years actually, it was borne by the railways? For the last one-and-a-half years it has been borne by the Centre as well the States making their contribution. I have no problem with my friends from Odisha. They want to contribute for projects. There were two railway line projects in Odisha. They have contributed. The Centre has contributed. Good. In Jharkhand, three projects are of ₹ 2,150 crores. Good. In Kerala, you are doing a suburban railway section. It is good. What happens to the other States? What happens to the debt stressed States? What happens to the States of the North-East? What happens to the States who do not have this kind of money? This is a real example of federalism. By conceptually merging the two, you are actually killing the entire transport link of this country. Then you tell us, from one end to another end, it will now be a joint transport network. We know that. We have been talking about it for the last twenty years. All this has been happening.

Sir, I have tried to keep in time. But, Sir, at the end of all this, there is a bigger message. It is time. All of us need to stand up, — whether we are doing it in Parliament

[Shri Derek O'Brien]

or not, — so many Opposition parties are doing it. There are some people outside who are doing it. The media needs to stand up. The corporate world needs to stand up and we appeal to the media, we appeal to the corporate world, we appeal to the right thinking people that if you do not stand up now, you will never stand up. Sir, I want to paraphrase in different words what somebody said more than a hundred years ago, a thought, because nobody wants to stand up against demonetisation and you are hearing what happened in the last two weeks in America when the corporate world is standing up. So, I end, Sir, with this thought and it is a very solemn thought. "First, they came for the Dalits and I did not speak out because I was not a Dalit. Then they came for the daily wage workers and I did not speak out because I was not a daily wage worker. Then they came for the Muslims and I did not speak out because I was not a Muslim. Then they came for the farmers and I did not speak out because I was not a farmer. Then they came for me and there was no one left to speak for me." Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri T. G. Venkatesh. He is absent. Shri Swapan Dasgupta.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the President's Address. For the past few hours, we have been hearing a lot of political exchange. I don't want to get into the *tu tu mein* mein of that and we have heard some very passionate speeches also. I think what is far more important is to look at it, from my perspective taking a little dispassionate view. In the President's Address, we have a plethora of schemes being mentioned. If the Economic Survey is to be believed, today, there are 950 Central Government schemes whose Budget takes up five per cent of the GDP. Now many of these schemes were framed by earlier Governments and many of these schemes are the handiwork of this Government. Let me say that all of them were probably well intentioned.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair.*]

They had a specific purpose in mind. The question which we have to ask ourselves at this stage is — and I am using the President's Address because the President attached a lot of importance to this scheme — to what extent, have we, as a State, acquired the capacity to be able to put well-intentioned schemes into operation? And, I think, this is an issue which does not affect the Centre alone, but it affects the States as well. And, it is really a shame that when people really contrast, how good a certain State has been doing in terms of women's empowerment, for example, which we just heard. It is always against the lapses of the Central Government. Likewise, a similar case can be made. The

Economic Survey pinpoints certain schemes, which have very well been executed. There have been schemes in Chhattisgarh, which have been wonderfully executed. There have been schemes in Tamil Nadu, which have been wonderfully executed. And, these are issues of which, I think, we need to take a pride. But let us take a look at the schemes which have faltered. And, if we were to add up the entire development Budgets of India since 1947 till now, I think, we would be correct in saying that the slogan of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' would not have remained just a slogan. It would have been a reality. So, the question is not merely of leakages, it is today the inability of the State to deliver. Now, we are having some bizarre situations. Can we blame it on the bureaucracy? My friend, Dr. Vinay Sahasrabudhe, was very right in saying that a lot of sterling work has been done in this Government by the very same *adhikaris*, who earlier may have been inefficient. And, I think, that is an important point. But, there are only a few people who actually carry a State. Unfortunately, there are many more laggards. And, that is true for any organization,- that is true for any bureaucracy. We have had a bizarre situation, a very bizarre situation, of Revenue Service officers actually protesting against the loss of their powers by the GST. An enactment of legislation, which has been passed unanimously by both the Houses of Parliament, is refused and there is non-cooperation from people whose job is to execute Government policies. I can understand; there may be certain sections of the State. May I say, the Judiciary, which believes that they should be making the laws? Now, if that disease was to spread to even the bureaucracy, and *babudom*, taking advantage of constitutional guarantees, were to say, "No, actually we make the laws." That would be a terrible situation. This is not to tar the entire bureaucracy with the same brush. There are people who have been helping, who have done sterling work during the demonetisation crisis. They have helped the ordinary people in their difficulties. But there have also been people, I think, Ghulam Nabi Azadji pointed it out, who allowed the backdoor to be opened and which actually undermine the equitable sufferings, which made it possible for some people that some people are suffering more than others. So, Sir, I think, in this entire President's Address, all I want to really say is, and I do not want to go on on this point, that if we have to make democracy much more rounded, one of the great achievements of this Government, I feel, is that they have added a new quotient to the entire equation of governance. And, for the first time, through the methods of direct transfer, through other imaginative uses of technology, etc., they have added the word 'efficiency' as a necessary obligation of governance. I think, this is an important step. It is a very creditable step. If we are to get out of the syndrome of being a permanently deprived, poor, under-developed, and helpless country, which we are not, if the achievements of India are to be on par with the achievements of Indians, then, I think

[Shri Swapan Dasgupta]

it is very, very important that the entire machinery of delivery has to be looked at far more rigorously. I was, therefore, a little taken aback when the entire mention of administrative reforms and administrative toning up was not a part of this. It is not necessarily a lapse, but it is something which seems to be done by stealth. I wish motivation alone could be the only way out of this. But, Sir, sometimes, we have also seen examples and I am glad of that. There have been certain actions taken against inefficient officers. Some IAS people have been sacked and an IPS officer has also been sacked. I am sure that they were really the rotten apples in the barrel. Likewise, there have been others who have done exemplary service. So, the question which really arises is, if this Government has to be really responsive, — and the word 'responsiveness' is very much a part of this; we have heard various examples of how this Government works but this is not to suggest that other Governments weren't responsive — I think it is very important that this basic feature has to be taken into account. I think demonetisation, which we have discussed at great length, was a very great audacious step forward. It was a step forward because it did what no one else was willing to do. It took the plunge. I think it calls for a certain strength of leadership to be able to do something when you realise what the formidable challenges are. Otherwise, you say, 'Oh my God, these challenges are too insurmountable. We can't go ahead.' Therefore, that is a very, very positive thing. But to carry that gain forward, it is not enough to just go by that and say, 'Oh, enough remonetisation of the economy.' Sir, if we have to make India ethical, if we have to take Swachh Bharat out of the physical thing and make it a part of our spirit, I think a lot of uncomfortable decisions will have to be taken, which, sometimes, may involve suffering. We can criticise the Government for its shortcomings and I think it is only legitimate that every one should, whenever a Government has done something wrong, or, there have been lapses. But to have a permanently negative attitude is something which is not proper. Here, I am reminded of — my friend, Mr. Jairam Ramesh, is here, has a greater experience of the United States — what a discredited American-Vice-President, Spiro Agnew, once said, 'the nattering nabobs of negativism', and I am, sometimes, reminded of that when I hear my friend, Mr. Derek O'Brien, whom I admire speaking. He mentioned that Ravi babu spoke 13 times about the Prime Minister. I can say that he managed, at least, half that feat, by managing six times. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Five times.

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Maybe five; I stand corrected. But he is getting there.

SHRI JAIRAM RAMESH: You have spoken about the Prime Minister four times.

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Thank you. My appreciation of the Prime Minister is a matter of record and it is not something which is very late.

SHRI JAIRAM RAMESH: We all know.

SHRI SWAPAN DASGUPTA: We all know that. I am very glad and it is not something which is late and it is not something which I need to apologise about. I think what we see today, Sir, is a Government, which is there with energy, with direction, with a sense of newness and with a sense of audacity. What it now requires to complement it is additional capacity to be able to deliver that. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Dasgupta. Now, Mr. D. Raja.

SHRI D. RAJA: Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, today, the country is passing through a very critical period. The President's Address and the Government's response do not actually address the challenges appropriately. Sir, I would not speak on Budget proposals. When I participate in the discussion on Budget, I will speak on those Budget proposals. I will confine to certain policy issues. I agree with the Leader of the Opposition and the issues which he raised. Sir, the democracy in the country is in unprecedented distress. That poses a grave challenge to the people and the progress of the nation. The situation in the country is very scary. Let us not take people for granted. People feel insecure. People, in general, feel insecure.

Sir, the whole question is, India as a nation, the parliamentary democracy which we have built up till now, are capable of fighting the pressures. The United States of America declared strategic partnership with India. One of the purposes of the strategic partnership is that China needs to be reined in. In the context of this partnership, the US Government's Development Agency, USAID, has negotiated cooperation agreements with the Indian Finance Ministry. One of the goals as declared is to push back the use of cash in favour of digital payments in India and globally. Sir, India and US have entered into many defence cooperation agreements. They have signed defence logistics agreements. This Parliament, we consider, is supreme. It represents the collective will of the people. I do not think the Government has taken this Parliament into confidence. In fact, my concern is, the Foreign Policy of the country is under pressure. It is being influenced by US, and India is becoming a subservient to American policies. India is willingly becoming a junior ally, a

[Shri D. Raja]

junior strategically of US. It compromises the independent foreign policy of the nation. India's Foreign Policy does not belong to one Party which is in power or which was in power or which can come to power. India's Foreign Policy is always one which evolves on the basis of consensus. India's Foreign Policy is on the basis of a national consensus. That national consensus is being broken by you, by this present Government. That is my charge. We can debate, keeping in view the interest of the country. I am speaking for the country. My country should pursue an independent sovereign foreign policy. It should not be influenced by any imperial power. But today, that is what is happening. This is a major concern. It is not just with the foreign policy; it is happening even with the domestic policies. That is exactly what I am talking about when I say demonetisation. In my opinion, demonetisation has not been announced in isolation. It has a context. The compromise on our sovereign policies, foreign and domestic, is a major concern. The President's Address notes that we have international engagements, etc., but what is the purpose? Does India play a proactive role in world affairs? What are we doing as far as the question of Palestine is concerned? Do we play a proactive role in the context of developments taking place in West Asia? Forget all those things, what proactive role are we playing in the context of Sri Lanka? The war got over in 2009. I have spoken about this many times in this House. Even today, the Sri Lankan Tamils have not got justice. War crimes have not been taken up as they should have been taken up. Even today, many thousands of Sri Lankan Tamils are declared to have disappeared. Women are living as half-widows. India, being the neighbour, should have taken up this issue. Why has India not taken up this issue? That is where there is a concern. India allows itself to be compromised on independent foreign policies. The President's Address does not speak about this issue. The Government's response on this issue is inappropriate.

Sir, coming to other issues, water disputes are growing in the country. I don't mean just Cauvery, but water disputes in general are growing. What is the policy of the Government on this? In the coming days, it is going to be a major challenge and it could pose a threat to the unity and integrity of the nation. Government should have a policy on this. Cooperative federalism and competitive federalism are mere words, but in reality, does the Government have the political will? That is what I would like to ask. Mr. Ravi Shankar Prasad and all the spokespersons for the BJP refer to this Government's concern for the youth. How do you look at our youth? Our youth is the future of our nation. The President refers to India as a country of young people. What is our responsibility towards our youth? What is our obligation to our youth? Today, the youth in our country live in hopelessness; they are living with joblessness. They are the future, but there is unrest

everywhere. It includes the students. The Government is discarding all colonial practices, but there is one small thing that I asked the Government to do, that is to do away with the sedition laws in this country. Why should our students be charged with sedition? Why should Jawaharlal Nehru University students be charged with sedition? What happened to Rohit Vemula at the Hyderabad Central University? It was an institutional murder. The young people are demanding a legislation to stop such discrimination and to stop these institutional murders. Do we have the political will to do that? What is happening today? If you question the Prime Minister, if you say something against the Prime Minister, you are being dubbed as anti-national. Questioning the Prime Minister is anti-national! Who taught you this politics? Who taught you this democracy? Now, you are taking the name of Dr. Ambedkar. I tell you what Dr. Ambedkar said. He said, "In politics, *bhakti* or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship." Do you want dictatorship in this country or a fascist dictatorial regime in this country? How can you dub people questioning the Government or the Prime Minister anti-national? How can you say that criticising the Government is anti-national and unpatriotic? What is this happening in this country? That is why I am saying that this poses a challenge to the Republic and its Constitution. Mr. Derek O'Brien also spoke about *dalits* and *adivasis*. Sir, with agony, I am telling you how our tribal people are treated in this country. There is an undeclared war on the tribal people in this country. Why should there be massacre? President's Address doesn't speak about the increasing atrocities on dalits. Everyone wants to shed crocodile's tears for *dalits*. But what is happening on the ground? What is this Government doing to stop atrocities against dalits? And you say that in Scheduled Caste Sub-Plan you are increasing the money; in Tribal Sub-Plan you are increasing the money! But you have replaced the Planning Commission with NITI Aayog. The Planning Commission has given the directive that Sub-Plans should be according to the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Where is the Planning Commission? NITI Aayog says, "Go towards privatization; reckless disinvestment of Public Sector Undertakings." RSS and other organizations will come out and say, "Review the reservation policy." We don't mind and review the national wealth policy also. Who creates national wealth in this country, if not *dalits* and *adivasis*, workers, farmers and agricultural workers? What is their share in the national wealth? I would like to ask the Government and all political parties. Touch your conscience and tell the people of this country what is the share of *dalits*, *adivasis*, workers, farmers and agricultural workers in the national wealth which they create. Now you are talking about Sub-Plans and that you are increasing the amount. Is it not just to hoodwink people? Will it work in this country? And you talk about women. My colleague also raised that issue. Where is the reservation for women? How many times we used to

[Shri D. Raja]

6.00 P.M.

ask for reservation? It is not the question of only reservation and that from 33 per cent they should come to Parliament and State Assemblies. What is the social security to our women? Women should have gender equality; women should have gender justice. And as a nation, are we standing up for women? This is what we should think up. And the same thing is with children. So, Sir, the situation is very challenging and the President's Address really does not address the challenges. In fact, inequalities and disparities are on the rise. I would like to remind you what Mr. K.R. Narayanan said. He was the Vice-President; he was the President; he was the Chairman of this House. When Mr. K.R. Narayanan was the President of India, in one of his Republic Day's speeches, he cautioned that if on our highway of privatization and globalization, safe pedestrian passages are not provided for the unemployed and un-empowered, then the long-suffering and silent people would exhibit anger which would be explosive for the system to withstand. Sir, exactly the same caution was given by Dr. Ambedkar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. D. Raja, one minute. It is 6 o'clock. If the House so wishes, we can extend the time.

SOME HON. MEMBERS: No, Sir. We can continue it tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Then, we will give Mr. Raja two more minutes. Within two minutes, he will conclude and then we can adjourn the House.

SHRI D. RAJA: Sir, exactly the same caution was given by Dr. Ambedkar in his last speech in the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar was a great genius and very prophetic. He said it on the 26th of January, 1950, and we all must have read that speech. But, what I am trying to say is that the same thing was stated by Dr. Ambedkar, "How long will we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment; or else, those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has laboriously built up." But now, what is happening? Those, who suffer from inequalities and disparities, are not blowing up the structures of political democracy, but those, who want to perpetuate the inequalities and disparities, are blowing up the structures of political democracy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

SHRI D. RAJA: Sir, I am concluding. Sir, that poses a great threat to secularism, to democracy, and India is not a theocracy. The President's Address should have referred to what is happening in our country. The Right-Wing Fundamentalist forces are instigating people against each other and they are really posing a threat to our democracy. There is no place for theocracy in our country, but in the name of Hindutva, or in the name of other 'isms', the religious fundamentalists and communal fascists are posing a threat to the secular fabric of our country and the secular fabric of our Constitution. All these questions need to be addressed. Otherwise, India cannot move forward. We all want our nation to move forward. India should move forward. India should become a prosperous country, a modern country, a modern Republic, and it should emerge as a great inspiring modern Republic in the world, but the Republic is challenged, the Constitution is challenged by reactionary forces, by communal forces. This needs to be understood and this House should stand to save this country. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Raja. The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Friday, the 3rd February, 2017.

*The House then adjourned at three minutes past
six of the clock till eleven of the clock on
Friday, the 3rd February, 2017.*